

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2007-08 में सुदृढ़ कार्य-निष्पादन दिखाना जारी रखा, हालांकि 2006-07 से वृद्धि की गति मंद हो गई। मंदी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन पिछले चार वर्षों की औसत वृद्धि के अनुरूप थी। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि भी 2006-07 की तुलना में 2007-08 में निम्नतर थी। विनिर्माण क्षेत्र की मंद वृद्धि, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के चार बटे पांच भाग से अधिक है, ने प्राथमिक तौर पर औद्योगिक वृद्धि की मंदी में अंशदान किया। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र ने दुहरे अंकों की वृद्धि का रिकॉर्ड बनाए रखा, जिसे प्राथमिक तौर पर दूरसंचार, साफ्टवेयर निर्यात और आइटी-समर्थित सेवाओं में हुई उच्च वृद्धि से मदद मिली। 2007 में, दक्षिण-पश्चिम मानसून औसत से अधिक था। इसके तथा जल संग्रहण स्तरों में सुधार के फलस्वरूप 2007-08 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।

2.2 थोक मूल्य सूचकांक (थोमूसू) में साल-दर-साल घटबढ़ पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति ने 2007-08 की पहली दो तिमाहियों में निरंतर गिरावट दर्शायी। तथापि, दिसंबर 2007 से प्राथमिक खाद्येतर वस्तुओं एवं खाद्य तेल/ खली और धातुओं जैसे विनिर्मित मदों की कीमतें बढ़ने के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगी। साल-दर-साल उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में, जिसमें जनवरी 2008 तक नरमी आयी थी, बाद के महीनों में तेजी आ गयी।

2.3 खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि की अगुआई में 2007-08 में वैश्विक पण्य मूल्यों में तेजी आई। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेज के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई, जो सख्त आपूर्ति-मांग संतुलन, भूराजनैतिक तनाव, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के कमजोर होने तथा निवेशकों एवं वित्तीय बाजार के खिलाड़ियों के बाजार कार्यकलापों में वृद्धि को दर्शाता है। 2007-08 में, विशेष तौर पर दूसरी छमाही में, मांग (उपभोग मांग तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे खाद्येतर उपयोगों की मांग दोनों) में वृद्धि, प्रमुख फसलों के कम स्टॉक, एवं कुछ प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब होने के कारण गेहूँ, चावल, और तिलहन/ खाद्य तेल की अगुआई में खाद्य मूल्यों में भी तेजी आई। खाद्य मदों पर वैश्विक मांग एवं आपूर्ति संबंधी दबावों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने गेहूँ और खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम कर दिया तथा उसके बाद गैर बासमती चावल और दाल जैसे कुछ पण्यों पर निर्यात पर पाबंदी लगा दी तथा चुनिंदा उत्पादों पर स्टॉक सीमा संबंधी प्रशासनिक उपाय किए गए। रिजर्व बैंक ने सीआरआर में वृद्धि के रूप में मौद्रिक

उपाय भी किए। 2007-08 में सीआरआर में चार चरणों में 150 आधार अंकों की वृद्धि की गई। तथापि, 2008-09 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति बढ़ी। इसके प्रतिसाद में, रिजर्व बैंक ने अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान सीआरआर में छः चरणों में 150 आधार अंकों की तथा रिपो दर में तीन चरणों में 125 आधार अंकों की वृद्धि की।

2.4 भारतीय वित्तीय बाजार 2007-08 में, इक्विटी बाजार को छोड़कर जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप अस्थिरता के कुछ दौर देखे गए, काफी सीमा तक व्यवस्थित रहे। सरकार के नकदी शेषों और पूंजी प्रवाहों में होने वाले दोलन वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों के मुख्य वाहक थे। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकृत खंड में जो वर्तमान में मुद्रा बाजार की कुल मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत है, ब्याज की दरें वर्ष के दौरान मांग दर के अनुरूप परंतु उससे नीचे रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपए में आम तौर पर दुतरफा गतिविधि देखी गई। वर्ष के प्रमुख हिस्से में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिफल में नरमी आई।

2.5 2006-07 में मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता में सुधार आया। बैंक ऋण सुदृढ़, हालांकि कुछ कम, दर पर बढ़ता रहा। वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार आया।

2.6 केंद्र और राज्य सरकार के वित्त में और समेकन हुआ; 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के मुख्य घाटा संकेतकों के संशोधित अनुमान उनके बजट स्तरों से कम रखे गए। अनंतिम खातों में मुख्य घाटा संकेतकों में और गिरावट आ गई। राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) के तहत राजकोषीय सुधार और समेकन के प्रति वचनबद्धता दर्शाना जारी रखा।

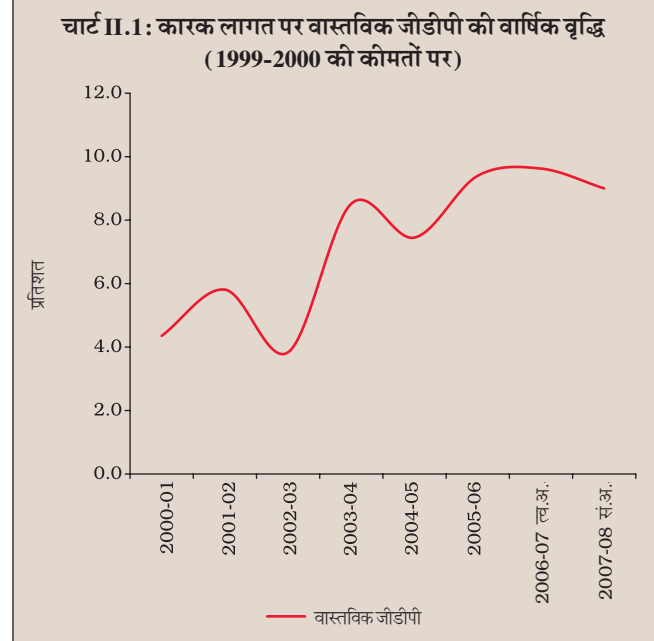
2.7 2007-08 के दौरान बाह्य क्षेत्र का प्रभावी कार्यनिष्पादन जारी रहा। माल और सेवाओं के निर्यात में 2007-08 में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, आयातों, विशेष तौर पर तेल से इतर आयातों, में काफी अधिक वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया। उच्चतर निजी विप्रेषणों तथा साफ्टवेयर सेवा निर्यातों की अगुआई में अदृश्य मदों के खातों में मौजूद अधिशेष के कारण चालू खाते पर व्यापार घाटा बढ़ने के प्रभाव को नियंत्रित किया गया। देश में निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था, जिसके फलस्वरूप समग्र भुगतान शेष में अधिशेष की स्थिति रही।

2.8 इस अध्याय में 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान (उस अवधि तक जिसके लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) समष्टि आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरेवार लेखा प्रस्तुत किया गया है। जहां खंड II में वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं, खंड III में केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्त का ब्यौरेवार लेखा दिया गया है। खंड IV में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के साथ मौद्रिक एवं ऋण संबंधी गतिविधियां दी गई हैं। खंड V में वित्तीय बाजारों की प्रमुख गतिविधियां दी गई हैं। 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के व्यावसायिक परिचालन खंड VI में शामिल किए गए हैं। खंड VII में बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां दी गई हैं। समग्र मूल्यांकन खंड VIII में प्रस्तुत किया गया है।

II. वास्तविक क्षेत्र

राष्ट्रीय आय

2.9 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा 30 मई 2008 को जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2006-07 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कमी के बावजूद, 2007-08 में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि पिछले चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) के 8.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक थी (चार्ट II.1)।



2.10 वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 2007-08 में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र नामक दो प्रमुख क्षेत्रों में मंदी के कारण कमी आई (सारणी 2.1 तथा सारणी 2.2)। जीडीपी में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा पिछले साल के

सारणी 2.1 : वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर
(आधार : 1999-2000)

क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08#
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कृषि एवं संबंधित कार्य	-0.2	6.3	-7.2	10.0	0.0	5.9	3.8	4.5
क) कृषि	-0.6	6.5	-8.1	10.8	0.0	6.1	3.8	..
II. उद्योग	6.4	2.4	6.8	6.0	8.5	8.0	10.6	8.1
क) खनन एवं उत्खनन	2.4	1.8	8.8	3.1	8.2	4.9	5.7	4.7
ख) विनिर्माण	7.7	2.5	6.8	6.6	8.7	9.0	12.0	8.8
ग) बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	2.1	1.7	4.7	4.8	7.9	4.7	6.0	6.3
III. सेवाएं	5.7	6.9	7.5	8.8	9.9	11.0	11.2	10.7
क) निर्माण	6.2	4.0	7.9	12.0	16.1	16.5	12.0	9.8
ख) व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	5.2	9.6	6.9	10.1	7.7	9.4	8.5	12.0^
ग) परिवहन, भंडारण और संचार	11.2	8.4	14.1	15.3	15.6	14.6	16.6	..
घ) वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं	4.1	7.3	8.0	5.6	8.7	11.4	13.9	11.8
ड) सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	4.7	4.1	3.9	5.4	6.9	7.2	6.9	7.3
IV. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	9.4	9.6	9.0
Sectoral Composition								
कृषि एवं संबंधित कार्य	23.9	24.0	21.4	21.7	20.2	19.6	18.5	17.8
उद्योग	20.0	19.3	19.9	19.4	19.6	19.4	19.5	19.4
सेवाएं	56.1	56.7	58.7	58.9	60.2	61.1	61.9	62.9
कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>जापन</i>								
वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद (करोड़ रुपये)	18,64,300	19,72,606	20,48,287	22,22,758	23,88,384	26,12,847	28,64,310	31,22,862
* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान .. : उपलब्ध नहीं								
^ : 'परिवहन, भंडारण एवं संचार' के साथ आंकड़ों को जोड़ा गया है।								
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन								

सारणी 2.2: सकल देशी उत्पाद की वार्षिक एवं तिमाही वृद्धि दरें

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2000-01 से 2007-08 (औसत)	2005-06	2006-07*	2007-08#	2006-07				2007-08			
					ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कृषि एवं संबंधित कार्य	2.9	5.9	3.8	4.5	2.7	3.2	4.0	4.9	4.4	4.7	6.0	2.9
		(19.6)	(18.5)	(17.8)								
1.1 कृषि	..	6.1	3.8
2. उद्योग	7.1	8.0	10.6	8.1	10.0	10.7	10.3	11.5	9.6	8.6	8.6	5.8
		(19.4)	(19.5)	(19.4)								
2.1 खनन एवं उत्खनन	4.9	4.9	5.7	4.7	4.1	3.9	6.0	8.2	1.7	5.5	5.7	5.9
2.2 विनिर्माण	7.8	9.0	12.0	8.8	11.7	12.2	11.3	12.8	10.9	9.2	9.6	5.8
2.3 बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	4.8	4.7	6.0	6.3	4.3	6.6	7.6	5.4	7.9	6.9	4.8	5.6
3. सेवाएं	9.0	11.0	11.2	10.7	11.7	11.6	11.1	10.5	10.6	10.7	10.0	11.4
		(61.1)	(61.9)	(62.9)								
3.1 व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भंडारण एवं संचार	10.3	11.5	11.8	12.0	10.9	12.7	12.1	11.6	13.1	11.0	11.5	12.4
3.2 वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं	8.8	11.4	13.9	11.8	13.6	13.9	14.7	13.4	12.6	12.4	11.9	10.5
3.3 सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	5.8	7.2	6.9	7.3	10.3	7.2	5.6	5.1	5.2	7.7	6.2	9.5
3.4 विनिर्माण	10.6	16.5	12.0	9.8	13.1	12.0	10.8	12.2	7.7	11.8	7.1	12.6
4. कारक लागत पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद	7.3	9.4	9.6	9.0	9.6	10.1	9.3	9.7	9.2	9.3	8.8	8.8
		(100)	(100)	(100)								

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान .. : उपलब्ध नहीं
 टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद में हिस्सेदारी का प्रतिशत हैं।
 स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

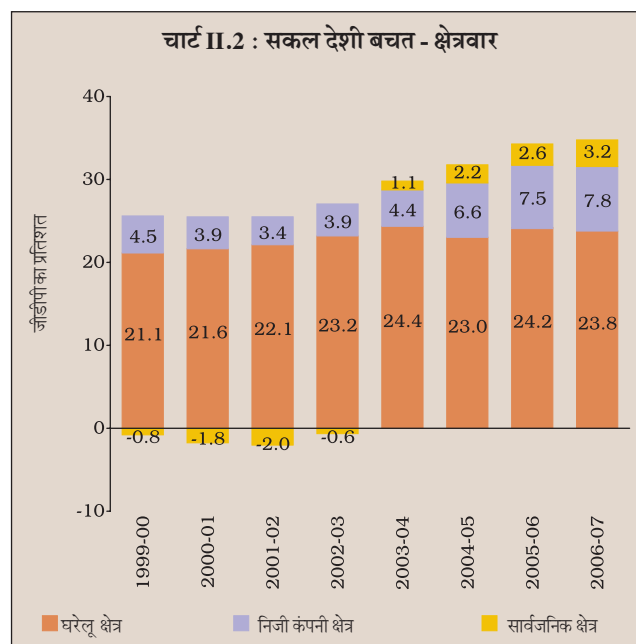
18.5 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 17.8 प्रतिशत रह गया। सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कुछ गिर गया।

बचत और निवेश

2.11 चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत (जीडीएस) की दर 2005-06 के 34.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत हो गई। निजी कंपनी बचत दर लगातार पांचवें साल 2001-02 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में जीडीपी का 7.8 प्रतिशत हो गई, जो कंपनी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाता है जिससे प्रतिधारित आय में वृद्धि होती है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत 2001-02 के 22.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 23.8 प्रतिशत हो गई। सरकारी क्षेत्र की बचत, जिसमें 2003-04 में टर्नअराउंड आया, में सुधार जारी रहा जो अधिकांशतः गैर विभागीय और विभागीय उद्यमों की उच्चतर बचत को दर्शाता है (चार्ट II.2 तथा सारणी 2.3)।

2.12 पहले की तरह थोक निवेश का वित्तपोषण देशी बचत द्वारा किया गया। सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) की दर 2005-06 के 35.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 35.9 प्रतिशत पर उच्चतर

होने का अनुमान था (सारणी 2.3 तथा चार्ट II.3)। निवेश संबंधी कार्यकलाप निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा चालित होना जारी रहा, जिसकी दर 2001-02 में जीडीपी के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में जीडीपी



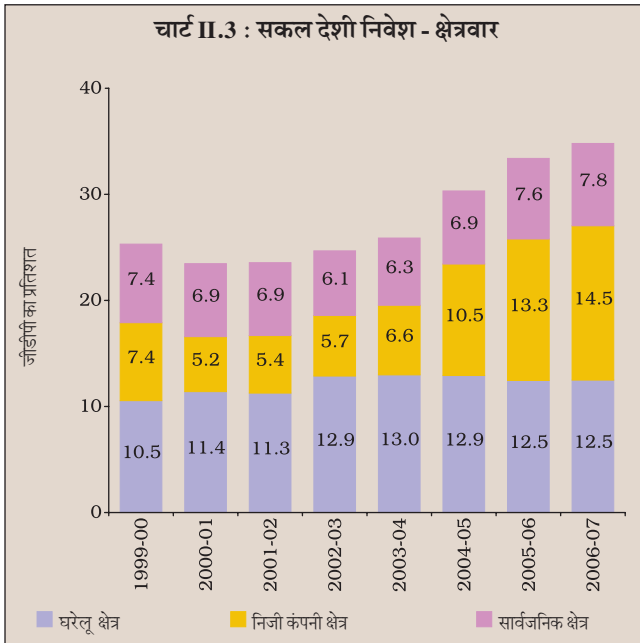
सारणी 2.3: सकल देशी बचत एवं निवेश की दर

(वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (त्व अ)	2006-07 10 वीं योजना (अ अ)	वीं योजना (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 सकल देशी बचत	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	31.4
i) घरेलू क्षेत्र	22.1	23.2	24.4	23.0	24.2	23.8	23.7
क) वित्तीय बचत	10.9	10.3	11.4	10.1	11.8	11.3	11.0
ख) भौतिक बचत	11.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.5	12.7
ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र	3.4	3.9	4.4	6.6	7.5	7.8	6.0
iii) सार्वजनिक क्षेत्र	-2.0	-0.6	1.1	2.2	2.6	3.2	1.7
2 सकल पूंजी निर्माण	24.2	25.2	26.8	31.6	34.5	36.0	30.8
i) घरेलू क्षेत्र	11.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.5	12.8
ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र	5.4	5.7	6.6	10.5	13.3	14.5	10.1
iii) सार्वजनिक क्षेत्र	6.9	6.1	6.3	6.9	7.6	7.8	6.9
iv) मूल्यवान वस्तुएं	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2	1.2	1.0
3 सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#	22.8	25.2	28.2	32.2	35.5	35.9	31.4
4 बचत निवेश शेष	0.7	1.2	1.6	-0.4	-1.2	-1.1	0.0
i) घरेलू क्षेत्र	10.9	10.3	11.4	10.1	11.8	11.3	10.9
ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र	-2.1	-1.9	-2.2	-4.0	-5.8	-6.8	-4.1
iii) सार्वजनिक क्षेत्र	-8.9	-6.7	-5.3	-4.7	-5.0	-4.5	-5.3

अ अ : अनंतिम अनुमान त्वअ : त्वरित अनुमान #: भूल चूक के लिए समायोजित।
 स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

का 14.5 प्रतिशत हो गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बचत और निवेश में से प्रत्येक की औसत दरें 31.4 प्रतिशत वार्षिक थीं। योजना अवधि के पहले दो वर्षों में बचत-निवेश का सकारात्मक शेष योजना अवधि के अगले तीन वर्षों में बचत-निवेश के ऋणात्मक शेष द्वारा प्रतितुलित हो गया।



कृषि

2.13 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि जनसंख्या का बड़ा भाग इस पर निर्भर है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 में अनाज का कुल उत्पादन 230.7 मिलियन टन (सभी समय का रिकार्ड) होने का अनुमान था, जो पिछले वर्ष (217.3 मिलियन टन) की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, सीएसओ के संशोधित अनुमानों में 2006-07 के 3.8 प्रतिशत की तुलना में कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में 2007-08 में 4.5 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि का अनुमान था।

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007

2.14 वर्ष 2007 में दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में सामान्य तारीख से चार दिन पहले 28 मई को आ गया। पूर्वी-मध्यवर्ती अरब सागर में “गोनू” नामक सुपर चक्रवात के निर्माण के कारण मानसून आने में जून की शुरुआत में हुई विवृत्ति (हाइएटस) के संक्षिप्त दौर के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जुलाई तक, सामान्य अनुसूची से लगभग 11 दिन पहले, पूरे देश पर छा गया। 29 जून 2007 को भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) द्वारा जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बरसात को +/- 4 प्रतिशत के मॉडल चूक के साथ दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 93 प्रतिशत पर रखा

सारणी 2.4 : संचयी वर्षा

श्रेणी	उप खंडों की संख्या						
	दक्षिण-पश्चिम मानसून				उत्तर-पूर्वी मानसून		
	2005	2006	2007	2008*	2005	2006	2007
	(1 जून से 30 सितंबर)				(1 अक्टूबर से 31 दिसंबर)		
1	2	3	4	5	6	7	8
अधिक	9	6	13	10	11	3	2
सामान्य	23	20	17	22	6	6	7
कम	4	10	6	4	5	14	9
अल्प वर्षा / वर्षा नहीं	0	0	0	0	14	13	18

* : 1 जून से 13 अगस्त तक
स्रोत: भारतीय मौसम विभाग

गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वास्तविक वर्षा एलपीए का 105 प्रतिशत थी जो आइएमडी के पूर्वानुमान की तुलना में बेहतर थी। 36 मौसम उपखण्डों में से, 30 उपखण्डों में (पिछले साल 26 उपखण्डों में) संचयी वर्षा अधिक/सामान्य थी तथा 6 उपखण्डों में (पिछले साल 10 उपखण्डों में) वर्षा कम/अल्प/नहीं के बराबर थी (सारणी 2.4 तथा चार्ट II.4अ)।

2.15 चार व्यापक समरूप क्षेत्रों¹ में, जहां उत्तर-पश्चिम भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बरसात सामान्य से कम (एलपीए का 85 प्रतिशत) थी, वहीं यह दक्षिण प्रायद्वीप (एलपीए का 126 प्रतिशत), मध्य भारत (एलपीए का 108 प्रतिशत) तथा उत्तर-पूर्व भारत (एलपीए का 104 प्रतिशत) में सामान्य से अधिक थी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के

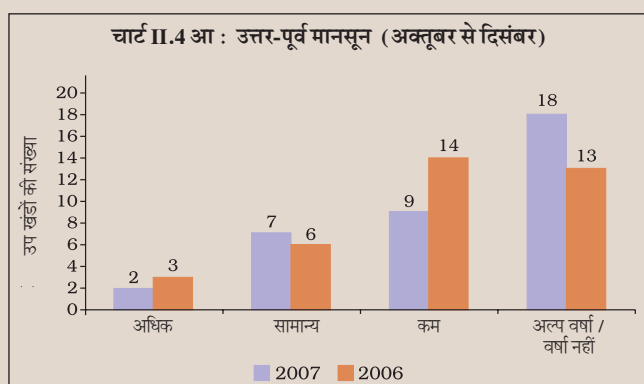
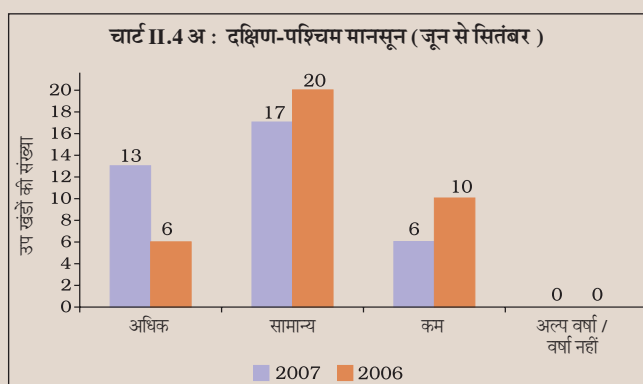
सामान्य कार्यनिष्पादन तथा जलसंग्रहण स्तरों में सुधार को देखते हुए, कृषि मंत्रालय ने 2007-08 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 221.5 मिलियन टन के लगभग लक्ष्य निर्धारित किया, जो पिछले साल के 220 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में थोड़ा अधिक था (सारणी 2.5)।

2.16 मौसम के अंत में पांच उपखण्डों (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश) में थोड़ी सूखे की स्थिति (26 से 50 प्रतिशत वर्षा की कमी) रही। मौसम के प्रारंभ में मानसून की गतिविधि मंद रही। जून के पहले सप्ताह, जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह तथा अगस्त के तीसरे सप्ताह में वर्षा में अत्यधिक कमी देखी गयी। शेष मौसम के दौरान वर्षा कालावधि में सुवितरित थी। कुल मिलाकर देश भर में संचयी वर्षा जून के अंतिम सप्ताह के आरंभ में हमेशा सामान्य से अधिक रही। माहवार वितरण से यह पता चलता है कि वर्षा जून (19 प्रतिशत) तथा सितंबर में (18 प्रतिशत) सामान्य से अधिक रही, जबकि जुलाई (3 प्रतिशत) तथा अगस्त (1 प्रतिशत) में यह सामान्य से सिर्फ थोड़ी कम रही।

जलाशय की स्थिति

2.17 81 प्रमुख जलाशयों, जिनकी क्षमता देश की कुल जलाशय क्षमता का लगभग 72 प्रतिशत है, में पानी का स्टॉक दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के अंत में (27 सितंबर 2007) पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) का 79 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 87 प्रतिशत से कम था परंतु पिछले दस वर्षों के 67 प्रतिशत के औसत से अधिक था।

चार्ट II.4 : संचयी वर्षा



1 चार व्यापक समरूप क्षेत्र इस प्रकार हैं : 1) उत्तर-पश्चिम भारत (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर); 2) मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और गोवा); 3) दक्षिण प्रायद्वीप (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह); और 4) उत्तर-पूर्व भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा)।

सारणी 2.5 : फसलवार लक्ष्य/उपलब्धियां

(मिलियन टन)

फसल	2005-06		2006-07		2007-08	
	ल	उ	ल	उ	ल	अ.अनु#
1	2	3	4	5	6	7
चावल	87.8	91.8	92.8	39.4	93.0	96.4
गेहूं	75.5	69.4	75.5	75.8	75.5	78.4
मोटे अनाज	36.5	34.1	36.5	33.9	37.5	40.7
दालें	15.2	13.4	15.2	14.2	15.5	15.1
कुल खाद्यान्न	215.0	208.6	220.0	217.3	221.5	230.7
तिलहन	26.6	28.0	29.4	24.3	30.0	28.8
गन्ना	237.5	281.2	270.0	355.5	310.0	340.6
कपास*	16.5	18.5	18.5	22.6	22.0	25.8
जूट एवं मेस्ता**	11.3	10.8	11.3	11.3	11.0	11.2
ल : लक्ष्य	उ: उपलब्धि					
# : चौथा अग्रिम अनुमान						
अ.अनु: अग्रिम अनुमान						
* : मिलियन गड्डों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा. का						
** : मिलियन गड्डों में प्रत्येक 180 कि.ग्रा. का						
स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार						

उत्तर-पूर्व मानसून 2007

2.18 उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान वर्षा तमिलनाडु तथा दक्षिण प्रायद्वीप के निकटवर्ती राज्यों में 22 अक्टूबर 2007 को आरंभ हुई। उत्तर-पूर्व मानसून (1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2007 तक) की प्रगति कम थी तथा इस दौरान पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई सामान्य से 21 प्रतिशत कम वर्षा की तुलना में सामान्य से 32 प्रतिशत कम संचयी वर्षा हुई। 36 मौसम उपखण्डों में से, 9 उपखण्डों में (पिछले वर्ष के अनुरूप) संचयी वर्षा अधिक/सामान्य थी तथा 27 उपखण्डों में (पिछले वर्ष के अनुरूप) वर्षा कम/अल्प/नहीं के बराबर थी (चार्ट II.4आ)। मौसम के अंत में 3 जनवरी 2008 को कुछ जलाशय संग्रहण एफआरएल का 61 प्रतिशत था (पिछले वर्ष के दौरान 65 प्रतिशत तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान औसतन 51 प्रतिशत)।

खरीफ 2007

2.19 चौथे अग्रिम अनुमानों में 2007-08 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 230.7 मिलियन टन के सर्वाधिक स्तर पर रखा गया जो पिछले वर्ष (217.3 मिलियन टन) की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन 121.0 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष (110.6 मिलियन टन) की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था। खाद्यान्नों में से, जहां खरीफ चावल के उत्पादन (3.3 प्रतिशत) में थोड़ी वृद्धि हुई, वहीं मोटे अनाजों (23.8 प्रतिशत) तथा दालों (34.4 प्रतिशत) के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। साथ ही, पिछले साल की तुलना में खरीफ तिलहन के उत्पादन में 41.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि देखी गयी।

रबी 2007-08

2.20 2007-08 के लिए रबी खाद्यान्न उत्पादन 109.7 मिलियन टन था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जहां दालों के उत्पादन में कमी (7.9 प्रतिशत) देखी गयी, वहीं गेहूं (3.4 प्रतिशत), मोटे अनाज (8.7 प्रतिशत) तथा चावल (3.3 प्रतिशत) जैसे फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गयी। रबी तिलहनों के उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की गिरावट आयी।

2.21 कुल मिलाकर, मुख्यतया खरीफ मौसम के उत्पादन के सुदृढ़ कार्यानिष्पादन की अगुवाई में 2007-08 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 2007-08 में खाद्यान्नों में से दालों का कुल उत्पादन 15.1 मिलियन टन (2006-07 में 14.2 मिलियन टन), चावल का उत्पादन 96.4 मिलियन टन (93.4 मिलियन टन) तथा मोटे अनाजों का उत्पादन 40.7 मिलियन टन (33.9 मिलियन टन) होने का अनुमान था (सारणी 2.6)।

सारणी 2.6 : मौसमवार कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसलें	खरीफ			रबी		
	2005-06	2006-07	2007-08 अ.अनु	2005-06	2006-07	2007-08 अ.अनु
1	2	3	4	5	6	7
चावल	78.3	80.2	82.8	13.5	13.2	13.6
गेहूं	-	-	-	69.4	75.8	78.4
मोटे अनाज	26.7	25.6	31.7	7.3	8.3	9.0
दालें	4.9	4.8	6.5	8.5	9.4	8.7
कुल खाद्यान्न	109.9	110.6	121.0	98.7	106.7	109.7
तिलहन	16.8	14.0	19.8	11.2	10.3	9.0
गन्ना	281.2	355.5	340.6	-	-	-
कपास*	18.5	22.6	25.8	-	-	-
जूट एवं मेस्ता**	10.8	11.3	11.2	-	-	-

-: लागू नहीं अ.अनु: 9 जुलाई 2008 की स्थिति के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान (2007-08)

*: मिलियन गड्डों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा. का **: मिलियन गड्डों में प्रत्येक 180 कि.ग्रा. का

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

11.1 मिलियन टन की तुलना में 22.6 मिलियन टन पर उच्चतर होना था। 2008-09 में (1 अप्रैल से 31 मई 2008 तक) 5.9 मिलियन टन पर चावल और गेहूं का कुल उठाव पिछले साल की तदनु रूप अवधि की तुलना में सीमांत रूप में 0.1 प्रतिशत उच्चतर था। जहां कल्याण योजना के तहत उठाव में लगभग 55.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आयी, वहीं यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत उठाव में हुई लगभग 4.6 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा प्रतितुलित हो गयी। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 1 जून 2008 को 36.4 मिलियन टन था जो पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 25.9 मिलियन टन की तुलना में 40.3 प्रतिशत अधिक था। इसका मुख्य कारण 1 जून 2007 के 13.3 मिलियन टन से बढ़कर गेहूं का स्टॉक 1 जून 2008 को 24.1 मिलियन टन हो जाना था।

उद्योग

2.25 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में वृद्धि 2006-07 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में कम होकर 8.5 प्रतिशत रह गयी। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में कमी मोटे तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के मंद कार्यानिष्पादन के कारण थी, जिसका आइआइपी की वृद्धि में अंशदान लगभग 90 प्रतिशत था (आइआइपी में 79.36 प्रतिशत का भारांक) (सारणी 2.8)। खनन और बिजली क्षेत्रों की वृद्धि में कुछ कमी आयी। ताप और जल विद्युत निर्माण में मंद वृद्धि के फलस्वरूप बिजली क्षेत्र में कम वृद्धि हुई।

2.26 2007-08 में, छः विनिर्माण उद्योग समूह (2-अंक स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार) में त्वरित वृद्धि हुई, जबकि ग्यारह में कमी अथवा ऋणात्मक वृद्धि देखी गयी (सारणी 2.9)।

2.27 आइआइपी में लगभग 5.9 प्रतिशत भारांक वाले तीन उद्योगों अर्थात् 'लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद', 'अन्य विनिर्माण उद्योग' तथा 'जूट और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र' में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी तथा 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में इनका अंशदान 14.3 प्रतिशत था। 'जूट और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र' में टर्नअराउंड आया, जबकि इसी अवधि में 'धातु उत्पाद और पुर्जे' में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। आइआइपी में अपेक्षाकृत उच्चतर भारांक वाले उद्योग समूहों अर्थात् 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' (पेट्रोलियन और कोयला उत्पादों को छोड़कर), 'मशीनरी और उपस्कर' तथा 'मूल धातु और मिश्र धातु' में 2007-08 के दौरान 10-15 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि दर्ज की गयी।

2.28 उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 2007-08 में सभी प्रमुख समूहों में गिरावट आयी (सारणी 2.10)। निट्रोजिनस तथा फास्फेटिक उर्वरक खण्डों दोनों तथा कार्बन स्टील, स्टील वायर, कॉइल और एच.आर.शीट के उत्पादन में गिरावट के कारण मूल वस्तु क्षेत्र में न्यूनतर वृद्धि हुई। कुछ रासायनिक रंगों, टिन के धातु कंटेनरों, बाल और रोलर बीयरिंग, नप्था, पॉलिश किये गये ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र में कमी आयी।

सारणी 2.8 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - मासिक वृद्धि

(प्रतिशत)

माह	साधारण		विद्युत		खनन एवं उत्खनन		विनिर्माण	
	(100)		(10.17)		(10.47)		(79.36)	
	2006-07	2007-08#	2006-07	2007-08#	2006-07	2007-08#	2006-07	2007-08#
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	9.9	11.3	5.9	8.7	3.4	2.6	11.0	12.4
मई	11.7	10.6	5.0	9.4	2.9	3.8	13.3	11.3
जून	9.7	8.9	4.9	6.8	4.7	1.5	10.7	9.7
जुलाई	13.2	8.3	8.9	7.5	5.1	3.2	14.3	8.8
अगस्त	10.3	10.9	4.1	9.2	-1.7	14.7	11.9	10.7
सितंबर	12.0	7.0	11.3	4.5	4.3	4.9	12.7	7.4
अक्टूबर	4.5	12.2	9.7	4.2	5.9	5.1	3.8	13.8
नवंबर	15.8	4.9	8.7	5.8	8.8	6.3	17.2	4.7
दिसंबर	13.4	8.0	9.1	3.8	6.1	5.0	14.5	8.6
जनवरी	11.6	6.2	8.3	3.7	7.7	2.9	12.3	6.7
फरवरी	11.0	9.5	3.3	9.8	7.5	7.9	12.0	9.6
मार्च	14.8	5.5	7.9	3.7	8.0	4.9	16.0	5.7
अप्रैल-मार्च	11.5	8.5	7.3	6.3	5.3	5.1	12.5	9.0

: अर्न्तम

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार दर्शाते हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

सारणी 2.9 : विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि (2 अंक स्तरीय वर्गीकरण)

(2007-08)			
15 प्रतिशत से अधिक	10-15 प्रतिशत	0-10 प्रतिशत	ऋणात्मक
1	2	3	4
1. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर एवं फिक्सचर (40.5) (29.7)	1. मूल धातु एवं मिश्र धातु (12.1) (22.8)	1. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयले के उत्पाद (8.9) (12.9)	1. धातु के उत्पाद एवं पुर्जे (-5.6) (11.4)
2. जूट एवं अन्य वनस्पति रेशों के वस्त्र (33.0) (-15.8)	2. पेय, तम्बाकू एवं संबंधित उत्पाद (12.0) (11.1)	2. खाद्य उत्पाद (7.0) (8.5)	
3. अन्य विनिर्माण उद्योग (19.8) (7.7)	3. चमड़ा एवं चमड़ा और फर उत्पाद (11.7) (0.6)	3. गैर धातु खनिज उत्पाद (5.7) (12.8)	
	4. पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पादों को छोड़कर रसायन एवं रासायनिक उत्पाद (10.6) (9.6)	4. ऊन, रेशम एवं मानव निर्मित रेशों से निर्मित कपड़े (4.8) (7.8)	
	5. परिवहन उपकरणों के अलावा मशीनरी एवं उपकरण (10.5) (14.2)	5. सूती कपड़े (4.3) (14.8)	
		6. कपड़ा उत्पाद (पहनने वाले कपड़ों सहित) (3.7) (11.5)	
		7. परिवहन उपकरण एवं पुर्जे (2.9) (15.0)	
		8. कागज एवं कागज के उत्पाद (2.7) (8.7)	

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर हैं।
2. इटालिक अक्षरों में लिखे हुए आंकड़े वर्ष 2006-07 के हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

2.29 तथापि पूंजी वस्तु क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि कार्यानिष्पादन जारी रहा। 2007-08 में पूंजी वस्तु क्षेत्र में 2006-07 की 18.2 प्रतिशत की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की गयी। फलस्वरूप 2007-08 में आइआइपी की वृद्धि में इसका अंशदान 2006-07 के 28.5 प्रतिशत से घटकर 22.9 प्रतिशत रह गया। ऐसा उपभोक्ता गैर टिकाऊ माल में न्यूनतर वृद्धि तथा उपभोक्ता टिकाऊ माल के उत्पादन में गिरावट के कारण हुआ। अन्य वस्तुओं में धातु के बर्तनों, टाइपराइटर्स, टेलीफोन उपकरणों, टेपरिकार्डर्स, मोटर साइकलों, अलार्म घड़ियों तथा कलाई घड़ियों के उत्पादन में हुई गिरावट के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 1.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि (2006-

07 में 9.2 प्रतिशत) दर्ज की गयी। साथ ही, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में मंदी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया प्रतीत होता है क्योंकि उपभोक्ता की पसंद में बदलाव तथा हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकीय रूप से उत्कृष्ट उत्पादों की उपलब्धता के कारण 1993-94 श्रृंखला पर आधारित वर्तमान आइआइपी बास्केट द्वारा इस खण्ड में उत्पाद अप्रचलन को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है (रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, बॉक्स II.6, पृष्ठ 60 देखें)।

मूलभूत संरचना

2.30 2007-08 में मूलभूत संरचना क्षेत्र की वृद्धि 2006-07 के 9.3 प्रतिशत से कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गयी (सारणी 2.11)। इस

सारणी 2.10: क्षेत्रवार वृद्धि एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) वृद्धि में अंशदान

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आइआइपी में भार	वृद्धि			सापेक्ष अंशदान		
		2005-06	2006-07	2007-08#	2005-06	2006-07	2007-08#
1	2	3	4	5	6	7	8
मूल वस्तुएं	35.57	6.7	10.3	7.0	25.4	27.2	24.7
पूंजीगत माल	9.26	15.7	18.2	18.0	20.0	17.6	25.0
मध्यवर्ती माल	26.51	2.5	12.0	8.9	8.4	27.0	27.4
उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	28.66	12.0	10.1	6.1	46.3	28.5	22.9
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.36	15.3	9.2	-1.0	14.9	6.7	-1.0
ख) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	23.30	10.9	10.4	8.5	31.4	21.8	24.0
आई आई पी	100	8.2	11.5	8.5	100	100	100

: अनन्तितम

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

सारणी 2.11: मूलभूत संरचना उद्योगों की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	आईआईपी में भार	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1. बिजली	10.2	5.0	5.2	5.2	7.3	6.3
2. कोयला	3.2	5.1	6.2	6.6	5.9	6.0
3. तैयार इस्पात	5.1	9.8	8.4	10.8	13.1	5.1
4. सीमेंट	2.0	6.1	6.6	12.4	9.1	8.1
5. कच्चा पेट्रोलियम	4.2	0.7	1.8	-5.2	5.5	0.4
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2.0	8.2	4.3	2.1	12.9	6.5
संमिश्र सूचकांक	26.7	6.1	5.8	6.1	9.3	5.6

निम्न वृद्धि में कोयला को छोड़कर सभी प्रमुख मूलभूत संरचना क्षेत्र का अंशदान था। बिजली क्षेत्र ने 6.3 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर्ज की तथा 2007-08 में मूल क्षेत्र की वृद्धि में 39.3 प्रतिशत का अंशदान किया। सीमेंट क्षेत्र ने 2007-08 में 8.1 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की।

2.31 देश से इस्पात निर्यात में कमी ने इस्पात उत्पादन की वृद्धि कम होने में अंशदान किया, हालांकि घरेलू मांग में सुदृढ़ता बनी हुई है। कच्चा तेल क्षेत्र में ओएनजीसी की मुंबई हाई इकाई में उत्पादन में गिरावट के कारण 0.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। 2007-08 के दौरान सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि में मुख्यतः आधार प्रभाव के कारण घट-बढ़ देखी गयी। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र की वृद्धि में कमी का कारण आधार प्रभाव, न्यूनतर क्षमता उपयोग तथा सरकारी क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियों में उत्पादन में गिरावट है।

सेवा क्षेत्र

2.32 2007-08 में सेवा क्षेत्र में 2006-07 में हुई 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.12)। वर्ष 2007-08 लगातार ऐसा तीसरा वर्ष था जब सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि हुई। देशी उत्पादन का 62.9 प्रतिशत इस क्षेत्र से संबंधित है। 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र' में पिछले पांच वर्षों में दुहरे अंकों की

वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्तमान में यह सेवा क्षेत्र की वृद्धि का लगभग आधा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पिछले छः वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि में निर्यात तथा आयात में क्रमशः 24.0 प्रतिशत तथा 29.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हुई सुदृढ़ वृद्धि के अलावा देशी खुदरा क्षेत्र में उछाल, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन में तेज वृद्धि तथा हवाई क्षेत्र में उछाल के कारण इस उपक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

2.33 'सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा' क्षेत्र में मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा इन सेवाओं पर किए गए उच्चतर व्यय के कारण 2007-08 के दौरान वृद्धि में सुधार हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं में विस्तार के कारण 'वित्तीयन, बीमा, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवा' में दुहरे अंकों की वृद्धि बरकरार रखी गयी हालांकि आधार प्रभाव के कारण इसमें कुछ कमी आयी।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग

2.34 2007-08 में भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योगों का सुदृढ़ कार्यनिष्पादन जारी रहा तथा आउटसोर्सिंग भारत में आईटीईएस-बीपीओ

सारणी 2.12: सेवा उप क्षेत्रों में तिमाही वृद्धि कार्य-निष्पादन

(आधार : 1999-2000)

(प्रतिशत)

उप क्षेत्र	2006-07					2007-08				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. विनिर्माण	13.1	12.0	10.8	12.2	12.0	7.7	11.8	7.1	12.6	9.8
2. व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	10.9	12.7	12.1	11.6	11.8	13.1	11.0	11.5	12.4	12.0
3. वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं	13.6	13.9	14.7	13.4	13.9	12.6	12.4	11.9	10.5	11.8
4. सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	10.3	7.2	5.6	5.1	6.9	5.2	7.7	6.2	9.5	7.3
5. सेवाएं	11.7	11.6	11.1	10.5	11.2	10.6	10.7	10.0	11.4	10.7
कारक लागत पर जीडीपी	9.6	10.1	9.3	9.7	9.6	9.2	9.3	8.8	8.8	9.0

उद्योग की वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहा। तथापि, अमरीका के हिस्से में हुई थोड़ी गिरावट को प्रतितुलित करते हुए यूरोप एवं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में देखी गई वृद्धि के साथ आउटसोर्सिंग बाजारों में कुछ बदलाव देखा गया। भारतीय आइटी उद्योग ने हाल के समय में अन्य भौगोलिक क्षेत्र में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया है। नैसकॉम के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय आइटी-आइटीईएस उद्योग (देशी बाजार सहित) 2007-08 में 33.3 प्रतिशत बढ़ा। साफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात खण्ड में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उसका राजस्व 2006-07 के 31.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 40.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत अपने प्रतिभावान स्टाफ के कारण वैश्विक आइटी सोर्सिंग का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है। तथापि, गुणवत्ता प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ अल्पावधि से मध्यावधि चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान किए जाने की जरूरत है। इनमें उपलब्ध प्रतिभा के कौशल को अपग्रेड करना, मूलभूत सुविधा का विकास तथा सकारात्मक नीति/विनियामक माहौल को बनाए रखना शामिल हैं। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने के लिए उद्योग तथा सरकार सहित सभी पणधारियों द्वारा समय पर, सुसंगत और निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

औद्योगिक संभावना

2.35 आइआइपी वृद्धि में कुछ कमी के बावजूद निवेश की सुदृढ़ मांग सहित उद्योग ने 2007-08 में अच्छा कार्यनिष्पादन दर्ज करना जारी रखा जो क्षमता विस्तार को दर्शाता है। तथापि, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की वृद्धि में प्राथमिक तौर पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं

के उत्पादन में आयी गिरावट के कारण उल्लेखनीय गिरावट आयी। खनन क्षेत्र, जिसका कार्यनिष्पादन 2005-06 में अच्छा नहीं रहा, ने 2006-07 में सुधार दर्ज किया तथा 2007-08 में इसमें सामान्य वृद्धि हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में छोटे वेतन संशोधन अवार्ड के कार्यान्वयन के साथ केंद्रीय बजट 2008-09 में निजी आयकर स्लैब में समायोजन तथा उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों के रूप में दिए गए प्रोत्साहनों के फलस्वरूप 2008-09 में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में गति आने की संभावना है। तथापि, औद्योगिक निविष्टियों की कीमतों में तेज वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने तथा देशी मुद्रास्फीतिकारी स्थितियों जैसी कुछ अधोमुखी जोखिम हैं।

2.36 2008-09 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान सारणी 2.13 में दिए गए हैं।

III. राजकोषीय स्थिति

केंद्र सरकार के वित्त

2.37 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमानों (आरई) में जीडीपी के संबंध में प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् राजस्व घाटा (आरडी) तथा राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में निम्नतर रखा गया है। अंतिम खातों में इन अनुपातों अर्थात् जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आरडी तथा जीएफडी में और

सारणी 2.13: वर्ष 2008-09 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि के लिए एजेंसियों का पूर्वानुमान

एजेंसी	समग्र वृद्धि	कृषि	उद्योग	सेवाएं	अनुमान का माह
1	2	3	4	5	6
एसोचैम	7.6	4.0	7.2	9.0	जुलाई 2008
मेरिल लिंच	7.9	2.5	7.4	9.6	जून 2008
जेपी मोर्गन	7.0	मार्च 2008
सीएमआई	9.4	3.2	11.1	10.6	अगस्त 2008
क्रिसिल	7.8	3.0	8.3	10.3	जून 2008
गोल्डमैन ससे	7.8	जुलाई 2008
विश्व आर्थिक स्थिति एवं भविष्य, यूएन 2008	8.2	जनवरी 2008
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	7.7	2.0	7.5	9.6	अगस्त 2008
एडीबी	8.0	अप्रैल 2008
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	8.0 *	जुलाई 2008
सीआईआई	8.0-8.5	मार्च 2008
आरबीआई	लगभग 8.0	जुलाई 2008
एनसीईआर	7.8	अगस्त 2008
.. : उपलब्ध नहीं		* : कैलेण्डर वर्ष			

गिरावट आयी। अंतिम खातों में जीडीपी के संबंध में प्राथमिक अधिशेष भी आरई की तुलना में उच्चतर था जो, बदले में, बीई की तुलना में उच्चतर था। प्रमुख घाटा संकेतकों में कटौती के लिए राजस्व प्राप्तियों में सुधार मुख्य रूप से जिम्मेवार था। 2008-09 के बजट अनुमानों में जीडीपी के संबंध में आरडी तथा जीएफडी में संशोधित अनुमानों तथा 2007-08 के अंतिम खातों की तुलना में और गिरावट आने की आशा थी। जहां जीएफडी संबंधी एफआरबीएम लक्ष्य अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना है, शून्य आरडी का निर्धारित लक्ष्य जिसे 2008-09 तक प्राप्त किया जाना था, प्राथमिक तौर पर राजस्व व्यय प्रधान कार्यक्रमों और योजनाओं के पक्ष में योजना की प्राथमिकताओं में आए बदलाव के कारण एक और वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित किया गया जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना है। बजट में प्रस्ताव किया गया कि चल रहे सुधार और राजकोषीय सुधार संबंधी पहलों से घरेलू मांग और निवेश, जिनमें से दोनों जीडीपी की वृद्धि के मुख्य वाहक हैं, बढ़ाने में समर्थन मिलना जारी रहेगा। इस लक्ष्य के प्रति बजट में निजी आयकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क को युक्तियुक्त बनाया गया, सेवा क्षेत्र का विस्तार और सेवाओं तक करके कर आधार को व्यापक बनाया गया तथा परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर व्यय प्रबंधन में सुधार लाया गया और सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त निवेश हेतु प्रावधान किया गया। बजट में भौतिक तथा सामाजिक मूलभूत संरचना के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए धारित, तीव्र और अधिक समावेशक वृद्धि के लिए प्राथमिकता देने पर मुख्य रूप से बल दिया गया।

2.38 विपत्तिग्रस्त किसानों की मदद के लिए ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना लागू करने का एक प्रमुख प्रस्ताव बजट में लाया गया, जिसकी केंद्र सरकार को अनुमानित लागत 71,680 करोड़ रुपए थी। इस व्यय को चरणों में चार राजकोषीय वर्षों के अंदर कुछ फ्रंट लोड के साथ वितरित किया जायेगा।

2.39 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष केंद्रीय बजट 2008-09 में समेकन, चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ वित्तीय आधार देने, कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी तथा जवाबदेही लागू करने तथा प्राप्त लक्ष्यों एवं उसकी गुणवत्ता के रूप में परिणामों को मापने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अतः सरकार ने प्रस्ताव किया कि प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकनों को प्राधिकृत कर मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया जाए। केंद्रीय योजना तथा केंद्र द्वारा प्रवर्तित स्कीमों के लिए स्कीम-वार तथा राज्यवार निर्मोचनों पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) लागू करने का प्रस्ताव किया गया। बजट में महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान की स्कीमों पर विशेष बल दिया गया।

2.40 हाल के वर्षों में कर नीति राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए कर-जीडीपी अनुपात बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य द्वारा नियंत्रित है। इसे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों तथा कर प्रशासन की गुणवत्ता और प्रभावशालिता में पक्का सुधार लाकर दोनों के जरिए प्राप्त किया जाना है। प्रत्यक्ष कर के संबंध में, मुख्य रणनीति यह है कि निम्नलिखित के रूप में हाल के वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को और समेकित किया जाए : (i) कर आधार बढ़ाकर तथा कर दरों को कम रखकर कर संरचना के भीतर व्याप्त विकृतियों को न्यूनतम करना; (ii) करदाता सेवाओं के साथ निवारक स्तरों को बढ़ाकर ऐच्छिक अनुपालन का संवर्धन करना; तथा (iii) आयकर विभाग की कार्यपरक दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, माल (केंद्रीय उत्पाद) तथा सेवा संबंधी करों को समन्वित कर माल और सेवा कर की ओर अंततः अग्रसर होने की रणनीति है। इस लक्ष्य के लिए सामान्य केंद्रीय मूल्यवर्धित कर की दर को 16 प्रतिशत से कम कर 14 प्रतिशत कर दिया गया जो सेवाओं पर लगायी जाने वाली 12 प्रतिशत कर दर के काफी निकट है। सेवा कर के मामले में कर आधार को बढ़ाने, विधि और प्रक्रिया को सरल बनाने, कर प्रशासन में सुधार तथा कर अनुपालन में वृद्धि की रणनीति है। कर आधार को बढ़ाने के लिए, कुछ और सेवाएं जोड़कर एवं कुछ मौजूदा सेवाओं का दायरा बढ़ाकर देय सेवाओं की व्याप्ति और कवरेज को और अधिक बढ़ा दिया गया है।

संशोधित अनुमान 2007-08²

2.41 2007-08 के संशोधित अनुमानों में एफआरबीएम ढांचे के तहत राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसे दर्शाते हुए राजस्व घाटा तथा जीडीपी संबंधी राजकोषीय घाटा उनके बजट स्तरों से नीचे रखा गया। ब्याज अदायगी और सब्सिडी के लिए उच्चतर प्रावधान के कारण राजस्व व्यय में हुई वृद्धि के बावजूद, कर और करेतर राजस्व (मुख्यतः संचार सेवाओं के कारण) में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व घाटे में कमी आयी। पूंजी व्यय में कमी के साथ राजस्व घाटे में सुधार के फलस्वरूप जीएफडी का स्तर कम हुआ। संशोधित अनुमानों में प्राथमिक अधिशेष में उल्लेखनीय सुधार हुआ। योजना व्यय में बजट अनुमानों से अधिक अंतर नहीं था, हालांकि संशोधित अनुमानों में राज्य एवं केंद्रशासित राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.42 संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 11.2 प्रतिशत कम हुआ तथा 1.5 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में 2007-08 में वह जीडीपी का 1.4 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों में 38,676 करोड़ रुपए (8.0 प्रतिशत) के उल्लेखनीय सुधार, जिसने राजस्व व्यय में हुई 30,686

² इस खण्ड में 2007-08 की सभी तुलनाएं, अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर, बजट अनुमानों के साथ हैं।

करोड़ रुपए (5.5 प्रतिशत) की वृद्धि को प्रतितुलित कर दिया, के कारण राजस्व घाटे में गिरावट आयी। जीएफडी में 7,295 करोड़ रुपए (4.8 प्रतिशत) की कमी आयी। जीडीपी के रूप में यह बजट अनुमान (3.3 प्रतिशत) की तुलना में 3.1 प्रतिशत पर कम था (सारणी 2.14)। 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत पर प्राथमिक अधिशेष बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 3.5 गुना उच्चतर था।

2.43 2007-08 के संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में 37,288 करोड़ रुपए अधिक था। संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निगम और व्यक्तिगत आय कर की वसूली का बजट के स्तर की तुलना में अधिक होना है। कंपनियों के अच्छे तुलनपत्र के समर्थन से उनके उच्चतर लाभ के कारण निगम कर में 17,724 करोड़ रुपए अथवा 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्यतः कर अनुपालन में सुधार के कारण व्यक्तिगत आय कर की वसूली में 16,641 करोड़ रुपए अथवा 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल में शुरू किए गए करों में, 2007-08 में सीमांत लाभ कर से 6,800 करोड़ रुपए, प्रतिभूत लेनदेन कर से 7,500 करोड़ रुपए तथा बैंकिंग नकद लेनदेन कर से 550 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। करेतर राजस्व भी द्वैध प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वालों तथा नये एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएसएसएल) परिचालकों से एकबारगी प्रवेश शुल्क के जरिए संचार सेवाओं से अधिक प्राप्ति के कारण बजट अनुमानों की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक था (सारणी 2.15)।

2.44 ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के तहत, ऋणों और अग्रियों की वसूली में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

2.45 2007-08 के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय बजट अनुमानों की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक था, जबकि पूंजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.16)। मुख्यतः ब्याज अदायगी, उर्वरक और ब्याज सब्सिडी, राज्यों को अनुदान तथा पेंशन के कारण राजस्व व्यय अधिक हुआ। पूंजीगत व्यय के भीतर, ऋण और अग्रिम तथा रक्षेतर पूंजी परिव्यय बजट अनुमानों की तुलना में अधिक थे।

बजट अनुमान 2008-09³

2.46 पिछले साल लक्ष्य प्राप्त करने के बाद 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 में किए गए प्रावधान के अनुसार राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जाए। 2008-09 के लिए बजट अनुमानों (बीई) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात् राजस्व घाटा (आरडी) तथा सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को 2007-08 के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में कम रखा गया। एफआरबीएम के रोड मॉप में राजकोषीय घाटे में कम से कम 0.3 प्रतिशत अंक की तथा राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशत अंक की वार्षिक कटौती करने की परिकल्पना की गयी है। जहां जीएफडी संबंधी एफआरबीएम लक्ष्यों को अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना है, वहीं प्राथमिक तौर पर राजस्व व्यय प्रधान कार्यक्रमों तथा स्कीमों के पक्ष में योजना की प्राथमिकताओं में बदलाव आने के कारण एफआरबीएम नियमावली, 2004 के अंतर्गत 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटे का निर्धारित लक्ष्य पुनर्निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अल्पावधि में योजनेतर व्यय नियंत्रित करने में व्यवस्थागत जटिलताएं हैं जो विशेष रूप से ब्याज भुगतान, पेंशन और रक्षा जैसे वचनबद्ध तथा

सारणी 2.14: केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक

(करोड़ रुपए)

मद	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09	घट-बढ़ प्रतिशत	
	(खाते)	(बअ)	(संअ)	(बअ)	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
1	2	3	4	5	6	7
सकल राजकोषीय घाटा	1,42,573 (3.5)	1,50,948 (3.3)	1,43,653 (3.1)	1,33,287 (2.5)	-4.8	-7.2
राजस्व घाटा	80,222 (1.9)	71,478 (1.5)	63,488 (1.4)	55,184 (1.0)	-11.2	-13.1
सकल प्राथमिक घाटा	-7,699 (-0.2)	-8,047 (-0.2)	-28,318 (-0.6)	-57,520 (-1.1)	251.9	103.1

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

³ इस खण्ड में 2008-09 की सभी तुलनाएं, अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर, 2007-08 के संशोधित अनुमानों के साथ हैं।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.15: केंद्र की प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07	2007-08 (बअ)	2007-08 (संअ)	2008-09 (बअ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
					स्तंभ 3 की तुलना में	स्तंभ 4 की तुलना में
1	2	3	4	5	6	7
कुल प्राप्तियां (1+2)	5,83,387 (14.1)	6,80,521 (14.5)	7,09,373 (15.1)	7,50,884 (14.2)	4.2	5.9
1. राजस्व प्राप्तियां	4,34,387 (10.5)	4,86,422 (10.4)	5,25,098 (11.2)	6,02,935 (11.4)	8.0	14.8
i) कर राजस्व (निवल)	3,51,182 (8.5)	4,03,872 (8.6)	4,31,773 (9.2)	5,07,150 (9.6)	6.9	17.5
ii) गैर-कर राजस्व	83,205 (2.0)	82,550 (1.8)	93,325 (2.0)	95,785 (1.8)	13.1	2.6
2. पूंजीगत प्राप्तियां	1,49,000 (3.6)	1,94,099 (4.1)	1,84,275 (3.9)	1,47,949 (2.8)	-5.1	-19.7
जिसमें से:						
बाजार उधार	1,14,801 (2.8)	1,10,827 (2.4)	1,10,727 (2.4)	99,000 (1.9)	-0.1	-10.6
ऋणों की वसूलियां	5,893 (0.1)	1,500 (0.0)	4,497 (0.1)	4,497 (0.1)	199.8	0.0
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का विनिवेश	534 (0.0)	1,651* (0.0)	1,817# (0.0)	10,165 (0.2)	10.1	459.4
ज्ञापन मदें						
सकल कर राजस्व	4,73,512 (11.4)	5,48,122 (11.7)	5,85,410 (12.5)	6,87,715 (13.0)	6.8	17.5
जिसमें से:						
i) निगम कर	1,44,318 (3.5)	1,68,401 (3.6)	1,86,125 (4.0)	2,26,361 (4.3)	10.5	21.6
ii) निगम कर के अलावा आय पर कर\$	80,397 (1.9)	93,629 (2.0)	1,10,270 (2.3)	1,28,764 (2.4)	17.8	16.8
iii) सीमा शुल्क	86,327 (2.1)	98,770 (2.1)	1,00,766 (2.1)	1,18,930 (2.2)	2.0	18.0
iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,17,613 (2.8)	1,30,220 (2.8)	1,27,947 (2.7)	1,37,874 (2.6)	-1.7	7.8
v) सेवा कर	37,598 (0.9)	50,200 (1.1)	50,603 (1.1)	64,460 (1.2)	0.8	27.4
vi) प्रतिभूति लेन-देन कर	4,646 (0.1)	4,500 (0.1)	7,500 (0.2)	9,000 (0.2)	66.7	20.0
vii) बैंकिंग नकद लेन-देन कर	507 (0.0)	645 (0.0)	550 (0.0)	550 (0.0)	-14.7	0.0
viii) संघशासित क्षेत्रों के कर (स्थानीय निकायों को समुद्देशन के बाद निवल)	1,263 (0.0)	1,442 (0.0)	1,334 (0.0)	1,451 (0.0)	-7.5	8.8
ix) अन्य कर एवं शुल्क	843 (0.0)	315 (0.0)	315 (0.0)	325 (0.0)	0.0	3.2
बअ: बजट अनुमान		संअ: संशोधित अनुमान				
* : भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी लेनदेन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि समायोजित ।						
\$: अनुषंगी लाभ कर शामिल है।						
# : केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से होने वाले लाभ के अन्तरण की निवल राशि 34,308 करोड़ रुपए है।						
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत हैं।						
2. इस खण्ड में वर्ष 2007-08 की गई सभी तुलनाएं वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों से की गई हैं, जब तक उन्हें अन्यथा न कहा जाए।						

बाध्यकारी व्ययों से उत्पन्न होती हैं। तथापि, जीएफडी/जीडीपी अनुपात एफआरबीएम लक्ष्य की तुलना में निम्नतर होगा। तदनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात् राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष के क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत तथा -0.6 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में क्रमशः

1.0 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत तथा -1.1 प्रतिशत पर कम होने का बजट अनुमान है (सारणी 2.14)। राजस्व घाटा तथा जीएफडी को उस सीमा तक कम आंका गया है जिस सीमा तक सरकार तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों से उत्पन्न देयताओं का वहन करती हैं जिसे लाइन के नीचे दर्ज किया जाता है। अतः राजकोषीय लेखांकन में अधिक पारदर्शिता लाने के उपाय

सारणी 2.16: केंद्र के व्यय का पैटर्न

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07	2007-08 (बअ)	2007-08 (संअ)	2008-09 (बअ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
					स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय (1+2)	5,83,387	6,80,521	7,09,373	7,50,884	4.2	5.9
1. राजस्व व्यय	5,14,609	5,57,900	5,88,586	6,58,119	5.5	11.8
ब्याज अदायगी	1,50,272	1,58,995	1,71,971	1,90,807	8.2	11.0
उपदान	57,125	54,330	69,742	71,431	28.4	2.4
राज्यों को अनुदान	35,734	38,403	36,432	43,294	-5.1	18.8
रक्षा राजस्व	51,682	54,078	54,795	57,593	1.3	5.1
2. पूंजीगत व्यय	68,778	82,621*	85,256#	92,765	3.2	8.8
ऋण और अग्रिम	8,524	7,498	10,992	8,243	46.6	-25.0
रक्षा पूंजी परिव्यय	33,828	41,922	37,705	48,007	-10.1	27.3
गैर रक्षा पूंजी परिव्यय	26,426	33,201*	36,559#	36,515	10.1	-0.1

बअ : बजट अनुमान संघ : संशोधित अनुमान

* : भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी लेनदेनो के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि समायोजित ।

: भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की 35.531 करोड़ रू. की अभिग्रहण लागत सो घटाकर ।

के तौर पर बजट में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में कुल 18,757 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की सूचना दी गई।

2.47 सरकार ने बेहतर व्यय प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखा। 2008-09 में राजस्व व्यय में 2007-08 के 14.4 प्रतिशत की तुलना में 11.8 प्रतिशत की निम्न वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 2.16)। उल्लेखनीय तौर पर कुल सब्सिडी की वृद्धि 2007-08 में हुई 22.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम होने का बजट अनुमान था। भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी सरकार को अंतरित करने संबंधी लेनदेन के रूप में 35,531 करोड़ रुपए का समायोजन करने के बाद पूंजीगत व्यय 2007-08 के 24.0 प्रतिशत की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान था।

2.48 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में हुई 20.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान था, जिसका प्राथमिक कारण सकल कर वसूलियों में 2007-08 के 23.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 17.5 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि होने का बजट अनुमान है। प्रत्यक्ष करों में निगम कर की वसूलियों में वृद्धि 2007-08 के 29.0 प्रतिशत के ऊंचाई से कम होकर 2008-09 में 21.6 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान था। निजी आय कर में वृद्धि 2007-08 के 37.2 प्रतिशत से कम होकर 16.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था। अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क के तहत वसूली में एक साल पहले के 16.7 प्रतिशत की तुलना में 18.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि का बजट अनुमान था। तथापि, उत्पाद शुल्क की वसूली में 8.8 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि का बजट अनुमान था। करेतर राजस्व

(एनटीआर) 2007-08 के 93,325 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 95,785 करोड़ रुपए होने का बजट अनुमान था, जो लाभांश और लाभ से प्राप्त उच्चतर राजस्व को दर्शाता है। दूसरी ओर, ब्याज प्राप्तियों में गिरावट जारी रही जिसका मुख्य कारण यह था कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार राज्यों को केंद्र द्वारा दिया गया उधार सिर्फ बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋणों के लिए सीमित है (सारणी 2.15 देखें)।

2.49 सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न यह दर्शाता है कि निवल बाजार उधार राशियों (एमएसएस के तहत बजट अनुमान लगाए गए आबंटनों को छोड़कर) द्वारा 2007-08 के 77.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में जीएफडी के 74.3 प्रतिशत वित्तपोषण का बजट अनुमान था। दूसरी ओर, बाह्य सहायता का हिस्सा 2007-08 के 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत होने का बजट अनुमान था। केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा निवेश से जीएफडी के 7.4 प्रतिशत का वित्तपोषण करने का बजट प्रावधान है। 2008-09 के दौरान, बजट में प्रस्ताव किया गया कि पिछले वर्ष जीएफडी के 12.7 प्रतिशत के नकद शेष के निर्माण के विरुद्ध जीएफडी के 5.4 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए नकद शेष का आहरण किया जाए (सारणी 2.17)।

संभावना

2.50 बजट 2008-09 में राजकोषीय सुधार का अनुसरण जारी रहा तथा एफआरबीएम के लक्ष्यों के अनुसार व्यय की गुणवत्ता पर बल दिया गया। यद्यपि बजट ने राजस्व घाटे में हर साल जीडीपी के 0.5 प्रतिशत

सारणी 2.17: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न
(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (संअ)	2008-09 (बअ)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	1,43,653	1,33,287
निम्न द्वारा वित्तपोषित :		
बाजार उधार	1,10,727 (77.1)	99,000 (74.3)
अल्पावधि उधार (क+ख)	25,497 (17.7)	14,000 (10.5)
क) 91 दिवसीय खजाना बिल	26,628	15,000
ख) 182 दिवसीय खजाना बिल	-1,131	-1,000
लघु बचतों के बदले प्रतिभूतियां	-1,802 (-1.3)	9,873 (7.4)
बाह्य सहायता	9,970 (6.9)	10,989 (8.2)
राज्य भविष्य निधि	4,800 (3.3)	4,800 (3.6)
एनएसएसएफ	11,174 (7.8)	53 (0.0)
आरक्षित निधि	3,504 (2.4)	-972 (-0.7)
जमा एवं अग्रिम	7,807 (5.4)	8,629 (6.5)
डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधियां	3,045 (2.1)	4,123 (3.1)
अन्य	-12,885 (-9.0)	-24,433 (-18.3)
नकद शेष का आहरण	-18,184 (-12.7)	7,225 (5.4)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे का प्रतिशत दर्शाते हैं।

की वार्षिक कटौती संबंधी एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा किया गया, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर अधिक खर्च के कारण अभी भी यह जीडीपी का 1.0 प्रतिशत है। बकाया राशि के भुगतान सहित छोटे वेतन आयोग (एसपीसी) के निर्णय के कार्यान्वयन, उच्चतर तेज सब्सिडी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल तथा उर्वरक के मूल्य में तेज वृद्धि के कारण उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि तथा किसानों का ऋण माफ किए जाने के कारण हुए व्यय की वजह से 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त पर दबाव बढ़ सकता है।

राज्य वित्त

2.51 राज्य सरकारों ने 2008-09 के अपने बजट में राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता को दुहराया है। मार्च 2008 के अंत में पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) तैयार किया है। सभी राज्यों ने बिक्री कर के बदले मूल्यवर्धित कर (वीएटी) लागू किया है तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश ने वीएटी 1 जनवरी 2008 से लागू किया है।

2.52 राज्य सरकारों ने 2008-09 के अपने बजट में कई नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया जिनका उद्देश्य राजस्व में वृद्धि तथा व्यय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निदेशित करना था। कई राज्यों में 2008-09 में कृषि एवं जलसंरक्षण, मूलभूत संरचना, पावर, शहरी विकास तथा आवास क्षेत्र जैसे उत्पादक क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें भी इंदिरा आवास योजना तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहित विभिन्न स्कीमों के तहत कम और मध्यम आय समूहवाले परिवारों तथा गंदी बस्ती में रहनेवालों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए भवन निर्माण का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकारें राजकोषों और कर विभागों के कंप्यूटरीकरण का कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य ने नकदी प्रवाह प्रणाली में सुधार लाने के लिए कंप्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली लागू की है। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ और राज्यों ने महिला सशक्तीकरण के लिए लिंग बजट बनाना शुरू किया है। केरल राज्य ने जेंडर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। मणिपुर ने गारंटी उन्मोचन कोष तथा समेकित निक्षेप निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 13 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का गठन किया गया जिसकी पंचाट की अवधि 2010-15 होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा गठित छठे वेतन आयोग ने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जहां कई राज्यों ने केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण किया, कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए अलग वेतन आयोग गठित किए।

बजट अनुमान - 2008-09⁴

2.53 राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (संअ) के 22,526 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.48 प्रतिशत) की तुलना में 2008-09 (बअ) में 28,426 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.54 प्रतिशत) होने का अनुमान है। यद्यपि जीएफडी 2007-08 (संअ) के 1,07,958 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 (बअ) में 1,12,653 करोड़ रुपए पर उच्चतर होने का बजट अनुमान है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 2007-08 (संअ) के 2.3 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (बअ) में 2.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। समेकित प्राथमिक घाटा 2008-09 (बअ) में जीडीपी का 0.1 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है, जो पिछले वर्ष के अनुरूप है (सारणी 2.18)।

2.54 2008-09 के दौरान राजस्व खाते में सुधार मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के द्वारा प्राप्त होने का बजट अनुमान है, जो विभाजन

⁴ 2008-09 के लिए राज्य वित्त का विश्लेषण (बजट अनुमान) 28 राज्य सरकारों के बजटों पर आधारित है।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.18: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	औसत			2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2007-08 संअ	2008-09 बअ
	1990-95	1995-00	2000-05					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084	77,509	108,323	107,958	112,653
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013	-24,857	-11,973	-22,526	-28,426
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060	-15,654	5,648	5,080	4,270
				(0.2)	(-0.4)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : (1) ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष को दर्शाता है।
(2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
(3) वर्ष 2006-07 के लिए सकल देशी उत्पाद के आंकड़े सीएसओ के त्वरित अनुमानों पर आधारित हैं; जबकि वर्ष 2007-08 के लिए आंकड़े इसके संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2008-09 के सकल देशी उत्पाद के आंकड़े केंद्रीय बजट दस्तावेज, 2008-09 के अनुरूप हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

योग्य करों में वृद्धि, राज्यों की अपने कर राजस्व तथा केंद्र से अनुदान से प्राप्त होगा (सारणी 2.19)। राजस्व व्यय में कमी, विशेष रूप से ब्याज भुगतान और पेंशन में कमी द्वारा भी राजस्व खाते में सुधार किया जाएगा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय को पिछले वर्ष के अनुसार 2008-09 (बअ) में 2.7 प्रतिशत पर बनाए

रखा जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि 2008-09 (बअ) में विकासात्मक व्यय कम होने का बजट अनुमान है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय बढ़ने का बजट अनुमान है (सारणी 2.20)।

2.55 2008-09 (बअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाए जाने के साथ, राजस्व अधिशेष से पूंजीगत परिव्यय

सारणी 2.19: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	औसत			2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2007-08 संअ	2008-09 बअ	प्रतिशत घट-बढ़		
	1990-95	1995-00	2000-05						स्तंभ 8/6	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राप्तियां (1+2)	(16.0)	(14.8)	(17.2)	595,627	673,358	767,695	763,367	895,307	13.4	-0.6	17.3
1. कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	(12.0)	(10.7)	(11.2)	431,020	530,556	606,733	628,742	719,835	18.5	3.6	14.5
(क) राज्यों का अपना राजस्व	(7.2)	(6.7)	(7.0)	260,246	315,812	353,229	355,970	403,658	12.7	0.8	13.4
राज्यों का अपना कर	(5.3)	(5.1)	(5.6)	212,307	252,548	294,038	293,392	336,810	16.2	-0.2	14.8
राज्यों के अपने करेतर राजस्व	(1.8)	(1.6)	(1.4)	47,939	63,263	59,191	62,578	66,848	-1.1	5.7	6.8
(ख) केंद्रीय अंतरण	(4.8)	(4.0)	(4.2)	170,774	214,744	253,504	272,773	316,177	27.0	7.6	15.9
हिस्सेदारी योग्य कर	(2.6)	(2.4)	(2.4)	94,024	120,293	136,184	148,134	173,147	23.1	8.8	16.9
केंद्रीय अनुदान	(2.3)	(1.6)	(1.8)	76,750	94,451	117,320	124,638	143,030	32.0	6.2	14.8
2. पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	(4.0)	(4.1)	(6.0)	164,607	142,802	160,962	134,625	175,472	-5.7	-16.4	30.3
(क) केंद्र से ऋण@	(1.9)	(1.7)	(1.0)	8,097	5,529	14,918	11,291	15,349	104.2	-24.3	35.9
(ख) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	(2.1)	(2.4)	(5.0)	156,510	137,273	146,043	123,334	160,123	-10.2	-15.5	29.8

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान

@: वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से को, जिसे पूर्व में केंद्र की ओर से ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया था, आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है और उसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि वर्ष 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के लिए आंकड़े, जो इस सारणी में दर्शाए गए हैं, तुलना के प्रयोजनार्थ अल्प बचतों के बदले दिए गए ऋणों को छोड़कर हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.20 : राज्य सरकारों के व्यय का पैटर्न

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	औसत			2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2007-08 संअ	2008-09 बअ	प्रतिशत घट-बढ़		
	1990-95	1995-00	2000-05						स्तंभ 8/6	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	(15.9)	(14.9)	(17.1)	561,682 (15.7)	657,280 (15.9)	766,620 (16.3)	787,489 (16.7)	892,783 (16.8)	19.8	2.7	13.4
1. राजस्व व्यय	(12.7)	(12.4)	(13.4)	438,034 (12.2)	505,699 (12.2)	594,760 (12.6)	606,216 (12.9)	691,409 (13.0)	19.9	1.9	14.1
जिसमें से :											
ब्याज भुगतान	(1.7)	(2.0)	(2.7)	84,024 (2.3)	93,164 (2.2)	102,675 (2.2)	102,878 (2.2)	108,383 (2.0)	10.4	0.2	5.4
2. पूंजी व्यय	(3.2)	(2.5)	(3.6)	123,648 (3.5)	151,582 (3.7)	171,859 (3.6)	181,273 (3.8)	201,374 (3.8)	19.6	5.5	11.1
जिसमें से :											
पूंजी परिव्यय	(1.5)	(1.4)	(1.6)	77,559 (2.2)	98,063 (2.4)	118,796 (2.5)	128,331 (2.7)	145,159 (2.7)	30.9	8.0	13.1
3. विकासात्मक व्यय	(10.7)	(9.4)	(9.4)	330,044 (9.2)	392,165 (9.5)	467,695 (9.9)	493,563 (10.5)	557,116 (10.5)	25.9	5.5	12.9
4. गैर विकासात्मक व्यय	(4.3)	(4.8)	(5.9)	190,021 (5.3)	211,872 (5.1)	246,130 (5.2)	241,019 (5.1)	275,609 (5.2)	13.8	-2.1	14.4
5. अन्य*	(0.9)	(0.7)	(1.7)	41,617 (1.2)	53,243 (1.3)	52,794 (1.1)	52,907 (1.1)	60,058 (1.1)	-0.6	0.2	13.5

बअ. : बजट अनुमान संअ. : संशोधित अनुमान
 * : इसमें स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समुपदेशन, सहायता अनुदान और अंशदान, आंतरिक ऋण की अदायगी, केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल है।
 टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।
 स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

का वित्तपोषण किया जाएगा। 2008-09 (बअ) में जीएफडी के बड़े भाग (56.7 प्रतिशत) का वित्तपोषण बाजार उधार द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (19.8 प्रतिशत) तथा भविष्य निधि (11.5 प्रतिशत) का स्थान होगा (सारणी 2.21)।

सारणी 2.21 : राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तपोषण का पैटर्न

(प्रतिशत)

मद	औसत			2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2007-08 संअ	2008-09 बअ
	1990-95	1995-00	2000-05					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वियोजन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	25.3	47.1	54.7	7.8	-32.1	-11.1	-20.9	-25.2
2. पूंजी परिव्यय	55.4	43.2	40.5	86.1	126.5	109.7	118.9	128.9
3. निवल ऋण	19.4	10.0	4.9	6.1	8.0	10.7	9.8	9.7
4. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति*	0.1	0.3	0.0	0.0	2.5	9.3	7.8	13.3
वित्तपोषण (1 से 11 तक)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधार राशियां	16.1	16.4	26.4	17.0	16.8	24.3	58.9	56.7
2. केंद्र से ऋण	48.8	39.7	4.3	0.0	-12.2	6.0	2.9	5.9
3. एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण	-	28.9#	40.2	81.9	72.9	49.6	9.1	19.8
4. एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए ऋण	1.8	2.9	4.0	4.5	1.0	7.3	6.2	6.0
5. भविष्य निधि आदि	17.6	16.2	10.1	11.6	13.4	11.4	11.3	11.5
6. आरक्षित निधियां	6.8	5.6	5.0	5.8	9.8	3.9	-8.9	1.1
7. जमाराशियां और अग्रिम	9.9	9.9	4.2	8.1	16.5	1.4	4.7	4.3
8. उर्ध्व और फुटकर	4.3	2.8	-0.8	8.8	6.1	-1.3	-4.5	-1.6
9. अर्थ प्रेषण	-1.4	-3.7	0.7	0.1	-0.4	0.0	-0.3	0.1
10. अन्य	0.7	1.4	4.7	0.0	-3.3	-1.5	-1.6	-1.4
11. समग्र अधिशेष (-)/घाटा (+)	-4.5	3.0	1.2	-37.7	-20.7	-1.0	22.3	-2.2

बअ. : बजट अनुमान संअ. : संशोधित अनुमान - : लागू नहीं
 * : विनिवेश तथा भूमि की बिक्री से प्राप्त आय शामिल # : केवल 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि इस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी।
 टिप्पणी : 'अन्य' में क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर राज्य निपटान व आकस्मिकता निधि शामिल है।
 स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2.56 2008-09 के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत अनंतिम निवल आबंटन 47,044 करोड़ रुपए है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौती तथा 45 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन को हिसाब में लेते हुए, राज्य सरकारों का सकल बाजार उधार 61,460 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वर्ष में अब तक (31 जुलाई 2008 तक), 8 राज्य सरकारों ने 8.39-9.90 प्रतिशत के दायरे में कट-ऑफ प्रतिफल के साथ नीलामियों के माध्यम से 10,812 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 14 राज्य सरकारों द्वारा (8.00 -8.57 प्रतिशत के दायरे में कट-ऑफ प्रतिफल के साथ) 8,542 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

संभावना

2.57 कुल मिलाकर 25 राज्य सरकारों ने 2008-09 में, जो राजस्व घाटा समाप्त करने के बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के लक्ष्य का अंतिम वर्ष है, बजट में राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है। साथ ही 17 राज्य सरकारों ने टीएफसी के लक्ष्य के एक साल पहले 3 प्रतिशत या उससे कम पर जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात का बजट अनुमान लगाया है। जैसे-जैसे राज्य सरकारें घाटा संकेतकों में कटौती का उद्देश्य पूरा करने के करीब आ रही हैं, उन्हें एफआरएल के बाद की अवधि में इस प्रगति को बनाए रखने पर काफी बल देने की आवश्यकता है। राजस्व बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में राजकोषीय राशि जुटाना महत्वपूर्ण होगा जिसका उपयोग विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जा सके। कर वसूली की दक्षता सुधार कर तथा जनसेवाओं पर उपयुक्त प्रभार लगाकर राजस्व उत्पन्न करने का उधार द्वारा व्यय के वित्तपोषण पर लगाई गई अव्यक्त अधिकतम सीमा के कारण नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के तहत विशेष महत्व है। तथापि, राज्य सेवाओं की सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाकर ही उनका कीमत निर्धारण कर सकते हैं।

2.58 राजकोषीय असंतुलन कम करने के प्रति राज्यों के प्रयास को सिफारिशों के आधार पर केंद्र से बड़ी मात्रा में न्यागमन और अंतरण द्वारा मदद मिली। सभी राज्यों द्वारा वैट लागू करने से भी राज्यों के करों की वृद्धि को सुधारने में मदद मिली। व्यय पक्ष में, जहां राज्य पूंजीगत परिव्यय

बढ़ाने में समर्थ रहे, वहीं एफआरएल अवधि के दौरान राजस्व व्यय को कुछ युक्तियुक्त बनाया गया। एनएसएसएफ के तहत उपचर्यों में गिरावट के साथ जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव आया है। फलस्वरूप बाजार उधार राशियां जीएफडी के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। राज्य सरकारों ने 2008-09 के दौरान अब तक बड़ी मात्रा में नकदी अधिशेष बनाए रखा है, जैसाकि मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में किए गए उनके निवेशों में दिखाई देता है।

2.59 जहां राजकोषीय समेकन के प्रयासों से प्रमुख घाटा संकेतकों को कम करने में मदद मिली है, राज्यों की बकाया देयताओं का स्तर कई उभरते और विकासशील देशों की तुलना में ऊंचा बना हुआ है। यद्यपि ऋण के समेकन और राहत उपायों के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में कुछ कमी आई है, राज्यों के पास उच्च लागत वाले ऋण का बड़ा भाग बना हुआ है। कुछ राज्यों ने नकद शेष स्थिति सुखद होने के कारण ऊंची लागत वाले ऋणों की पूर्व-चुकौती कर दी है।

2.60 राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्टाफ के उच्चतर पारिश्रमिक के प्रभाव को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद और सीमा शुल्क कम किए जाने तथा कुछ राज्यों द्वारा इन उत्पादों पर बिक्री कर घटाए जाने के कारण न्यूनतर कर न्यागमन की वजह से राज्य सरकारों को राजस्व की हानि उठानी पड़ सकती है। निकट भविष्य में नवंबर 2007 में स्थापित तेरहवें वित्त आयोग (पंचाट अवधि:2010-15) की सिफारिशों तथा 1 अप्रैल 2010 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन द्वारा राज्य वित्त का निर्माण होगा।

सार्वजनिक ऋण

2.61 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बकाया देयताएं मार्च 2008 के अंत के 77.0 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत तक केंद्र तथा राज्यों द्वारा चलायी जा रही राजकोषीय समेकन प्रक्रिया तथा सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यानिष्पादन के फलस्वरूप 73.4 प्रतिशत रह जाएंगी (सारणी 2.22)।

सारणी 2.22 : संयुक्त देयताएं और ऋण जीडीपी अनुपात

वर्ष	बकाया देयताएं (करोड़ रुपए)			ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)		
	केंद्र	राज्य	संयुक्त	केंद्र	राज्य	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,28,155	3,68,824	55.2	22.5	64.7
1995-96	6,06,232	2,49,535	7,26,854	50.9	20.9	61.0
2004-05	19,94,422	10,29,174	25,62,015	63.3	32.7	81.3
2005-06	22,60,145	11,67,866	28,79,706	63.1	32.6	80.4
2006-07	25,38,596	12,50,819	31,90,698	61.2	30.2	77.0
2007-08 संअ	28,97,037	13,37,044	36,27,260	61.5	28.4	77.0
2008-09 बअ	30,62,912	14,51,169	38,91,740	57.7	27.4	73.4

संअ. : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

स्रोत : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और राज्य वित्त - बजट अध्ययन, 2007-08, भारतीय रिजर्व बैंक

IV. मौद्रिक और ऋण स्थिति

मौद्रिक स्थिति

2.62 उभरते मुद्रास्फीतिकारी दबावों की पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 2007-08 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2007) में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली गतिविधियों के प्रति सभी संभव उपायों सहित त्वरित प्रतिसाद करने के अपने संकल्प को दुहराया। चूंकि व्यापक नीतिगत चुनौती मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करते हुए उच्चतर वृद्धि के मार्ग की ओर संक्रमण का प्रबंध करने से संबंधित थी, आगे की अवधि के लिए 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के निकट नियंत्रित करने तथा 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में मध्यावधि उद्देश्य के अनुरूप नीति और अवधारणाएं बनाने के प्रयास के साथ सुदृढ़तापूर्वक मूल्य स्थिरता तथा सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के पक्ष में नीति तैयार करने को तरजीह दी गई। इस लक्ष्य के प्रति यह संकेत किया गया कि रिज़र्व बैंक स्थिति की मांग के अनुसार अपने सभी नीतिगत लिखतों का लचीलेपन से उपयुक्त उपयोग करके चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा।

2.63 2007-08 की मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही तक हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो गई जो विलंबित और संचयी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों तथा आपूर्ति प्रबंधन हेतु राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों के मिश्रित प्रभाव को दर्शाता है। इन उपायों का मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर भी हितकर प्रभाव पड़ा। तथापि जुलाई 2007 की पहली तिमाही की समीक्षा में यह जोड़ा गया कि मौद्रिक प्रबंधन को मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के प्रति संभावित खतरे के रूप में पण्य मूल्यों, विशेष तौर पर तेल के मूल्यों, में घटबढ़, आस्ति मूल्यों के बढ़े हुए स्तर तथा उत्पादकों के बीच मूल्य निर्धारण शक्ति के पुनरोदय के प्रति चौकस रहने की जरूरत है। तथापि, समीक्षा में 2007-08 में मुद्रास्फीति की संभावना को अपरिवर्तित रखा गया।

2.64 मध्यावधि समीक्षा 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य तथा पहली तिमाही की समीक्षा में निर्धारित रुख के साथ जारी रही जिसमें मूल्य स्थिरता एवं सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर बल दिया गया था तथा ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था जो अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं निवेश संबंधी मांग का समर्थन करे ताकि वृद्धि की गति जारी रखी जा सके। समष्टि आर्थिक तथा, विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऋण के प्रसार करने और वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय बाजारों में ऋण की गुणवत्ता तथा व्यवस्थित स्थितियों पर पुनः बल दिया गया। मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली वैश्विक एवं देशी स्थिति पर सभी संभव उपयुक्त उपायों के साथ तेजी से रेस्पांड करने की तैयारी को दुहराते हुए, मध्यावधि समीक्षा में सामान्य रूप से बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं तथा वित्तीय बाजारों में गतिविधियों के प्रति अपरंपरागत नीतिगत प्रतिसादों को

देखते हुए अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए सभी संभव विकल्पों का आश्रय लेने का संकल्प किया गया।

2.65 मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही की समीक्षा (जनवरी 2008) में मध्यावधि समीक्षा की नीति संबंधी रुख पर पुनः बल देना जारी रखते हुए सब-प्राइम संकट के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों को नोट किया गया तथा समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए सभी उपलब्ध लिखतों के साथ अधिक सघन निगरानी और त्वरित प्रतिसाद की जरूरत पर बल दिया गया। जहां यह माना गया कि भारत में वित्तीय स्थिरता को वैश्विक गतिविधियों से कोई दृश्य अथवा तात्कालिक खतरा नहीं है, इसने जोखिम को यथासंभव कम करने के लिए समय पर, त्वरित और उपयुक्त उपाय करने की तैयारी पर बल देने के साथ निरंतर परंतु अधिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया। तदनुसार, इसने मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता तथा घरेलू स्थिति पर निगरानी रखने की जरूरत पर बल दिया ताकि उपयुक्त परंपरागत और अपरंपरागत दोनों उपायों के साथ तुरंत रेस्पांड किया जा सके।

2.66 अप्रैल 2008 में जारी 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने 2008-09 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.0 से 8.5 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान लगाया। वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकलन को देखते हुए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में मौद्रिक नीति के समग्र रुख को मोटे तौर पर निम्नानुसार सूचित किया गया (i) इस प्रकार का मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थितियों को उच्च प्राथमिकता दे और वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायक हो; (ii) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के समूह तथा घरेलू स्थिति के प्रति निरंतर आधार पर उपयुक्त परंपरागत और अपरंपरागत दोनों प्रकार के उपायों से त्वरित रेस्पांड करना; तथा (iii) वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए रोजगार प्रधान क्षेत्रों के लिए ऋण की गुणवत्ता तथा ऋण की सुपुर्दगी पर विशेष रूप से बल देना।

2.67 मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में यह नोट किया गया कि अप्रैल 2008 में वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य की घोषणा के बाद आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में वैश्विक एवं देशी गतिविधियों ने, विशेष रूप से मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और अवधारणाओं के रूप में, मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ने की ओर संकेत किया। वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने तथा देशी मुद्रास्फीति तेरह वर्ष की ऊंचाई पर पहुंच जाने के माहौल में, समीक्षा में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि मुद्रास्फीति वैश्विक संभावना के लिए सबसे बड़ी जोखिम के रूप में उभरी है क्योंकि यह पूरे

विश्व में बहुत ऊंचे स्तरों पर पहुंच गई है जैसाकि पिछले दो दशकों में आम तौर पर नहीं देखा गया था। इस प्रकार ऊंचे स्तरों से मुद्रास्फीति को कम करना तथा मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर करने को मौद्रिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। इसमें नोट किया गया कि आगे देखने पर वैश्विक तथा उससे अधिक देशी कारक मौद्रिक प्रबंधन को कड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए कई स्तरों पर नीतिगत कार्रवाइयां अपेक्षित हैं। तदनुसार वास्तविक नीतिगत प्रयास यह होगा कि मुद्रास्फीति को उस समय प्रचलित 11.0-12.0 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 31 मार्च 2009 तक 7.0 प्रतिशत के निकट लाया जाए। समस्त मांग प्रबंधन और ऊपर वर्णित आपूर्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए, देशी अथवा बाह्य आघातों को छोड़कर 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 8.0 प्रतिशत पर लगाया गया। इस पृष्ठभूमि में अप्रैल 2008 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए उल्लेख के अनुसार मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखा गया।

2.68 मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं तथा बड़े पूंजी अंतर्वाहों के कारण प्रचलित मौद्रिक/चलनिधि स्थितियों के संभावित प्रभाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने समय-समय पर मौद्रिक उपायों की घोषणा की। तदनुसार, 5 मार्च 2007 से यह निर्णय लिया गया कि दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण को अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए पर सीमित किया जाए ताकि प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखने तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के जरिए सक्रिय चलनिधि प्रबंधन को सुकर बनाया जा सके। तथापि, प्रचलित समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एलएएफ के तहत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई। 2006-07 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 4 चरणों में 100 आधार अंक बढ़ाकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनडीटीएल के 5.00 प्रतिशत से 6.00 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर में परिवर्तनों के कारण बैंकिंग प्रणाली पर पहले दौर में 2006-07 में 27,500 करोड़ रुपए का चलनिधि प्रभाव पड़ा। 2007-08 में सीआरआर में चार चरणों में 150 आधार अंकों की और वृद्धि कर उसे 7.50 प्रतिशत कर दिया गया तथा बैंकिंग प्रणाली पर पहले दौर में 47,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा। 2008-09 में अब तक सीआरआर में 150 आधार अंकों की और वृद्धि की गई तथा रिपो दर 125 आधार अंक बढ़ाकर दोनों को 9.00 प्रतिशत कर दिया गया। रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने एमएसएस के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए अधिकतम सीमा संशोधित कर उसे 1,10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 अगस्त 2007 को 1,50,000 करोड़ रुपए तथा 4 अक्टूबर 2007 को और बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए तथा 7 नवंबर 2007 को 2,50,000 करोड़ रुपए कर दिया ताकि मौद्रिक नीति के संचालन में रिजर्व बैंक को अधिक युक्तिचालन प्रदान किया जा सके।

आरक्षित मुद्रा सर्वेक्षण

2.69 मार्च 2008 के अंत में साल-दर-साल आरक्षित मुद्रा में 30.9 प्रतिशत का विस्तार एक साल पहले के 23.7 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर था। सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, एक साल पहले के 18.9 प्रतिशत की तुलना में आरक्षित मुद्रा का विस्तार 25.3 प्रतिशत था। 2007-08 में आरक्षित मुद्रा में व्यापक घटबढ़ देखा गया जो मुख्य रूप से सीआरआर में वृद्धि के कारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में घटबढ़, मांग और मीयादी देयताओं में व्यापक वृद्धि तथा रिजर्व बैंक के बाजार परिचालनों को दर्शाता है। रिजर्व बैंक के पास रखी बैंकों की जमाराशियों में 2006-07 के 45.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 66.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्रोत पक्ष में, आरक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों द्वारा चालित थी जो पिछले साल में हुई 1,64,601 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 3,70,550 करोड़ रुपए (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) बढ़ गई। 2007-08 में केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में घटबढ़ ने मोटे तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन परिचालनों तथा रिजर्व बैंक के पास रखी सरकारी जमाराशियों में घटबढ़ को दर्शाया। एमएसएस के तहत रिजर्व बैंक के निष्प्रभावीकरण संबंधी परिचालनों के कारण रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशियां बढ़ गई। रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार का अधिशेष नकदी शेष भी बढ़ गया। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की धारिताएं एलएएफ के तहत चलनिधि के अंतर्वेशन के कारण बढ़ गईं। इन गतिविधियों को दर्शाते हुए केंद्र को रिजर्व बैंक का निवल ऋण 2006-07 में हुई 3,024 करोड़ रुपए से की गिरावट की तुलना में 2007-08 में 1,16,772 करोड़ रुपए कम हो गया (सारणी 2.23)।

2008-09 की गतिविधियां

2.70 एक साल पहले के 24.1 प्रतिशत की तुलना में 15 अगस्त 2008 को साल-दर-साल आरक्षित मुद्रा की वृद्धि 31.1 प्रतिशत थी। सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, आरक्षित मुद्रा की वृद्धि एक साल पहले के 14.2 प्रतिशत की तुलना में 24.3 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) में एक साल पहले हुई 2, 40, 618 करोड़ रु. की वृद्धि की तुलना में साल-दर-साल 2,51,201 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। केंद्र के रिजर्व बैंक के निवल ऋण में एक साल पहले हुई 78,935 करोड़ रुपए की गिरावट की तुलना में साल-दर-साल 6,125 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

मौद्रिक सर्वेक्षण

2.71 पिछले साल के 21.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में स्थूल मुद्रा (एम₃) की वृद्धि साल-दर-साल 20.8 प्रतिशत थी (सारणी 2.24 तथा चार्ट II.5)। बैंकों की सकल जमाराशियों में हुई वृद्धि में

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.23 : आरक्षित मुद्रा - घट-बढ़

(राशि करोड़ रूप में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़					
		2006-07	2007-08	2007-08			
				ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा	9,28,417	1,35,935 (23.7)	2,19,427 (30.9)	11,630	60,688	26,606	1,20,503
घटक (1+2+3)							
1. संचालन में करेंसी	5,90,901	73,523 (17.1)	86,702 (17.2)	16,866	-13,297	46,781	36,352
2. रिजर्व बैंक के पास बैंकरो की जमा	3,28,447	61,784 (45.6)	1,31,152 (66.5)	-4,800	75,464	-19,369	79,857
3. रिजर्व बैंक के पास (अन्य) जमा	9,069	628 (9.1)	1,573 (21.0)	-436	-1,479	-806	4,294
स्रोत (1+2+3+4-5)							
1. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को निवल ऋण उसमें से : केंद्र को (i+ii+iii+iv-v)	-1,14,636	-3,024	-1,16,772	-21,825	-55,588	-65,078	25,719
i. ऋण तथा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
ii. भा.रि.बैंक द्वारा धारित राजकोषीय बिल	0	0	0	0	0	0	0
iii. भा.रि.बैंक की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता	1,14,593	26,763	17,421	-34,284	4,019	20,874	26,812
iv. भा.रि.बैंक की रूपए सिक्कों की धारिता	132	-143	121	128	20	3	-31
v. केंद्र सरकार की जमाराशियां	2,29,361	29,644	1,34,314	-12,330	59,627	85,956	1,062
2. भा.रि.बैंक द्वारा बैंकों तथा वाणिज्य क्षेत्र को ऋण	6,378	1,990	-2,794	-6,450	-1,256	848	4,064
3. भा.रि.बैंक का एनएफईए	12,36,130	1,93,170 (28.7)	3,69,977 (42.7)	-2,745	1,9,430	94,681	1,58,610
जिसमें से : एफसीए, पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित		1,64,601	3,70,550	47,728	1,18,074	1,00,888	1,03,860
4. सरकार की जनता के प्रति मुद्रा देयताएं	9,324	-493	1,064	166	354	312	232
5. भा.रि.बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2,10,206	54,556	33,187	-42,812	3,145	3,448	69,406
जापन :							
निवल देशी आस्तियां	-3,07,713	-57,234	-1,50,550	14,375	-58,743	-68,075	-38,107
एलएएफ - रिपो (+)/रिवर्स रिपो(-)	50,350	36,435	21,165	-32,182	9,067	16,300	27,980
खुले बाजार में निवल बिक्री #*		5,125	-5,923	1,246	1,560	-3,919	-4,810
केन्द्र का अधिशेष	76,686	1,164	26,594	-34,597	15,376	54,765	-8,950
एमएसएस के अंतर्गत संग्रहण	1,68,392	33,912	1,05,419	19,643	48,855	31,192	5,728
निवल खरीद (+) / बिक्री (-), प्राथमिक व्यापारियों से		1,18,994	3,12,054	38,873	1,01,814	87,596	83,771
एनएफईए / रिजर्व मुद्रा @	133.1	122.2	133.1	119.8	125.8	133.4	133.1
एनएफईए / मुद्रा @	209.2	171.8	209.2	165.7	193.6	194.3	209.2
एनएफईए : निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां		एफसीए : विदेशी मुद्रा आस्तियां		एलएएफ : चलनिधि समायोजन सुविधा			
*: अंकित मूल्य पर		# : राजकोषीय बिलों को छोड़कर		@ : प्रतिशत, अवधि के अंत में			
नोट:							
1. ति.4 के आंकड़े 31 मार्च के हैं और अन्य तिमाहियों के आंकड़े रिपोर्ट करने के लिए नियत शुक्रवार के हैं।							
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।							

कुछ कमी आई। 2007-08 में मांग जमाराशियों में एक वर्ष पहले की 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि (साल-दर-साल) हुई। मीयादी जमाराशियों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में) हुई। फिर भी, मीयादी जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंक जमाराशियों पर ऊंचे ब्याज दरों तथा पांच वर्ष और अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर कर लाभ का परिणाम थी। 2007-08 में डाक जमाराशियों में हुए उपचय में नवंबर 2007 तक काफी कमी आई। इसके अलावा, दिसंबर 2007 में अल्पबचत स्कीमों से निवल बहिर्वाह हुआ। डाक जमाराशियों में रुचि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2007 में कतिपय डाक जमाराशियों के लिए कर

लाभ सहित कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की। तथापि निवल बहिर्वाह जून 2008 तक, जब तक के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, जारी रहा।

2008-09 की गतिविधियां

2.72 साल-दर-साल आधार पर स्थूल मुद्रा (एम₃) में वृद्धि एक साल पहले के 21.8 प्रतिशत की तुलना में 1 अगस्त 2008 को 19.6 प्रतिशत थी। प्रमुख घटकों में समस्त जमाराशियों में एक साल पहले के 23.1 प्रतिशत की तुलना में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्रोत पक्ष में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में 1 अगस्त 2008 को 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष के 23.5 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक थी, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में उनका निवेश एक साल पहले के 12.9 प्रतिशत की तुलना में 15.4 प्रतिशत बढ़ गया।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.24 : मौद्रिक संकेतक

(राशि करोड़ रूप में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़			
		31 मार्च 2007		31 मार्च 2008	
		समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. आरक्षित मुद्रा	9,28,417	1,35,935	23.7	2,19,427	30.9
II. संकीर्ण मुद्रा (एम ₁)	11,50,953	1,39,714	16.9	1,84,864	19.1
III. व्यापक मुद्रा (एम ₃)	40,06,722	5,86,548	21.5	6,90,629	20.8
क) जनता के पास मुद्रा	5,67,476	69,786	16.9	84,571	17.5
ख) कुल जमाराशियाँ	34,30,177	5,16,134	22.3	6,04,485	21.4
i) माँग जमाराशियाँ	5,74,408	69,300	17.1	98,721	20.8
ii) मीयादी जमाराशियाँ	28,55,769	4,46,834	23.5	5,05,765	21.5
जिसमें से : अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ	56,935	8,185	13.8	-10,525	-15.6
IV. एनएम्	40,32,699	5,77,013	21.0	7,08,101	21.3
जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं से माँग मीयादी निधीयन	1,06,504	2,692	3.2	20,668	24.1
V. क) एल ₁	41,47,550	5,88,644	20.6	7,07,403	20.6
जिसमें से : डाक जमाराशियाँ	1,14,851	11,631	11.2	-698	-0.6
ख) एल ₂	41,50,482	5,88,644	20.6	7,07,403	20.5
ग) एल ₃	41,76,450	5,90,718	20.5	7,08,674	20.4
VI. व्यापक मुद्रा के प्रमुख स्रोत					
क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii)	9,07,077	69,177	9.0	72,842	8.7
i) सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	-1,13,209	-4,176		-1,15,632	
जिसमें से केन्द्र को	-1,14,636	-3,024		-1,16,772	
ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण	10,20,286	73,353	9.7	1,88,474	22.7
ख) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	25,69,912	4,37,074	25.8	4,39,834	20.6
ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	12,95,131	1,86,985	25.7	3,81,952	41.8
घ) जनता के प्रति साकार की मुद्रा देयता	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9
ङ) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	7,74,723	1,06,195	22.9	2,05,063	36.0
जापन:					
अ.वा.बैंकों की सकल जमाराशि	31,96,939	5,02,885	23.8	5,85,006	22.4
अ.वा.बैंकों का खाद्येतर ऋण	23,17,515	4,18,282	28.5	4,32,846	23.0
अ.वा.बैं. : अनुसूचित वाणिज्य बैंक एनएम् ₃ निवास आधारित व्यापक मुद्रा समुच्चय है तथा एल ₁ , एल ₂ तथा एल ₃ मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष डॉ. या.वे. रेड्डी, 1998) की सिफारिशों के अनुसार संकलित चलनिधि संबंधी समुच्चय है। चलनिधि समुच्चयों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। एल ₁ = एनएम् ₁ + डाकघर बचत बैंकों की चुनिंदा जमाराशियाँ। एल ₂ = एल ₁ + मीयादी उधारदात्री संस्थाओं तथा पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मीयादी जमाराशियाँ + वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली गई मीयादी उधारियाँ + वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमाराशि प्रमाणपत्र। एल ₃ = एल ₂ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियाँ। टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं। जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां पिछले माह के उपलब्ध आंकड़े दुहराए गए हैं।					

बैंक ऋण

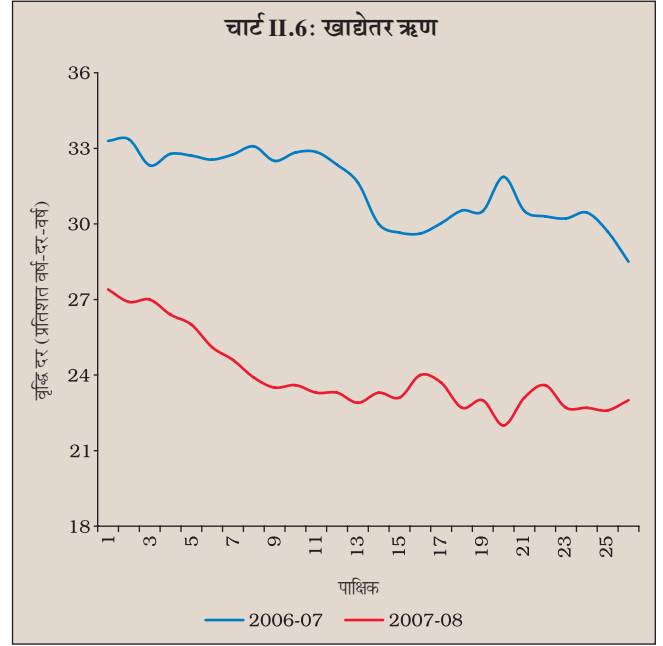
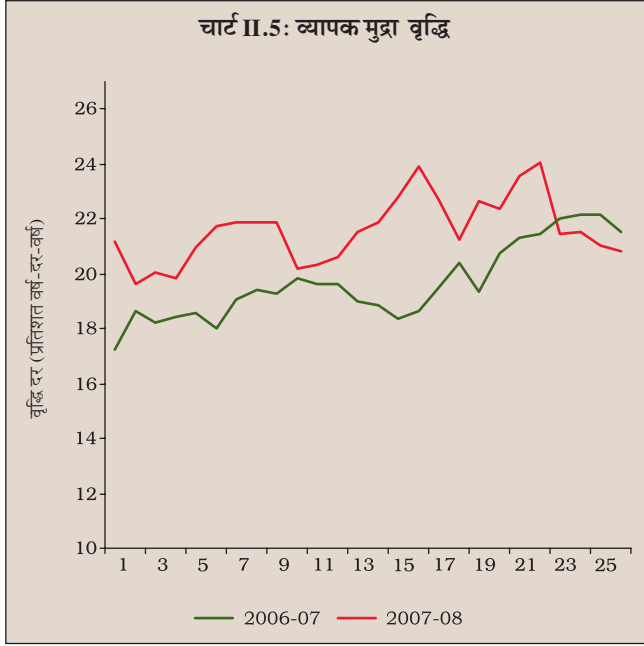
2.73 बैंक ऋण की मांग में 2007-08 में कमी आई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया खाद्येतर ऋण मार्च 2008 के अंत में 23.0 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ा, जो एक साल पहले के 28.5 प्रतिशत की तुलना में न्यूनतर था (सारणी 2.25 तथा चार्ट II.6)। 2007-08 में एसएलआर प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों के निवेश में एक साल पहले के 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 22.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि (साल-दर-साल) हुई।

2008-09 की गतिविधियां

2.74 1 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार, खाद्येतर ऋण में एक वर्ष पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में साल-दर-साल 26.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों

में किये गये निवेश में एक वर्ष पहले के 12.5 प्रतिशत की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2.75 सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी जानकारी से यह पता चलता है कि मार्च 2008 तक साल-दर-साल आधार पर सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में सर्वाधिक वृद्धि (31.1 प्रतिशत) दर्ज की गई, जिसके बाद उद्योग (25.0 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (18.8 प्रतिशत) तथा वैयक्तिक ऋण (10.7 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 के दौरान, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में साल-दर-साल वृद्धि (मई 2008 तक) बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गई। मई 2008 के अंत में सेवा क्षेत्र को ऋण में सर्वाधिक वृद्धि (31.3 प्रतिशत) दर्ज की गई, जिसके बाद उद्योग (26.9 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (19.3 प्रतिशत) तथा वैयक्तिक ऋण (15.9 प्रतिशत) का स्थान था। औद्योगिक ऋण में वृद्धि मुख्यतः मूलभूत सुविधा (पावर,



सड़क, बंदरगाह और दूरसंचार), पेट्रोलियम, वस्त्र, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, इंजीनियरिंग, वाहन और निर्माण उद्योगों के कारण हुई। वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए ऋण में उल्लेखनीय कमी आई, हालांकि यह अभी भी कई अन्य क्षेत्रों की ऋण वृद्धि की तुलना में अधिक था(सारणी 2.26)।

2.76 बैंकों से प्राप्त ऋण के अलावा, कंपनी क्षेत्र ने निधियन संबंधी अपनी जरूरतें पूंजी बाजार, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा निधियों के आंतरिक रूप से सृजन जैसे विभिन्न बैंकेतर स्रोतों से पूरी कीं। 2007-08 के दौरान देशी इक्विटी निर्गमों के जरिए जुटाए गए संसाधन (48,153 करोड़ रुपये) एक साल पहले की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक थे। 2007-08

सारणी 2.25 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रूप में)

मद	28 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़ (साल-दर-साल)			
		30 मार्च 2007 को		28 मार्च 2008 को	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत					
1. सकल जमाराशि	31,96,939	5,02,885	23.8	5,85,006	22.4
2. वित्तीय संस्थाओं से मांग / मीयादी वित्तपोषण	1,06,504	2,692	3.2	20,668	24.1
3. विदेशी मुद्रा में लिए गए अपतटीय ऋण	44,451	2,071	6.9	12,546	39.3
4. पूंजी	43,770	1,461	4.5	9,695	28.5
5. आरक्षित निधि	2,28,852	23,613	16.3	60,126	35.6
निधियों का उपयोग					
1. बैंक ऋण	23,61,914	4,24,112	28.1	4,30,724	22.3
जिसमें से: खाद्येतर ऋण	23,17,515	4,18,282	28.5	4,32,846	23.0
2. सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9,71,715	74,062	10.3	1,80,199	22.8
क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9,58,661	75,316	10.7	1,82,603	23.5
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	13,053	-1,255	-7.5	-2,405	-15.6
3. गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश	1,70,609	5,114	3.8	30,155	21.5
4. विदेशी मुद्रा आस्तियां	31,189	15,260	35.1	-27,564	-46.9
5. भा.रि.बैंक के पास शेष राशि	2,57,122	53,161	41.8	76,900	42.7
टिप्पणी : आंकड़े अर्न्तम हैं।					

सारणी 2.26 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(राशि करोड़ रूप में)

क्षेत्र	23 मई 2008 को बकाया राशि	वार्षिक घट-बढ़			
		2007-08*		2008-09**	
		समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4 तक)	2,174,767	365,814	26.4	422,418	24.1
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	264,787	54,038	32.2	42,745	19.3
उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	858,515	141,280	26.4	182,075	26.9
लघु उद्योग	176,282	26,387	29.5	60,398	52.1
वैयक्तिक ऋण	528,046	87,944	23.9	72,607	15.9
गृह निर्माण	262,486	41,066	21.6	31,735	13.8
मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम	42,220	6,237	19.0	3,128	8.0
क्रेडिट कार्ड बकाया राशि	26,596	4,411	45.0	12,375	87.0
शिक्षा	21,352	4,903	46.5	5,914	38.3
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8,297	1,661	23.2	-534	-6.0
सेवाएं	523,249	82,551	26.1	124,821	31.3
परिवहन परिचालक	35,248	7,922	45.5	9,927	39.2
प्रोफेशनल व अन्य सेवाएं	31,942	8,999	56.8	7,108	28.6
व्यापार	122,438	23,319	28.4	16,902	16.0
भूसंपदा ऋण	61,045	19,010	69.7	14,750	31.9
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	71,974	12,401	38.7	27,549	62.0
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	739,964	120,463	23.9	114,666	18.3
उद्योग (लघु, मध्यम, बड़े)	858,515	141,280	26.4	182,075	26.9
खाद्य प्रसंस्करण	50,493	6,758	22.1	13,126	35.1
वस्त्र	93,916	19,223	32.9	16,259	20.9
कागज एवं कागज के उत्पाद	13,826	2,243	24.5	2,435	21.4
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आणविक ईंधन	47,289	9,884	51.6	18,250	62.8
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	65,397	6,511	14.2	12,982	24.8
रबर, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद	11,116	1,938	28.0	2,261	25.5
लोहा तथा इस्पात	78,834	13,554	27.2	15,460	24.4
अन्य धातु तथा धातु के उत्पाद	25,112	5,447	36.3	4,658	22.8
सभी अभियांत्रिकी	52,551	8,553	25.1	9,959	23.4
वाहन, वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपस्कर	30,015	5,267	28.6	6,324	26.7
रत्न तथा आभूषण	24,826	2,572	12.3	1,403	6.0
निर्माण	26,082	6,632	49.2	5,959	29.6
इंफ्रास्ट्रक्चर	203,331	35,292	32.6	59,811	41.7

* : 26 मई 2006 की तुलना में 25 मई 2007।

** : 25 मई 2007 की तुलना में 23 मई 2008।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं। आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक, जिसका 31 मार्च 2007 को इंडियन ओवरसीज बैंक में विलय हो गया था, के आंकड़े भी शामिल हैं।

के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के जरिए किए गए निवल संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करके किया गया संग्रहण पिछले साल के निर्गम की तुलना में लगभग तीन गुना था। 2007-08 के दौरान चुनिंदा गैर वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के करोत्तर लाभ की वृद्धि में पिछले साल की तुलना में कुछ कमी होने के बावजूद, निधियों के आंतरिक सृजन से कंपनी क्षेत्र की निधीयन संबंधी जरूरतों को समर्थन मिलना जारी रहा। 2007-08 के दौरान अमरीकी निक्षेपागार रसीद (एडीआर) तथा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर) के जरिए इक्विटी निर्गमों के रूप में जुटाए गए संसाधन (13,023 करोड़ रुपये) एक साल पहले की तुलना में 20 प्रतिशत कम थे (सारणी 2.27)।

मूल्य की स्थिति

2.77 2007-08 के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति आम तौर पर अधिक रही, जो विशेषकर उभरते बाजारों में खाद्य और ईंधन की उच्चतर कीमतों तथा सुदृढ़ मांग स्थितियों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, मार्च 2008 में हेडलाइन मुद्रास्फीति एक साल पहले के क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत की तुलना में यूएस में 4.0 प्रतिशत, यूके में 2.5 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत रही। मूल मुद्रास्फीति भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ बनी रही। यूएस में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (अनाज और ऊर्जा को छोड़कर) एक साल पहले के 2.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 में 2.4 प्रतिशत थी। ओईसीडी देशों में उपभोक्ता

सारणी 2.27 : उद्योग के लिए निधियों के चुनिंदा स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	2006-07	2007-08
1	2	3
अ. उद्योग को बैंक ऋण #	1,46,890	1,74,566
आ. गैर बैंकों से कंपनियों को प्रवाह		
1 पूंजी निर्गम (i+ii)	29,178	51,479
i) गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ (क+ख)	29,178	48,962
क) बांड / डिबेंचर	585	809
ख) शेयर	28,593	48,153
ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी कंपनियाँ	0	2,517
2. एडीआर / जीडीआर निर्गम	16,184	13,023
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	1,04,046	1,60,221
4. वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम	5,145	14,903
इ. मूल्य हास प्राक्धान +	37,095	40,664
ई. करोत्तर लाभ +	1,11,107	1,34,291

+ : आंकड़े चुनिंदा गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय चुनिंदा परिणामों पर आधारित हैं।

: आंकड़े चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

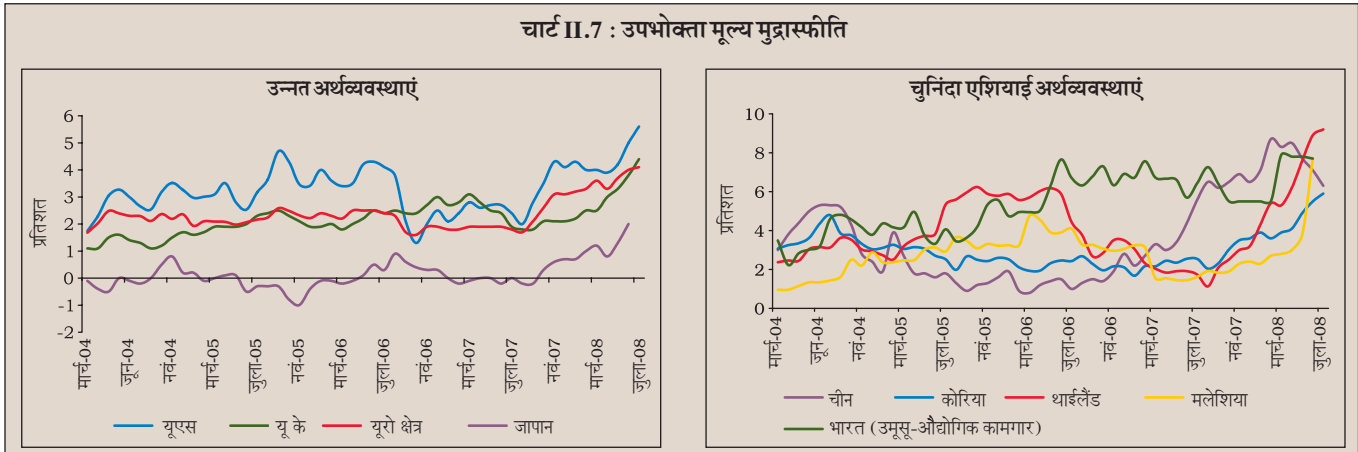
- टिप्पणी :**
1. आंकड़े अनंतिम हैं।
 2. पूंजी निर्गमों का आंकड़ा सकल निर्गमों से संबंधित है जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं। पूंजी निर्गमों में बैंकों के निवेश के लिए वे आंकड़े समायोजित नहीं किए गए हैं जो उल्लेखनीय नहीं हैं।
 3. एडीआर/जीडीआर के निर्गमों के आंकड़ों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं।
 4. बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंकड़ों में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

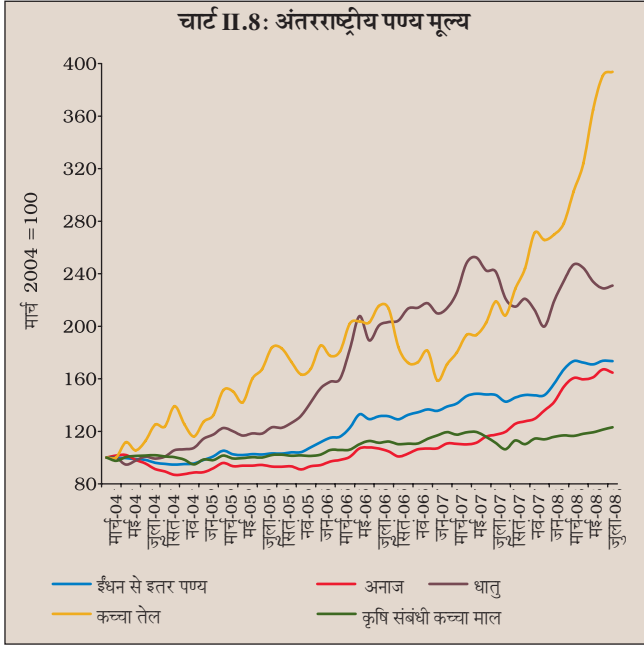
मूल्य मुद्रास्फीति (अनाज और ऊर्जा को छोड़कर) एक साल पहले की तरह मार्च 2008 में 2.1 प्रतिशत थी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, मार्च 2008 में हेडलाइन मुद्रास्फीति चीन में 8.3 प्रतिशत (एक साल पहले 3.3 प्रतिशत), कोरिया में 3.9 प्रतिशत (2.2 प्रतिशत) तथा थाईलैंड में 5.3 प्रतिशत (2.0 प्रतिशत) पर सुदृढ़ थी (चार्ट II.7)। 2008-09 में अब तक कई विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में और तेजी आई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर जुलाई 2008 में यूएस में 5.6 प्रतिशत, यूके में 4.4

प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत हो गई। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई 2008 में चीन में 6.3 प्रतिशत, कोरिया में 5.9 प्रतिशत और थाईलैंड में 9.2 प्रतिशत थी।

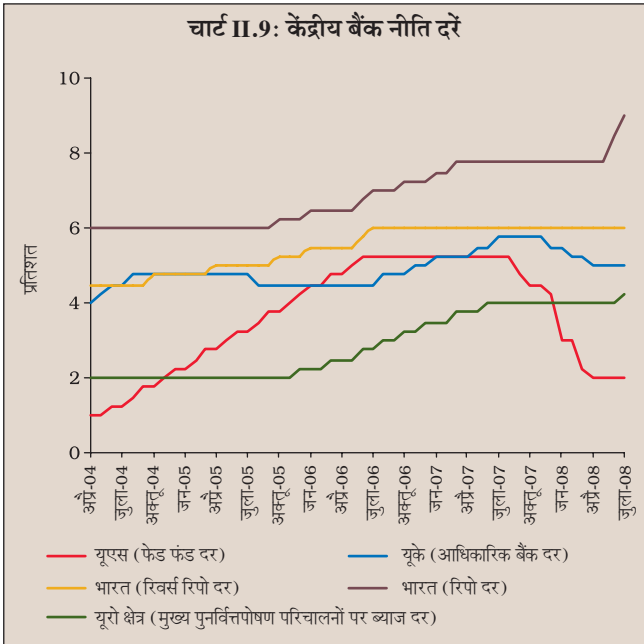
2.78 2007-08 के दौरान अनाज और कच्चे तेल के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि की अगुआई में वैश्विक पण्य मूल्यों में तेजी आई (चार्ट II.8)। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, जो मांग-आपूर्ति संतुलन की सख्त स्थिति, भूराजनैतिक तनाव, प्रमुख मुद्राओं के प्रति अमरीकी डालर के कमजोर होने तथा निवेशकों और वित्तीय बाजार के खिलाड़ियों की बढ़ी हुई रुचि को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान, अमरीका में कच्चे तेल के स्टॉक में आयी तीव्र गिरावट के कारण 13 मार्च 2008 को यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चे तेल की कीमतें 110.2 अमरीकी डालर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उसके बाद तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता यूएस में मंदी की गहराती हुई चिंताओं के कारण कुछ नरम होने के बाद कीमतें पुनः बढ़कर 3 जुलाई 2008 को 145.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं परंतु 19 अगस्त 2008 तक वे कम होकर 114.4 अमरीकी डालर रह गईं। 2007-08 के दौरान, विशेष तौर पर दूसरी छमाही में, मांग (उपभोग मांग तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे खाद्येतर उपयोगों के लिए मांग दोनों) में वृद्धि तथा प्रमुख फसलों के कम स्टॉक के कारण तथा अंशतः कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में मौसम संबंधी बाधाओं के कारण गेहूं, चावल और तिलहन/ खाद्य तेल की अगुआई में अनाज की कीमतों में तेजी आई। इन कारकों को दर्शाते हुए मार्च 2008 में गेहूं, चावल, सोयाबीन, सोयाबीन तेल और पाम तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में क्रमशः 121 प्रतिशत, 86 प्रतिशत, 79 प्रतिशत, 106 प्रतिशत और 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें वर्ष के दौरान मोटे तौर पर एक दायरे में रहीं, जो परंपरागत आयातक देशों में उच्चतर उत्पादन को दर्शाता है। धातुओं की कीमतों में जून-दिसंबर 2007 में न्यूनतर आयात मांग तथा आपूर्ति में कुछ सुधार को दर्शाते हुए कुछ कमी देखी गई, परंतु जनवरी-मार्च 2008 में उसमें पुनः वृद्धि हो गई।

चार्ट II.7 : उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति





2.79 मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कई केन्द्रीय बैंकों ने यूएस सबप्राइम संकट से उत्पन्न ऋण की तंगी के व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को पूर्वनिवारित करने के लिए मौद्रिक नरमी का आश्रय लिया (चार्ट II.9)। 2007-08 की पहली छमाही में अमरीका ने नीति दर को अपरिवर्तित रखा। तथापि, यह देखने के बाद कि ऋण की स्थितियों को सख्त बनाने तथा आवास संकुचन को गंभीर बनाने का असर अगली कुछ तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है, फेडरल ओपेन मार्केट समिति (एफओएमसी) ने 30 अप्रैल 2008 को फेडरल निधि दर के लिए अपने लक्ष्य को 25 आधार अंक कम करके 2.00 प्रतिशत कर दिया,



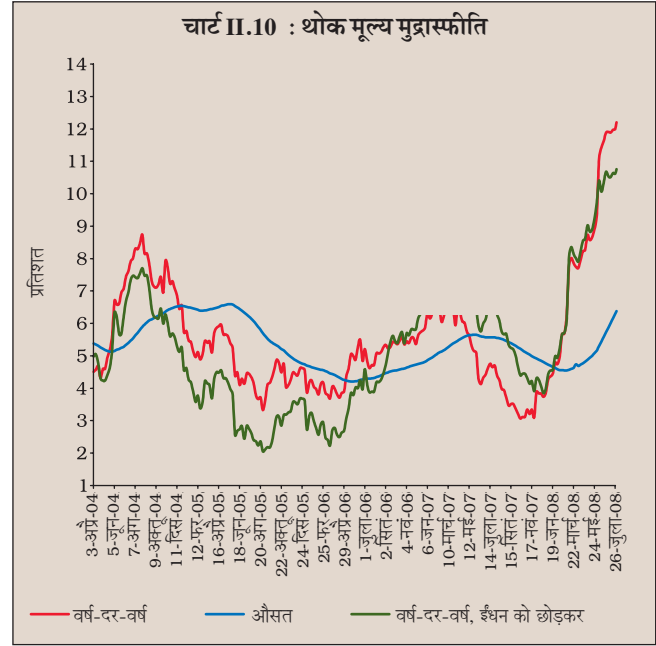
और इस प्रकार सितंबर 2007 से, जब दरों में कटौती करने की शुरुआत की गई, संचयी कटौती बढ़कर 325 आधार अंक हो गई। बाजार में चलनिधि में सुधार लाने के लिए, अगस्त 2007 से बट्टे की दर भी 400 आधार अंक कम कर 2.25 प्रतिशत के स्तर पर ला दी गई। 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी नवीनतम बैठक में एफओएमसी ने नोट किया कि ऊर्जा एवं कुछ अन्य पण्यों की कीमतों में पहले की गई वृद्धि से प्रेरित होकर मुद्रास्फीति बढ़ गई है और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं के कुछ संकेतकों को बढ़ा दिया गया है। समिति के अनुसार, यद्यपि इस साल के अंत में और अगले साल मुद्रास्फीति में कमी आने की आशा है, तथापि संभावना अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में फेडरल निधि दर को 2.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसने मुद्रास्फीति की संभावना के प्रति ऊर्ध्वमुखी जोखिम को देखते हुए मई-जुलाई 2007 में नीति दर को 50 आधार अंक बढ़ा दिया था, ने दिसंबर 2007 से अपनी नीति दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर 10 अप्रैल 2008 को उसे 5.0 प्रतिशत कर दिया ताकि मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को बढ़ाते हुए इस वर्ष लक्ष्य से अधिक मुद्रास्फीति की ऊर्ध्वमुखी जोखिमों को वित्तीय बाजारों में विघटन की अधोमुखी जोखिमों से संतुलित किया जा सके; जो अर्थव्यवस्था में ऐसी मंदी ला सकती है जो काफी तेजी से मुद्रास्फीति को लक्ष्य से नीचे ले जा सकती है। यह नोट करते हुए कि सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष के अंत में शिखर पर पहुंच जाएगी और उसके बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर गिरकर 2 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर आना शुरू कर देगी, एमपीसी ने उसके बाद नीति दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया। यूरो क्षेत्र में, 6 जून 2007 को नीति दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि करने के बाद, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने उसके बाद 2007-08 के दौरान नीति दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया क्योंकि उसने सोचा कि मध्यावधि में मूल्य स्थिरता के प्रति जोखिम अत्यंत प्रबल मुद्रा और ऋण वृद्धि के संदर्भ में ऊर्ध्वमुखी होगी। तथापि, मुद्रास्फीति दरें बढ़ते रहने और पहले सोची गई अवधि की तुलना में अधिक लंबी अवधि के लिए उसके मूल्य स्थिरता से सुसंगत स्तर के ऊपर रहने को मद्देनजर रखते हुए, ईसीबी ने 9 जुलाई 2008 से अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की ताकि व्यापक आधार वाले दूसरे दौर के प्रभावों को निवारित किया जा सके तथा मध्यावधि में मूल्य स्थिरता के प्रति बढ़ती हुई ऊपरी जोखिमों को प्रभावहीन किया जा सके।

2.80 बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने फरवरी 2007 से अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा, जब उसने अपनी असंपाश्विकीकृत रात भर की मांग दर (जो मार्च 2006 से मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है) 25 आधार अंक बढ़ाकर उसे 0.50 प्रतिशत कर दिया। बीओजे के अनुसार, आगामी महीनों में मुद्रास्फीति कुछ उच्चतर रहने की आशा है, परंतु उसके बाद उसमें क्रमिक रूप से कमी आ सकती है। कुछ समय तक मंदा रहने के बाद आर्थिक वृद्धि के क्रमिक रूप से सामान्य वृद्धि मार्ग पर वापस आने की आशा है क्योंकि पण्यों के मूल्य एक स्तर पर आ गए हैं तथा विदेशी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के

चरण से बाहर आ गई हैं। अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ कनाडा, जिसने प्रारंभ में जुलाई 2007 में अपनी नीति दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की थी, दिसंबर 2007 से इसमें 150 आधार अंकों की कटौती कर 22 अप्रैल 2008 को उसे 3.0 प्रतिशत कर दिया, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया ने अपनी नीति दर को बढ़ाना जारी रखा - मई 2006 से 175 आधार अंक बढ़ाकर 5 मार्च 2008 को 7.25 प्रतिशत कर दिया।

2.81 सुदृढ़ वृद्धि तथा तेल, अनाज और अन्य पण्य की उच्चतर कीमतों के कारण प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव अधिक बना रहा। मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के कारण चीन में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 8.3 प्रतिशत हो गई। बाद में जुलाई 2008 में यह कुछ नरम होकर 6.3 प्रतिशत रह गई। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की समस्या दूर करने के लिए तथा मुद्रा और ऋण विस्तार पर दबाव कम करने के लिए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी) ने अप्रैल 2006 से बेंचमार्क एक वर्षीय उधार दर 189 आधार अंक बढ़ाकर 21 दिसंबर 2007 को 7.47 प्रतिशत कर दिया। चलनिधि समेटने हेतु अपने निजी बिलों को लगातार जारी करने के अलावा, पीबीसी ने जुलाई 2006 तथा जून 2008 के बीच नकदी आरक्षित अनुपात 1000 आधार अंक बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया ताकि बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके और मुद्रा तथा ऋण की उपयुक्त वृद्धि का मार्गदर्शन किया जा सके। अन्य उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ कोरिया ने 9 अगस्त 2007 से 5.0 प्रतिशत पर अपनी नीति दर अपरिवर्तित रखने के बाद, मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार की अस्त-व्यस्तता तथा अमरीका की आर्थिक मंदी के कारण भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में मौजूद अनिश्चितता को देखते हुए, 7 अगस्त 2008 को दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 5.25 प्रतिशत कर दिया। मौद्रिक नीति समिति के नवीनतम आकलन के अनुसार, तेल की ऊंची कीमतों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की गति बढ़ गई है (एक साल पहले के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2008 में यह 5.9 प्रतिशत हो गई है) तथा कुछ समय तक मुद्रास्फीति काफी अधिक बने रहने की संभावना है। थाईलैंड में एमपीसी, जिसने 18 जुलाई 2007 से (जब नीति दर में 25 आधार अंकों की अंतिम कटौती की गई थी) अपनी नीति दर को 3.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था, दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर 16 जुलाई 2008 को उसे 3.50 प्रतिशत कर दिया। एमपीसी के अनुसार, मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो निजी क्षेत्र के विश्वास को प्रभावित करेगा जिससे आगे चलकर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और कठिन हो जाएगा तथा यह दीर्घावधि में थाई अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करेगा।

2.82 भारत में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति राजकोषीय वर्ष के आरंभ में 6.4 प्रतिशत थी, जो नरम



होकर 13 अक्टूबर 2007 को 3.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई, जो आंशिक तौर पर प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और कुछ विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में कमी और आधार प्रभाव को दर्शाता है। नवंबर 2007 में 3 प्रतिशत के आसपास रहने के बाद दिसंबर 2007 के आरंभ से मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और 29 मार्च 2008 को वह 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मुख्यतः अनाज, सब्जी, तिलहन, कच्ची रूई और लौह अयस्क, ईंधन समूह जैसी प्राथमिक वस्तुओं तथा खाद्य तेल/खली जैसी विनिर्मित वस्तुओं एवं धातुओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। वार्षिक औसत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति दर (52 सप्ताहों का औसत) मई 2007 तक बढ़ने के बाद जून 2007 के आरंभ से घटनी शुरू हुई तथा वह 29 मार्च 2008 को समाप्त सप्ताह में 4.7 प्रतिशत (एक साल पहले 5.4 प्रतिशत) पर पहुंच गई। 2007-08 के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.1-8.0 प्रतिशत के दायरे में रही (चार्ट II.10)।

2.83 प्रमुख समूहों में साल-दर-साल प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति अप्रैल 2007 के आरंभ के 12.2 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2007 के अंत तक 3.7 प्रतिशत के अंतर-वर्ष निम्न स्तर पर पहुंच गई, जो खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से दालों, फलों और सब्जियों तथा अंडों, मछली और मांस के मूल्य में नरमी तथा आधार प्रभाव को दर्शाती है। बाद में मुख्यतः फल, सब्जी, तिलहन, कच्ची रूई और लौह अयस्क की अगुवाई में प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति 29 मार्च 2008 को बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई। गेहूँ के मूल्य में एक साल पहले की 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सामान्य मानसून के कारण उत्पादन में सुधार तथा सरकार द्वारा लिए गए आपूर्ति पक्ष संबंधी उपायों को दर्शाता है। एक साल पहले के 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में दालों की कीमतों में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो उत्पादन में सुधार को दर्शाता

हाल की आर्थिक गतिविधियां

है। एक साल पहले की 5.7 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर चावल के मूल्य में साल-दर-साल 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहनों की कीमतों में उच्चतर मांग, निम्नतर देशी रबी उत्पादन तथा बढ़ते हुए वैश्विक मूल्यों के कारण एक साल पहले की 31.6 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर साल-दर-साल 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्ची रूई की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मूल्य में घटबढ़ के अनुरूप एक साल पहले हुई 21.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल 14.0 प्रतिशत अधिक थीं (सारणी 2.28)।

2.84 ईंधन समूह की मुद्रास्फीति, जो अंशतः आधार प्रभाव तथा पिछले साल ईंधन (पेट्रोल और डीजल) की कीमतों में कटौती को दर्शाते

हुए जून-नवंबर 2007 में ऋणात्मक थी, नवंबर 2007 के मध्य से सकारात्मक होकर 29 मार्च 2008 को 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। नवंबर 2007 से शुरू हुई वृद्धि का कारण नफ्था, फर्नेस ऑइल, अविएशन टर्बाइन फ्यूएल (एटीएफ) तथा बिटूमेन जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और वृद्धि तथा 15 फरवरी 2008 से पेट्रोल और डीजल की देशी कीमतों में क्रमशः दो रूप प्रति लीटर तथा एक रूप प्रति लीटर का ऊर्ध्वगामी संशोधन है (जो लगभग एक साल के अंतर के बाद आया जब मूल्यों में कटौती की गई)। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों (भारतीय बास्केट) में लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह फरवरी 2007 के

सारणी 2.28 : भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

पण्य	भार	2006-07 (मार्च 31)		2007-08 (मार्च 29)	
		मुद्रास्फीति	भा.अं.	मुद्रास्फीति	भा.अं.
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.0	5.9	100.0	7.7	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएं	22.0	10.7	39.0	9.7	28.2
खाद्यान्न वस्तुएं	15.4	8.0	20.8	6.5	13.2
i. चावल	2.4	5.7	2.1	9.1	2.5
ii. गेहूं	1.4	7.3	1.8	5.1	1.0
iii. दालें	0.6	12.5	1.4	-1.9	-0.2
iv. सब्जियां	1.5	1.2	0.3	14.2	2.3
v. फल	1.5	5.7	1.8	4.1	1.0
vi. दूध	4.4	8.4	5.8	8.7	4.7
vii. अंडे, मछली और मांस	2.2	9.4	3.8	2.4	0.8
खाद्योत्तर वस्तुएं	6.1	17.2	15.6	11.4	8.8
i. कच्ची रूई	1.4	21.9	3.5	14.0	2.0
ii. तिलहन	2.7	31.6	11.0	20.3	6.7
iii. गन्ना	1.3	1.1	0.3	-0.4	-0.1
खनिज	0.5	17.5	2.6	49.9	6.2
2. ईंधन, पावर, लाइट और लुब्रिकेंट	14.2	1.0	4.0	6.8	18.9
i. खनिज तेल	7.0	0.5	1.1	9.3	15.1
ii. विद्युत	5.5	2.3	2.8	1.5	1.4
iii. कोयला खनन	1.8	0.0	0.0	9.8	2.5
3. विनिर्मित उत्पाद	63.8	6.1	57.3	7.3	52.8
i. खाद्य उत्पाद	11.5	6.1	10.5	9.4	12.4
जिनमें से: चीनी	3.6	-12.7	-6.6	1.1	0.4
खाद्य तेल	2.8	14.1	4.7	20.0	5.5
ii. सूती वस्त्र	4.2	-1.0	-0.6	-6.8	-2.8
iii. मानव निर्मित रेशे	4.4	3.9	1.3	2.8	0.7
iv. रसायन और रासायनिक उत्पाद	11.9	3.6	7.1	6.0	8.7
जिनमें से: उर्वरक	3.7	1.8	1.0	5.1	2.0
v. मूल धातु, संमिश्र धातु और धातु उत्पाद	8.3	11.3	17.4	20.3	25.2
जिनमें से: लोहा और इस्पात	3.6	8.1	6.0	34.2	20.1
vi. गैर धातु खनिज उत्पाद	2.5	9.0	3.6	6.4	2.0
जिनमें से: सीमेंट	1.7	11.6	3.2	5.1	1.1
vii. मशीनरी और मशीन औजार	8.4	8.1	8.6	3.5	2.9
जिनमें से: इलेक्ट्रिकल मशीनरी	5.0	12.9	6.7	4.8	2.0
viii. परिवहन उपकरण और पुर्जे	4.3	2.0	1.2	3.9	1.7
ज्ञापन:					
खाद्य वस्तुएं (मिश्रित)	26.9	7.3	31.2	7.7	25.6
थो.मू.सू., खाद्य वस्तुओं को छोड़कर	73.1	5.5	68.8	7.8	74.4
थो.मू.सू., ईंधन को छोड़कर	85.8	7.4	96.0	8.0	81.1

भा.अं.: भारित अंशदान।

56.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च 2008 में 99.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई। जहां पेट्रोल और डीजल के देशी मूल्यों में आंशिक समायोजन किया गया है, सरकार द्वारा सामाजिक चिंताओं के आधार पर अप्रैल 2002 से केरोसिन के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं जबकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के दाम, जो 2007-08 में अपरिवर्तित रहे, जून 2008 में आंशिक रूप से बढ़ा दिए गए। कच्चे तेल के उच्चतर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को देशी मूल्यों में पूर्णतः अंतरित करने को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए उपलब्ध इन उत्पादों के लिए सब्सिडी योजनाओं को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया है।

2.85 विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में साल-दर-साल नरमी आई और वह चीनी, वस्त्र और अलौह धातुओं के मूल्यों में कमी तथा आधार प्रभावों की अगुवाई में साल के शुरु के 6.4 प्रतिशत से कम होकर 24 नवंबर 2007 तक 3.5 प्रतिशत (एक साल पहले 5.3 प्रतिशत) हो गई। बाद में विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति बढ़कर 29 मार्च 2008 तक 7.3 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः खाद्य तेल/खली, बेसिक भारी अकार्बनिक रसायन और बेसिक धातु और संमिश्र धातुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। इन पण्यों ने 29 मार्च 2008 को समग्र डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में कुल मिलाकर लगभग 41 प्रतिशत का अंशदान किया। विनिर्मित उत्पाद समूह के भीतर 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल आधार पर खाद्य तेल (20.0 प्रतिशत), खली (27.2 प्रतिशत), रसायन और रासायनिक उत्पाद (6.0 प्रतिशत), सीमेंट (5.1 प्रतिशत), लोहा और इस्पात (34.2 प्रतिशत) तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी (4.8 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान अलौह धातुओं की देशी कीमतों में गिरावट आई, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में, जिनमें दिसंबर 2007 तक नरमी आई थी, जनवरी - मार्च 2008 में वृद्धि हुई। लोहा और इस्पात के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल में आई तेजी के अनुरूप वृद्धि हुई। तथापि मोटे तौर पर निर्माण क्षेत्र से सुदृढ़ मांग तथा सीमेंट उद्योग में क्षमता उपयोग की उच्च दरों के कारण सीमेंट की देशी कीमतों में वृद्धि हुई। देशी खाद्य तेल और खली की कीमतों में तेजी स्थिर देशी उत्पादन, बढ़ी हुई मांग और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को दर्शाती है।

2.86 मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2007-08 के दौरान कई राजकोषीय और आपूर्ति संवर्धक उपाय शुरू किए। 3 अप्रैल 2007 को सरकार ने पोर्टलैंड सीमेंट के आयात को काउंटरवेलिंग ड्यूटी तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त करने का निर्णय लिया; पहले इसे जनवरी 2007 में मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया था। सरकार ने खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई उपाय भी किए। सरकार ने अप्रैल 2007 में पाम तेल पर सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत अंकों की एकसमान तथा जुलाई 2007 में

विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 5-10 प्रतिशत अंकों के दायरे में कटौती की। इसने सभी खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत का अतिरिक्त काउंटरवेलिंग शुल्क भी हटा लिया। शून्य शुल्क पर गेहूं का आयात, जो दिसंबर 2006 के अंत तक उपलब्ध था, और बढ़ाकर दिसंबर 2007 के अंत तक कर दिया गया। दालों के आयात पर सीमा शुल्क कम कर 8 जून 2006 को शून्य कर दिया गया तथा शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता अवधि, जो आरंभ में मार्च 2007 तक उपलब्ध थी, पहले बढ़ाकर अगस्त 2007 तक तथा बाद में मार्च 2009 तक कर दी गई। 22 जून 2006 से दालों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई तथा दालों के निर्यात पर मनाही की वैधता अवधि, जो आरंभ में मार्च 2007 के अंत तक लागू थी, बढ़ाकर मार्च 2008 के अंत तक कर दी गई। मार्च 2008 में चावल पर सीमा शुल्क 70 प्रतिशत से कम कर मार्च 2009 तक शून्य प्रतिशत कर दिया गया; कच्चे तेल तथा परिशोधित खाद्य तेल पर सीमा शुल्क 40-75 प्रतिशत के दायरे से कम कर 20.0-27.5 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2008 से तत्काल प्रभाव से सभी खाद्य तेलों के निर्यात की मनाही की गई। इन उपायों से मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं नियंत्रित करने में मदद मिलने की आशा थी।

2.87 हेडलाइन डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.7 प्रतिशत तथा एक साल पहले के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 9 अगस्त 2008 को साल-दर-साल 12.6 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन समूह तथा विनिर्मित उत्पाद समूह मुद्रास्फीति बढ़कर 9 अगस्त 2008 को क्रमशः 11.8 प्रतिशत (9.5 प्रतिशत), 18.0 प्रतिशत (-2.0 प्रतिशत) तथा 10.9 प्रतिशत (4.7 प्रतिशत) हो गई। औसत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति दर एक साल पहले के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 9 अगस्त 2008 को 6.6 प्रतिशत हो गई।

2.88 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में साल-दर-साल घटबढ़ के आधार पर मुद्रास्फीति में जनवरी 2008 तक नरमी आई जो मुख्यतः खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी को दर्शाती है। बाद में अनाज और ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ गई। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की विभिन्न मापों को मार्च 2007 के 6.7- 9.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के दौरान 6.0-7.9 प्रतिशत के दायरे में न्यूनतर रखा गया। अलग-अलग आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापों में खाद्य समूह मुद्रास्फीति मार्च 2007 के 10.9-12.2 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2008 में 7.8-9.3 प्रतिशत के दायरे में आ गई। ईंधन समूह मुद्रास्फीति मार्च 2007 में 3.2-6.9 प्रतिशत के दायरे में थी जो बढ़कर मार्च 2008 में 4.6-8.0 प्रतिशत के दायरे में आ गई तथा इसने भी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की वृद्धि में अंशदान किया। “विविध समूह” की प्रतिनिधि सेवाओं की कीमतें 2007-08 के दौरान आम तौर पर तेज बनी रहीं (सारणी 2.29)। जून 2008 में सीपीआइ मुद्रास्फीति 7.3-8.8 प्रतिशत के दायरे में रही।

सारणी 2.29 : उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - मुख्य समूह

(प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़)

सीपीआइ मान	भार	मार्च-04	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	जून-07	सितं.-07	दिसं.-07	मार्च-08	जून-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सीपीआइ - आइडब्ल्यू (आधार : 2001 = 100)#										
सामान्य	100.0	3.5	4.2	4.9	6.7	5.7	6.4	5.5	7.9	7.7
खाद्य समूह	46.2	3.1	1.6	4.9	12.2	8.1	8.7	6.2	9.3	-
पान, सुपारी आदि	2.3	4.2	2.1	3.1	4.4	9.6	10.3	10.3	10.9	-
ईंधन और लाइट	6.4	6.5	4.9	-2.9	3.2	1.6	2.3	2.3	4.6	-
आवास	15.3	3.9	20.4	6.6	4.1	4.1	4.0	4.0	4.7	-
वस्त्र, बिस्तर आदि	6.6	2.1	2.3	3.0	3.7	4.4	5.3	3.5	2.6	-
विविध	23.3	3.2	3.9	4.6	3.3	4.0	4.0	4.7	6.3	-
सीपीआइ - यूएनएमई (आधार : 1984-85 = 100)										
सामान्य	100.0	3.4	4.0	5.0	7.6	6.1	5.7	5.1	6.0	7.3
खाद्य समूह	47.1	3.0	2.2	5.3	10.9	7.7	7.7	6.2	7.8	9.6
ईंधन और लाइट	5.5	3.2	9.6	1.9	6.4	7.2	7.0	5.4	4.6	5.3
आवास	16.4	5.2	7.5	5.5	5.6	5.6	4.9	4.7	4.0	3.8
वस्त्र, बिस्तर आदि	7.0	2.6	2.0	2.9	3.6	4.3	4.0	4.1	4.3	3.4
विविध	24.0	2.8	4.4	5.1	4.4	3.7	3.2	3.8	4.8	6.6
सीपीआइ - एएल (आधार : 1986-87 = 100)										
सामान्य	100.0	2.5	2.4	5.3	9.5	7.8	7.9	5.9	7.9	8.8
खाद्य समूह	69.2	1.6	2.2	5.5	11.8	8.8	8.8	6.2	8.5	9.6
पान, सुपारी आदि	3.8	4.7	-1.3	6.6	5.7	9.1	11.1	11.3	10.4	11.2
ईंधन और लाइट	8.4	3.0	3.0	4.3	6.9	7.4	7.2	6.3	8.0	8.9
वस्त्र, बिस्तर आदि	7.0	4.1	2.5	2.2	3.5	2.7	1.9	1.3	1.8	3.1
विविध	11.7	2.7	5.5	5.5	6.8	6.7	5.5	5.2	6.1	6.5
सीपीआइ - आरएल (आधार : 1986-87 = 100)										
सामान्य	100.0	2.5	2.4	5.3	9.2	7.5	7.6	5.6	7.6	8.7
खाद्य समूह	66.8	1.9	1.9	5.8	11.5	8.5	8.8	6.2	8.2	9.6
पान, सुपारी आदि	3.7	4.7	-1.0	6.3	5.7	9.3	11.6	11.5	10.6	10.9
ईंधन और लाइट	7.9	3.0	2.9	4.0	6.9	7.4	7.2	6.3	8.0	8.9
वस्त्र, बिस्तर आदि	9.8	3.4	2.8	2.7	3.1	2.6	2.1	2.6	2.8	4.1
विविध	11.9	3.0	5.5	5.2	6.3	6.2	5.3	5.0	6.2	6.8
ज्ञापन :										
डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति (अवधि के अंत में)		4.6	5.1	4.1	5.9	4.4	3.4	3.8	7.7	11.9
# : जनवरी 2006 से पहले के आंकड़े पुरानी श्रृंखला (आधार : 1982 = 100) पर आधारित हैं।										
आइडब्ल्यू : औद्योगिक कामगार										
यूएनएमई : शहरी श्रमेतर कर्मचारी										
एएल : कृषि श्रमिक										
आरएल : ग्रामीण श्रमिक										

V. वित्तीय बाजार

2.89 वर्ष 2007-08 के दौरान मांग मुद्रा बाजार और इक्विटी बाजार में अस्थिरता के कुछ दौर को छोड़कर भारतीय वित्तीय बाजार काफी सीमा तक व्यवस्थित बने रहे। सरकार के नकद शेष तथा पूंजी प्रवाह में घटबढ़ वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों के मुख्य वाहक थे। मुद्रा बाजार के संपाश्र्विकृत खंड में ब्याज दरें वर्ष के दौरान मांग दर के अनुरूप परंतु उससे नीचे बनी रहीं (सारणी 2.30)।

चलनिधि प्रबंधन - 2007-08

2.90 रिजर्व बैंक ने प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखने के लिए सीआरआर तथा खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ), एलएएफ,

एमएसएस तथा अपने पास उपलब्ध अन्य नीतिगत लिखतों का लचीलेपन से उचित उपयोग कर 2007-08 के दौरान चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी, ताकि विशेष रूप से उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण की सभी वैध अपेक्षाएं मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप पूरी हो सकें। परिचालनात्मक रूप में इससे चलनिधि की स्थितियों को इस तरह से नियंत्रित किया गया ताकि मुद्रा बाजार में रात भर की दरें कमोबेश नीतिगत दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक एलएएफ कारीडोर के भीतर बनी रहें।

2.91 2007-08 के दौरान न सिर्फ केंद्र सरकार के नकद शेषों में घटबढ़ के कारण अपितु साल के अधिकतर भाग में अधिक तथा अस्थिर पूंजी आवकों के कारण भी चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन को बाजार

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.30 : देशी वित्तीय बाज़ार - एक नज़र में

वर्ष/ माह	माँग मुद्रा		सरकारी प्रतिभूतियां		विदेशी मुद्रा			चलनिधि प्रबंध			ईक्विटी			
	औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत माँग दर* (प्रतिशत)	औसत 10- वर्षीय आय @ (प्रतिशत)	सरकारी प्रतिभूतियों में औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक अंतर बैंक कारोबार (मिलियन अमरीकी डॉलर)	औसत विनि-मय दर (रुपए प्रति अमरी- की डॉलर)	रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिक्री (-) / खरीद (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	औसत वायदा प्रीमियम 3-माह (प्रति- शत)	औसत एम एस एस # (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक (एल ए एफ) बकाया (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बी एस ई कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक एन एस ई कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत बी एस ई सेसेक्स**	औसत एस एंड पी सी एन एक्स निफ्टी **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006-07														
अप्रैल	16,909	5.62	7.45	3,685	17,712	44.95	4,305	1.31	25,709	46,088	4,860	9,854	11,742	3,494
मई	18,074	5.54	7.58	3,550	18,420	45.41	504	0.87	26,457	59,505	4,355	9,155	11,599	3,437
जून	17,425	5.73	7.86	2,258	15,310	46.06	0	0.73	31,845	48,610	3,131	6,567	9,935	2,915
जुलाई	18,254	5.86	8.26	2,243	14,325	46.46	0	0.83	36,936	48,027	2,605	5,652	10,557	3,092
अगस्त	21,294	6.06	8.09	5,788	15,934	46.54	0	1.22	40,305	36,326	2,867	5,945	11,305	3,306
सितंबर	23,665	6.33	7.76	8,306	18,107	46.12	0	1.31	40,018	25,862	3,411	6,873	12,036	3,492
अक्टूबर	26,429	6.75	7.65	4,313	16,924	45.47	0	1.67	41,537	12,983	3,481	6,919	12,637	3,649
नवंबर	25,649	6.69	7.52	10,654	20,475	44.85	3,198	2.07	38,099	9,937	4,629	8,630	13,416	3,869
दिसंबर	24,168	8.63	7.55	5,362	19,932	44.64	1,818	3.20	38,148	-1,713	4,276	8,505	13,628	3,910
जनवरी	22,360	8.18	7.71	4,822	21,171	44.33	2,830	4.22	39,553	-10,738	4,380	8,757	13,984	4,037
फरवरी	23,254	7.16	7.90	4,386	20,298	44.16	11,862	3.71	40,827	648	4,676	9,483	14,147	4,084
मार्च	23,217	14.07	8.00	2,991	25,992	44.03	2,307	4.51	52,944	-11,858	3,716	7,998	12,858	3,731
2007-08														
अप्रैल	29,689	8.33	8.10	4,636	29,311	42.15	2,055	6.91	71,468	-8,937	3,935	8,428	13,478	3,947
मई	20,476	6.96	8.15	4,442	25,569	40.78	4,426	4.58	83,779	-6,397	4,706	9,885	14,156	4,184
जून	16,826	2.42	8.20	6,250	30,538	40.77	3,192	2.59	83,049	1,689	4,537	9,221	14,334	4,222
जुलाई	16,581	0.73	7.94	13,273	32,586	40.41	11,428	1.12	82,996	2,230	5,684	12,147	15,253	4,474
अगस्त	23,603	6.31	7.95	6,882	31,994	40.82	1,815	1.59	1,00,454	21,729	4,820	10,511	14,779	4,301
सितंबर	21,991	6.41	7.92	5,859	36,768	40.34	11,867	1.45	1,17,674	16,558	6,156	13,302	16,046	4,660
अक्टूबर	18,549	6.03	7.92	5,890	39,452P	39.51	12,544	1.12	1,58,907	36,665	9,049	20,709	18,500	5,457
नवंबर	20,146	6.98	7.94	4,560	30,677P	39.44	7,827	1.40	1,75,952	-2,742	7,756	18,837	19,260	5,749
दिसंबर	16,249	7.50	7.91	7,704	31,547P	39.44	2,731	1.64	1,64,606	-10,804	8,606	19,283	19,827	5,964
जनवरी	27,531	6.69	7.61	19,182	38,008P	39.37	13,625	2.07	1,59,866	15,692	8,071	19,441	19,326	5,756
फरवरी	22,716	7.06	7.57	12,693	40,441P	39.73	3,884	0.24	1,75,166	-1,294	5,808	13,342	17,728	5,202
मार्च	22,364	7.37	7.69	5,881	38,617P	40.36	2,809	1.25	1,70,285	-8,271	6,166	14,056	15,838	4,769
2008-09														
अप्रैल	19,516	6.11	8.10	6,657	36,710P	40.02	4,325	2.68	1,70,726	26,359	5,773	13,561	16,291	4,902
मई	19,481	6.62	8.04	8,780	31,868P	42.13	148	2.45	1,75,565	11,841	6,084	13,896	16,946	5,029
जून	21,707	7.75	8.42	6,835	38,108P	42.82	-5,229	3.78	1,74,433	-8,622	5,410	12,592	14,997	4,464
जुलाई	24,736	8.76	9.18	5,474	..	42.84	..	6.04	1,72,169	-27,961	5,388	12,862	13,717	4,125

: बाज़ार स्थिरीकरण योजना के साप्ताहिक बकाया का औसत। ... : उपलब्ध नहीं * : दैनिक भारत माँग मुद्रा उधार दरों का औसत।
 ** : दैनिक लेखाबंदी सूचकांकों का औसत। @ : दैनिक लेखाबंदी दरों का औसत। अ : अनंतिम।
 टिप्पणी : स्तंभ 11 में (-) चलनिधि का डाला जाना दर्शाता है, जबकि (+) चलनिधि का शोषण दर्शाता है।

की चलनिधि में गुरुतर घटबढ़ से संतुष्ट रहना पड़ा। पूंजी प्रवाह में वृद्धि से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ फंडामेंटल, हाल के वर्षों में केन्द्रीय बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही समायोजक मौद्रिक नीति तथा उन्नत देशों में सबप्राइम संकट के प्रतिसाद में केन्द्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर चलनिधि का अंतर्वेशन प्रदर्शित होता है। आम तौर पर, केन्द्र सरकार के नकद शेषों में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न चलनिधि प्रबंधन की चुनौतियों तथा बड़े और अस्थिर पूंजी प्रवाह में कई कारकों की वजह से हाल के वर्षों में वृद्धि हो गयी है। पहला, कंपनियों की लाभप्रदता और आय वृद्धि में निरंतर सुधार के कारण प्रत्यक्ष कर वसूलियों में काफी वृद्धि हो गई है, इस प्रकार कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़

गया है। फलस्वरूप हर तिमाही में अग्रिम कर के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी बैंकिंग प्रणाली से बाहर चली जाती है। इस प्रकार के अग्रिम कर अंतर्वाहों का चलनिधि पर बड़ा परन्तु अस्थायी प्रभाव पड़ता है। जहां इस प्रकार के नकदी के बहिर्वाह के समय की पूर्वघोषणा आम तौर पर की जा सकती है, मात्र परिमाण से दैनिक आधार पर अप्रत्याशित अस्थिरता आ सकती है। दूसरे, व्यय पक्ष में पूरे साल सरकारी खर्च के पैटर्न की पूर्वघोषणा उतनी अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। वित्त वर्ष के अंत के आस-पास स्थिति तीव्र हो जाती है; वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्मित के बाद हर साल मार्च के अंत/ अप्रैल के पूर्वार्ध में नकदी शेष का बड़े पैमाने पर उछाड़ देखना अस्वाभाविक नहीं है। तीसरे, पूंजी प्रवाह के समय की पूर्वघोषणा

नहीं की जा सकती क्योंकि वे देशी और बाह्य कारकों के संमिश्र द्वारा चालित होते हैं। चौथे, जब कभी सरकारी नकदी शेष तथा पूंजी प्रवाह साथ-साथ और एक ही दिशा में होते हैं, जैसाकि हाल में अतीत में देखा गया था, चलनिधि आघातों की मात्रा तथा सहवर्ती तौर पर अपेक्षित नीतिगत एवं परिचालनगत प्रतिसादों की मात्रा बढ़ जाती है।

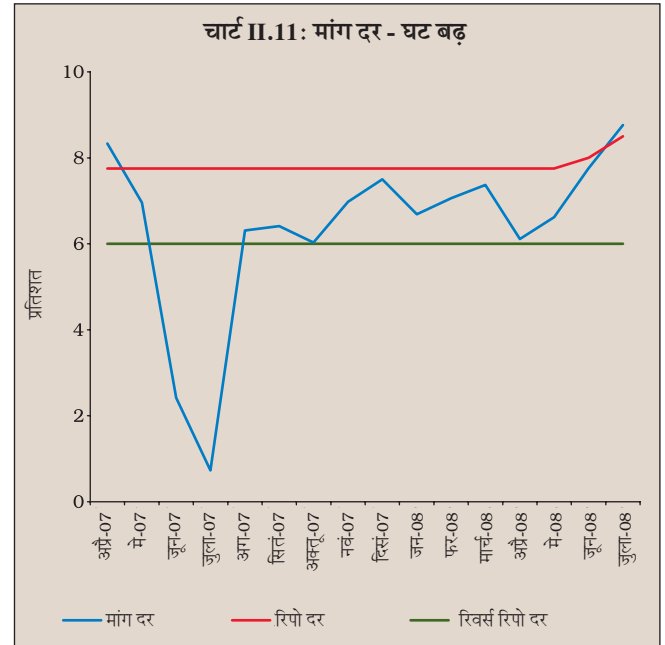
2.92 उक्त पृष्ठभूमि में, 2007-08 में मौद्रिक नीति के संचालन में चलनिधि प्रबंधन की प्राथमिकता बढ़ जाती है। साल के बड़े हिस्से में अधिशेष चलनिधि की स्थिति रहती है, जो सुदृढ़ पूंजी अंतर्वाहों की स्थिति में रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन तथा सरकारी नकदी शेष के आहरण को दर्शाता है, जोकि प्रेरणार्थक कारक बदलने पर चलनिधि की कमी के दौर के साथ विकीर्ण हो गई थी। चलनिधि की स्थिति में ऐसे घटबढ़ के प्रबंधन में रिजर्व बैंक ने सीआरआर, एलएएफ तथा एमएसएस का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। सीआरआर में चरणों में (अप्रैल, अगस्त और नवंबर में) 150 आधार अंकों की वृद्धि कर वर्ष के दौरान⁵ उसे 7.5 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि एमएसएस के तहत बकाया शेष की अधिकतम सीमा 80,000 करोड़ रुपये से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये कर दी गई। पूंजी प्रवाह की मात्रा और अस्थिरता को दर्शाते हुए एमएसएस के तहत किए गए निर्गमों को वर्ष के दौरान लिखत के आकार और प्रकार के रूप में अनुकूलित किया गया। 2007-08 में जहां रिजर्व बैंक द्वारा निवल विदेशी मुद्रा बाजार खरीद की संचयी राशि 3,12,054 करोड़ रुपये के समतुल्य थी, उसी अवधि में एमएसएस के तहत शेष में निवल वृद्धि 1,05,691 करोड़ रुपये की थी।

2.93 2007-08 के दौरान, 4 अप्रैल 2007 से अप्रैल 2007 के मध्य तक, आंशिक तौर पर केंद्र सरकार के नकद शेष में कमी के कारण चलनिधि का दबाव क्रमिक रूप से कम होने के साथ, एलएएफ के जरिए चलनिधि का अंतर्वेश मार्च 2007 के अंत के 29,185 करोड़ रुपये से घटकर 5 अप्रैल 2007 को 1,455 करोड़ रुपये रह गया, जिसके बाद 9-15 अप्रैल 2007 को चलनिधि का अवशोषण किया गया। चूंकि एलएएफ के तहत की गई आशोधित व्यवस्थाओं के अनुसार 5 मार्च 2007 से रिवर्स रिपो के जरिए चलनिधि के अवशोषण की अधिकतम सीमा 3,000 करोड़ रुपए रखी गई, प्रमुख तौर पर चलनिधि का प्रबंधन अप्रैल 2007 में सीआरआर में दो चरणों में हर बार 25 आधार अंकों की वृद्धि कर तथा एमएसएस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम बढ़ाकर किया गया। 2007-08 के लिए बकाया एमएसएस की वार्षिक अधिकतम सीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल 2007 को 1,10,000 करोड़ कर दी गई। 28 मई 2007 से प्रणाली में बड़ी मात्रा में अधिशेष चलनिधि की स्थिति आ गई, जो सरकारी व्यय तथा

रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों में वृद्धि को दर्शाता है। तदनुसार, एलएएफ पटल पर अवशोषण की स्थिति आ गई तथा जून-जुलाई 2007 के दौरान कुछ अवसरों को छोड़कर वह इसी स्थिति में रहा।

2.94 समष्टि आर्थिक तथा समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों को देखते हुए, एलएएफ के दैनिक रिवर्स रिपो पटल पर 3,000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई। 28 नवंबर 2005 को शुरू किए गए दूसरे एलएएफ को भी 6 अगस्त 2007 से हटा लिया गया। मांग दरें, जो गिरकर जून और जुलाई 2007 में कॉरिडोर की निम्नतर सीमा के नीचे चली गई थीं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2007 के दौरान अधिकांशतः रिवर्स रिपो और रिपो दरों के अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर रहीं (चार्ट II.11) (ब्यौरों के लिए अगला खंड देखें)।

2.95 अगस्त और सितंबर 2007 के दौरान, एलएएफ के तहत औसत अवशोषण क्रमशः 21,729 करोड़ रुपये तथा 16,558 करोड़ रुपये थे। एलएएफ के तहत अवशोषित राशि में आयी कमी अगस्त 2007 में सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किए जाने तथा एमएसएस के तहत बाजार परिचालनों के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। बड़े और सतत पूंजी प्रवाहों को देखते हुए, एमएसएस के तहत अधिकतम सीमा को अगस्त 2007 में पुनः बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपया कर दिया गया।



⁵ 2008-09 के दौरान सीआरआर में 150 आधार अंकों की वृद्धि की गई।

2.96 केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेष में गिरावट तथा रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण तीसरी तिमाही के आरंभ में चलनिधि की स्थिति नरम हुई। अक्टूबर 2007 में एलएएफ के तहत दैनिक औसत अवशोषण 36,665 करोड़ रुपए था। त्यौहार के मौसम की मुद्रा संबंधी मांग के कारण सख्ती की संक्षिप्त अवधि के बावजूद, नवंबर 2007 के दूसरे सप्ताह तक चलनिधि की स्थिति नरम रही जो विदेशी पूंजी का आवक बने रहना दर्शाता है। इसके कारण एमएसएस के तहत बकाया राशियों की अधिकतम सीमा में ऊर्ध्वमुखी संशोधन कर उसे 4 अक्टूबर 2007 को 2,00,000 करोड़ रुपए तथा 7 नवंबर 2007 को 2,50,000 करोड़ रुपए करना जरूरी हो गया। सीआरआर को भी 50 आधार अंक बढ़ाकर नवंबर 2007 में 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि, जैसे ही केंद्र सरकार का अतिरिक्त नकदी शेष बढ़ा तथा सीआरआर में वृद्धि लागू हो गई, माह के मध्य से चलनिधि की स्थिति सख्त हो गई। मोटे तौर पर तिमाही अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण दिसंबर 2007 में चलनिधि की स्थिति में सख्ती आई। इसके कारण एलएएफ के जरिए रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी तौर पर चलनिधि का अंतर्वेशन आवश्यक हो गया।

2.97 केंद्र सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष में कमी तथा इस अवधि में बड़े पूंजी प्रवाहों के कारण रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा परिचालनों की वजह से चौथी तिमाही के आरंभ में चलनिधि की स्थिति में कुछ नरमी देखी गई। चलनिधि की विकसित हो रही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएस के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी जनवरी 2008 में शुरू कर दी गई। तथापि, जनवरी 2008 के दूसरे पखवाड़े में रिजर्व बैंक के पास केंद्र का नकदी शेष बढ़ने के साथ अतिरिक्त चलनिधि में गिरावट आई। एलएएफ के जरिए औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अवशोषण जनवरी 2008 में 15,692 करोड़ रुपए था। फरवरी 2008 में, एलएएफ पटल अवशोषण से अंतर्वेशन की ओर चला गया क्योंकि रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार का अतिरिक्त नकदी शेष माह के दूसरे पखवाड़े में बढ़ गया। फरवरी 2008 में औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अंतर्वेशन 1,294 करोड़ रुपए था। चलनिधि की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए माह के मध्य से एमएसएस के तहत कोई नीलामी नहीं की गई। केंद्र के अतिरिक्त नकदी शेष में कटौती तथा रिजर्व बैंक द्वारा ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों की खरीद के कारण मार्च 2008 के आरंभ में चलनिधि की स्थितियों में नरमी आ गई। तथापि, मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण चलनिधि की स्थितियां 17 मार्च 2008 से पुनः सख्त हो गई। मार्च 2008 के मध्य में अग्रिम कर अदायगी अनुसूची तथा बाद में बैंकों की छुट्टियों (20-22 मार्च 2008) को देखते हुए कई बैंकों के अनुरोध पर रिजर्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति को ठीक करने के लिए अतिरिक्त एलएएफ की व्यवस्था करने का निर्णय लिया तथा निम्नलिखित का संचालन किया - (i) 14 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के तहत तीन दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामी; (ii) 17 मार्च 2008 को

अतिरिक्त एलएएफ के तहत सात दिवसीय रिपो नीलामी; तथा (iii) 31 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के तहत दो दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियां।

2.98 2007-08 में पूरे वर्ष के लिए 171 दिन चलनिधि का निवल अवशोषण तथा 75 दिन चलनिधि का निवल अंतर्वेशन (2006-07 में क्रमशः 197 दिन तथा 48 दिन) किया गया। वर्ष के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल बकाया शेष 10,804 करोड़ रुपए के अंतर्वेशन (दिसंबर 2007) से 36,665 करोड़ रुपए के अवशोषण (अक्टूबर 2007) के बीच रहा।

2.99 2007-08 के दौरान मुख्यतः आवधिक मोचनों के कारण रिजर्व बैंक के संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों का स्टॉक घट गया। सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2007 से खुले बाजार परिचालनों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का आश्रय लिया। रिजर्व बैंक के संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन की राशि तक ऐसे परिचालनों का असर चलनिधि पर नहीं पड़ता। 2007-08 में ओएमओ के तहत खरीदी गई भारत सरकार की प्रतिभूतियों की कुल राशि 13,510 करोड़ रुपए थी।

2008-09 में अब तक चलनिधि प्रबंधन

2.100 अप्रैल 2008 के आरंभ से मुख्यतः केंद्र सरकार के नकदी शेषों में काफी कमी के कारण चलनिधि की स्थितियां नरम हुईं। एमएसएस के तहत नीलामियां शुरू की गईं तथा 25 अप्रैल 2008 को एमएसएस के तहत शेष राशि 1,72,444 करोड़ रुपए थी। 25 अप्रैल 2008 को एलएएफ के तहत अवशोषण 32,765 करोड़ रुपए था। चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर रिजर्व बैंक ने सीआरआर में दो चरणों में प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर, जो क्रमशः 26 अप्रैल 2008 तथा 10 मई 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से लागू होगी, उसे 8.0 प्रतिशत करने की घोषणा की। एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अवशोषण अप्रैल 2008 में 26,359 करोड़ रुपए था। चलनिधि की विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा करने पर, 29 अप्रैल 2008 को जारी मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि 24 मई 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से सीआरआर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 8.25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाते हुए मई 2008 में एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण कम होकर 11,841 करोड़ रुपए हो गया। मई 2008 में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी नहीं की गई तथा 30 मई 2008 को एमएसएस के तहत बकाया शेष 1,75,362 करोड़ रुपए था। जून के आरंभ में चलनिधि की स्थितियां नरम हुईं तथा एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण 1-9 जून 2008 के दौरान 15,469 करोड़ रुपए

था। मौजूदा समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने एलएएफ के तहत रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 12 जून 2008 से उसे 8 प्रतिशत कर दिया। बाद में, अग्रिम कर वसूलियों को देखते हुए सरकारी शेष बढ़ने के साथ चलनिधि की स्थिति घाटे में बदल गई तथा जून 2008 में एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 8,622 करोड़ रुपए था। दो चरणों की सीआरआर वृद्धि प्रभावी होने के बाद चलनिधि की स्थिति जून 2008 की तुलना में जुलाई 2008 में और सख्त हो गई। जुलाई 2008 में औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 27,961 करोड़ रुपए था। वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) में निर्धारित मौद्रिक नीति के रख के अनुरूप तथा देशी एवं वैश्विक समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों संबंधी नवीनतम जानकारी के आधार पर, 24 जून 2008 को यह निर्णय लिया गया कि सीआरआर में दो चरणों में हर बार 25 आधार अंकों की वृद्धि कर, जो 5 जुलाई 2008 तथा 19 जुलाई 2008 को आरंभ पखवाड़े से लागू होगी, 50 आधार अंकों की वृद्धि कर दी जाए। उसी दिन (अर्थात् 24 जून 2008 को) रिपो दर में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यांकन को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 29 जुलाई 2008 को जारी मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में तत्काल प्रभाव से रिपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि (बढ़कर 9 प्रतिशत) की तथा 30 अगस्त 2008 से आरंभ पखवाड़े से सीआरआर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 9 प्रतिशत करने की घोषणा की। अगस्त 2008 में चलनिधि की स्थितियां सख्त रहीं तथा 1-22 अगस्त 2008 के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 26,478 करोड़ रुपए था।

2.101 कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के समक्ष उपस्थित चलनिधि के प्रणालीगत प्रभावों तथा अन्य संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के सुचारु रूप से कार्य करने तथा समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए 30 मई 2008 को विशेष बाजार परिचालन (एसएमओ) की घोषणा की। यह परिचालन 5 जून 2008 से शुरू हुआ। एसएमओ के तहत, रिजर्व बैंक ने परिचालन के पहले चरण में किसी एक दिन 1,500 करोड़ रुपए की समग्र अधिकतम सीमा (11 जून 2008 को 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ओर संशोधित) के अधीन, नामोद्दिष्ट बैंकों के माध्यम से उनके अपने खातों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणक कंपनियों द्वारा धारित तेल बांडों की खरीद की। दूसरे चरण में, इसने बाजार विनिमय दर पर नामोद्दिष्ट बैंकों के माध्यम से समतुल्य विदेशी मुद्रा तेल कंपनियों को उपलब्ध कराई। विदेशी मुद्रा तथा बांड लेनदेनों का निपटान साथ-साथ किया गया ताकि चलनिधि का कोई प्रभाव न पड़े। रिजर्व बैंक द्वारा एसएमओ के तहत खरीदे गए तेल बांडों की कुल राशि 19,325 करोड़

रुपए थी। वित्तीय स्थिरता के हित में एसएमओ एक आपवादिक उपाय था। इसे 8 अगस्त 2008 को समाप्त कर दिया गया।

मुद्रा बाजार

मांग मुद्रा बाजार

2.102 चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के प्रभाव को दर्शाते हुए अस्थिरता के कुछ संक्षिप्त दौरों को छोड़कर 2007-08 में मुद्रा बाजार मोटे तौर पर व्यवस्थित बने रहे। 2007-08 के दौरान अंशतः केंद्र सरकार के नकदी शेष में कटौती के कारण 4 अप्रैल 2007 से अप्रैल 2007 के मध्य तक क्रमिक रूप से चलनिधि पर दबाव कम हुआ। इसे दर्शाते हुए मांग दर, जो मार्च 2007 के दूसरे पखवाड़े में रिपो दर से अधिक हो गई थी, क्रमिक रूप से कम होकर 12 अप्रैल 2007 को 3.27 प्रतिशत रह गई। केंद्र सरकार के नकदी शेष में निरंतर कटौती के बावजूद, बाद में अंशतः 30 मार्च 2007 को घोषित नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार अंकों की वृद्धि, जो 14 अप्रैल 2007 तथा 28 अप्रैल 2007 को आरंभ पखवाड़े से लागू होगी, के कारण चलनिधि की स्थितियां सख्त हो गईं। फलस्वरूप मांग दर बढ़ गई तथा अप्रैल 2007 के दूसरे पखवाड़े और मई 2007 के कुछ भाग में वह रिपो दर से अधिक हो गई। 28 मई 2007 से चलनिधि की स्थितियों में काफी नरमी आई, जो सरकारी व्यय में वृद्धि तथा रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों को दर्शाती है। चूंकि एलएएफ के रिवर्स रिपो पटल के तहत अवशोषित की जानेवाली राशि पर दैनिक आधार पर चलनिधि प्रबंधन की आशोधित व्यवस्थाओं के अनुसार 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी, मांग दर जून और जुलाई 2007 में रिवर्स रिपो दर के नीचे बनी रही। वस्तुतः जून और जुलाई 2007 में कई अवसरों पर मांग दर 1 प्रतिशत से नीचे रही और 2 अगस्त 2007 को वह 0.13 प्रतिशत तक नीचे पहुंच गई। 6 अगस्त 2007 से एलएएफ के दैनिक रिवर्स रिपो पटल पर 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा समाप्त करने के साथ मांग दर बढ़ गई परंतु अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2007 के दौरान वह अधिकांशतः रिवर्स रिपो और रिपो दरों के अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर बनी रही। नवंबर 2007 के दूसरे सप्ताह से चलनिधि की स्थितियों में सापेक्षित सख्ती को देखते हुए, मांग/नोटिस मुद्रा बाजार दरें बढ़ गईं तथा वे अनौपचारिक कॉरिडोर की ऊपरी सीमा के आसपास चलती रहीं। इसका मुख्य कारण मुद्रा की त्र्यौहार मौसम की मांग, रिजर्व बैंक के पास सरकार के नकद शेष में वृद्धि तथा 10 नवंबर 2007 को आरंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाना था। दिसंबर 2007 में, मांग/सूचना दर रिपो दर के आस-पास रही तथा दिसंबर 2007 के लिए औसत मांग/सूचना दर 7.50 प्रतिशत थी। अंशतः केन्द्र सरकार के नकद शेषों में कटौती के कारण चलनिधि की स्थितियों में नरमी आने के साथ, मांग दर घट गई तथा वह जनवरी

2008 में अधिकांशतः अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर रही तथा माह के लिए उसका औसत 6.69 प्रतिशत था। फरवरी 2008 में, पिछले माह की तुलना में दर बढ़ गई तथा उसका औसत 7.06 प्रतिशत था। मार्च 2008 में, मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण दूसरे पखवाड़े में रिजर्व बैंक के पास केन्द्र सरकार की नकद शेषराशियां बढ़ने लगीं तथा 15 मार्च 2008 से मांग दर अधिकांशतः रिपो दर के ऊपर रही। मार्च 2008 में औसत मांग दर और बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गई। तथापि, 2007-08 के पूरे वर्ष के लिए औसत मांग दर 2006-07 के 7.22 प्रतिशत की तुलना में 6.07 प्रतिशत पर निम्नतर थी।

2.103 चलनिधि की स्थितियों में नरमी आई, औसत मांग दर घटकर अप्रैल 2008 में 6.11 प्रतिशत रह गई (सारणी 2.30)। अप्रैल-मई 2008 में सीआरआर में की गई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाते हुए, औसत मांग दर मई 2008 में बढ़कर 6.62 प्रतिशत हो गई। जून 2008 में औसत मांग दर बढ़कर 7.75 प्रतिशत हो गई, जो मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण चलनिधि की स्थितियों में सख्ती को दर्शाता है। चलनिधि की स्थितियों में और सख्ती आने के साथ, जुलाई 2008 में औसत मांग दर बढ़कर 8.76 प्रतिशत हो गई।

संपार्श्विकीकृत बाजार

2.104 बैंकेतर प्रतिभागियों को 6 अगस्त 2005 से मांग मुद्रा बाजार से बाहर करने के बाद संपार्श्विकीकृत बाजार - बाजार रिपो (एलएएफ के बाहर) तथा संपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने का दायित्व (सीबीएलओ) - मुद्रा बाजार के एक प्रमुख खंड के रूप में उभरा है। वर्तमान में, संपार्श्विकीकृत खंड मुद्रा बाजार की कुल मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत है। म्यूच्युअल फंड संपार्श्विकीकृत खंड में प्रमुख ऋणदाता हैं, जबकि बैंक और प्राथमिक डीलर (पीडी) इस खंड के प्रमुख उधारकर्ता हैं।

2.105 2007-08 के दौरान, बाजार रिपो (एलएएफ के बाहर) तथा सीबीएलओ खंडों में ब्याज दरें मांग दर के अनुरूप परंतु उसके नीचे रहीं। सीबीएलओ तथा बाजार रिपो खंडों में 2007-08 के दौरान ब्याज दरों का औसत, एक साल पहले के क्रमशः 6.24 प्रतिशत तथा 6.34 प्रतिशत की तुलना में, क्रमशः 5.20 प्रतिशत तथा 5.50 प्रतिशत था। सीबीएलओ तथा बाजार रिपो खंडों में औसत दरें अप्रैल 2008 के क्रमशः 5.05 प्रतिशत तथा 5.48 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2008 में मांग दर में घटबढ़ के अनुरूप 7.78 प्रतिशत तथा 7.99 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.12)।

2.106 मांग/सूचना और मीयादी मुद्रा बाजार में सभी लेनदेनों के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तातय कोट-चालित प्रणाली (एनडीएस-काल) 18 सितंबर 2006 को शुरू की गई। यद्यपि इस प्लेटफार्म पर लेनदेन करना वैकल्पिक है, 86 बैंकों तथा 8 प्राथमिक डीलरों ने अब तक एनडीएस-

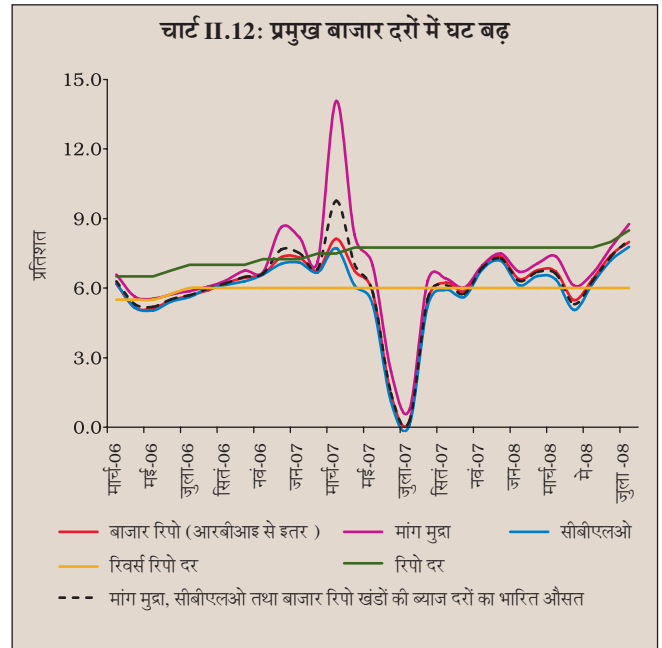
काल की सदस्यता ली है। कुल काल-सूचना लेनदेनों के 75 प्रतिशत से अधिक एनडीएस-काल के जरिए होता है।

वाणिज्यिक पत्र

2.107 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सीपी की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के 17,863 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 32,592 करोड़ रुपए हो गई। 'पट्टादायी और वित्त कंपनियां' सीपी के प्रमुख जारीकर्ता थीं, जिनके पास कुल बकाया राशि का तीन-चौथाई था। मार्च 2008 के अंत में विनिर्माण कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास सीपी की कुल बकाया राशि का क्रमशः 17 प्रतिशत और 8 प्रतिशत था। सीपी पर भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2007 के अंत के 11.3 प्रतिशत से कम होकर अक्टूबर 2007 के अंत में 7.7 प्रतिशत रह गई, जो मुद्रा बाजार में चलनिधि की स्थितियों में सामान्य नरमी को दर्शाता है। उसके बाद, 31 मार्च 2008 को डब्ल्यूएडीआर बढ़कर 10.4 प्रतिशत हो गया। सीपी के निर्गम की सर्वाधिक पसंदीदा अवधि 181 से 365 दिन के दायरे की अवधि थी। 31 जुलाई 2008 को बकाया सीपी की राशि बढ़कर 51,569 करोड़ रुपए हो गई तथा डब्ल्यूएडीआर 10.95 प्रतिशत हो गया।

जमा प्रमाणपत्र (सीडी)

2.108 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का निर्गम 58.5 प्रतिशत बढ़ गया तथा वह मार्च 2007 के अंत के 93,272



करोड़ रुपए से बढ़कर 28 मार्च 2008 को 1,47,792 करोड़ रुपए हो गया। सीडी की बकाया राशि सीडी जारी करनेवाले बैंकों की समस्त जमाराशि का 6.0 प्रतिशत है तथा उसमें काफी अंतर-बैंक घटबढ़ है (कम जमा आधारवाले कुछ छोटे बैंकों के संबंध में प्रतिशत बहुत अधिक है तथा बड़े बैंकों के लिए प्रतिशत कम है)। 2007-08 के दौरान बैंकों ने अपना जमा संग्रहण बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सीडी जारी किया। म्यूच्युअल फंड सीडी के प्रमुख निवेशकर्ता थे। सीडी की भारित औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2007 के अंत के 10.8 प्रतिशत से घटकर, मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 10.0 प्रतिशत होने के पूर्व, अक्टूबर 2007 के अंत में 7.9 प्रतिशत रह गई। बकाया सीडी की राशि बढ़कर 1,64,892 करोड़ रुपए हो गई तथा 18 जुलाई 2008 को डब्ल्यूएडीआर 10.23 प्रतिशत था।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

2.109 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के तहत नए युग के अनुसरण में, 2007-08 के लिए डब्ल्यूएमए सीमाएं साल की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए पर तथा साल की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए रखी गईं। सरकार से परामर्श करके संक्रमणकालीन मुद्दों तथा प्रचलित परिस्थितियों पर विचार करते हुए सीमाओं में संशोधन करने का लचीलापन रिजर्व बैंक के पास था। डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर को अब तक की तरह रिपो दर के साथ जोड़ना जारी रहा। केंद्र के पास राजकोषीय वर्ष के आरंभ में 50,092 करोड़ रुपए का बड़ा अतिरिक्त शेष था, जो तेजी से समाप्त हो गया तथा 27 अप्रैल 2007 तक घाटे में बदल गया जो राज्यों द्वारा भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश में तीव्र कटौती, प्रत्याशित से अधिक खर्च और राष्ट्रीय अल्पबचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत न्यूनतर वसूलियों को दर्शाता है। 17-18 मई 2007 के दो दिनों की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 17 जून 2007 तक सरकार का नकदी शेष घाटे में रहा। 30 मई 2007 को नकद घाटा 20,000 करोड़ रुपए की डब्ल्यूएमए सीमा को पार कर गया तथा 8 जून 2007 तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बना रहा। 6-27 जून 2007 के दौरान छः अवसरों पर 27,500 करोड़ रुपए के 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों के अतिरिक्त निर्गम, उक्त कैलेंडर के बाहर 12 जून 2007 को 5,000 करोड़ रुपए की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी, अप्रैल-जून तिमाही के लिए अग्रिम कर अंतर्वाह तथा भारत सरकार के खजाना बिलों में राज्यों द्वारा निवेश शुरू किए जाने के फलस्वरूप 18 जून 2007 से सरकारी शेष अधिशेष की स्थिति में आ गया। 29 जून 2007 को 35,531 करोड़ रुपए के नकदी

बहिर्गम सहित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अंतरित किए जाने के साथ, सरकार का नकद शेष पुनः घाटे की स्थिति में चला गया तथा 8 अगस्त 2007 तक इसी स्थिति में रहा। 9 अगस्त 2007 को रिजर्व बैंक से अधिशेष के अंतरण के बाद, भारत सरकार का नकद शेष अधिशेष की स्थिति में वापस आ गया। सरकार ने पिछले वर्ष के विपरीत, जब उसने किसी ओवरड्राफ्ट का आश्रय नहीं लिया, 2007-08 के दौरान तीन बार ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। 2007-08 के दौरान सरकार ने पिछले साल के 39 दिनों की तुलना में 91 दिनों में डब्ल्यूएमए/ओडी प्राप्त किया।

2.110 डब्ल्यूएमए की सीमाएं साल की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए पर तथा साल की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए रखी गई हैं। डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर अब तक की तरह रिपो दर से जुड़ी रहेगी। केंद्र ने राजकोषीय वर्ष की शुरुआत 76,686 करोड़ रुपए के बड़े अधिशेष के साथ की तथा 3 अगस्त 2008 तक अधिशेष की स्थिति रही। केंद्र ने 4 अगस्त 2008 से 6 अगस्त 2008 तक तीन दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का आश्रय लिया। कुल मिलाकर 2008-09 में अब तक (11 अगस्त 2008 तक) केंद्र ने तीन दिन डब्ल्यूएमए का आश्रय लिया है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 91 दिन (37 दिन के ओवरड्राफ्ट सहित) इसका आश्रय लिया था।

केंद्र सरकार के बाजार उधार - 2007-08

2.111 केंद्र सरकार के बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों सहित) 2007-08 में 1,88,828 करोड़ रुपए (निवल राशि 1,09,579 करोड़ रुपए) होने का बजट अनुमान था जो 2006-07 में जुटाई गई वास्तविक राशि की तुलना में 9,455 करोड़ रुपए अधिक थी। 2007-08 की पहली और दूसरी छमाही के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से जारी किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में जुटाई गई क्रमशः 89,000 करोड़ रुपए तथा 57,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में बाजार उधार राशियां क्रमशः 92,000 करोड़ रुपए तथा 59,000 करोड़ रुपए रखी गईं। 2007-08 की पहली छमाही में जुटाई गई वास्तविक राशि 97,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए की राशि भारतीय रिजर्व बैंक से भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी भारत सरकार को अंतरित करने के आंशिक वित्तपोषण के प्रति निर्गम कैलेंडर के बाहर जुटाई गई। दूसरी छमाही में 59,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो निर्गम कैलेंडर के अनुसार था।

दिनांकित प्रतिभूतियां

2.112 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई गई सकल बाजार उधार राशियां पिछले वर्ष के 1,46,000

करोड़ रुपए की तुलना में 1,56,000 करोड़ रुपए थीं। 2007-08 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई गई सकल बाजार उधार राशियां पिछले वर्ष के 94.18 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 100.35 प्रतिशत थीं। वर्ष के दौरान जुलाई 2007 में सिर्फ एक नई प्रतिभूति (7.99 प्रतिशत जीएस 2017) जारी की गई, जबकि सभी शेष 34 प्रतिभूतियों को दुबारा जारी किया गया। वित्त वर्ष के दौरान पीडी पर कुल न्यागमन 957 करोड़ रुपए था।

2.113 2007-08 के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारत औसत प्रतिफल 2006-07 के 7.89 प्रतिशत की तुलना में 8.12 प्रतिशत पर उच्चतर था। वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 14.72 वर्ष की तुलना में 14.90 वर्ष थी।

2008-09 के दौरान बाजार उधार

2.114 2008-09 के लिए केंद्र सरकार का बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों सहित) 2007-08 में जुटाई गई वास्तविक राशि की तुलना में 1,75,780 करोड़ रुपए (निवल राशि 99,000 करोड़ रुपए) पर निम्नतर होने का बजट अनुमान है। 24 मार्च 2008 को 2008-09 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों हेतु निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से जारी किया गया। तदनुसार, पिछले साल की तदनुसूचित अवधि में जुटाई गई 97,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 96,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जानी है। जुटाई जानेवाली मासिक राशि 8,000 करोड़ रुपए (सितंबर 2008) से 20,000 करोड़ रुपए (अप्रैल तथा मई 2008) के बीच अलग-अलग है। जहां 2008-09 की पहली छमाही में जुटाई जानेवाली 36 प्रतिशत प्रतिभूतियां 10-14 वर्ष के बीच की अवधि की होंगी, 32 प्रतिशत प्रतिभूतियों की अवधि 20 वर्ष और अधिक होगी।

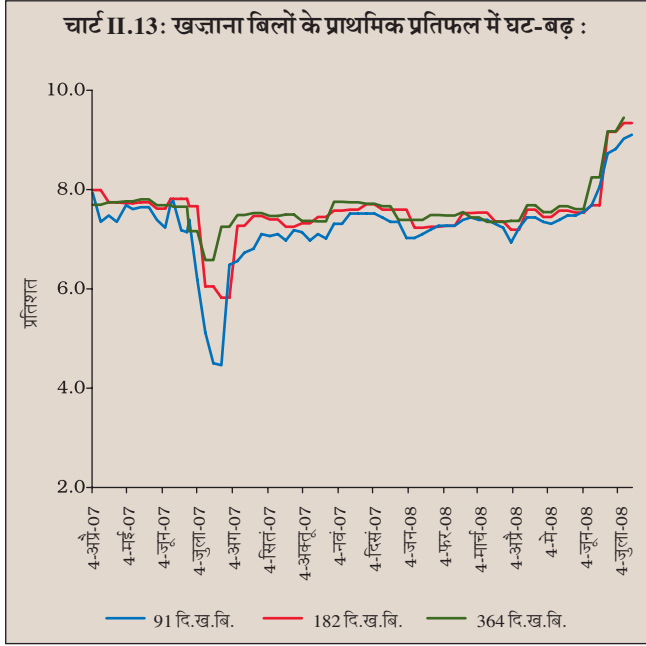
2.115 2008-09 के दौरान अब तक (11 अगस्त 2008 तक) केंद्र सरकार ने बाजार उधार कार्यक्रम के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपए जुटाए। उधार राशियां सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार जुटाई गईं, 24 जुलाई 2008 को की गई नीलामी इसका अपवाद थी जिसके तहत बाजार की अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए उच्चतर परिपक्वतावाली प्रतिभूति के स्थान पर 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति जारी की गई। 24 जुलाई 2008 तथा 8 अगस्त 2008 को की गई नीलामियां एक समान मूल्य पद्धति पर आधारित थीं। 2008-09 के दौरान (11 अगस्त 2008 तक) सभी नीलामियां, 10 वर्षीय परिपक्वतावाले एक नए निर्गम को छोड़कर, वर्तमान प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गम थीं। 2008-09 के दौरान (11 अगस्त 2008 तक) जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की तदनुसूचित अवधि के 14.32 वर्ष की तुलना में 15.21 वर्ष पर उच्चतर थी। उसी अवधि में जारी की गई

दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 8.72 प्रतिशत हो गया।

खजाना बिल

2.116 30 मार्च 2007 को जारी वार्षिक निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि क्रमशः 500 करोड़ रुपए (साप्ताहिक नीलामी), 500 करोड़ रुपए (पाक्षिक नीलामी) तथा 1000 करोड़ रुपए (पाक्षिक नीलामी) पर अपरिवर्तित रखी गईं। तथापि, जैसाकि पहले सूचित किया गया है, जून 2007 में कई अवसरों पर अधिसूचित राशियां बढ़ा दी गईं ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, 29 जून 2007 को भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अंतरण के कारण प्रत्याशित अस्थायी नकदी बेमेल का वित्तपोषण किया जा सके।

2.117 अप्रैल-जून 2007 के दौरान 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिफल क्रमशः 7.32 प्रतिशत, 7.73 प्रतिशत तथा 7.75 प्रतिशत पर मार्च के अंत के स्तरों के आसपास अपेक्षाकृत स्थिर बने रहे। 2007-08 की दूसरी तिमाही, विशेषकर जुलाई 2007 में प्रतिफल में कमी आई जो मुद्रा बाजार खंडों की प्रवृत्तियों तथा देशी मुद्रास्फीति दर में गिरावट को दर्शाती है। 18 जुलाई 2007 को प्रतिफलों में गिरावट आई जो चलनिधि की स्थितियों में नरमी तथा बहुत कम अल्पावधि दरों को दर्शाती है। एलएएफ रिपोर्ट में 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा को देखते हुए अधिशेष चलनिधि के फलस्वरूप अल्पावधि दरें अत्यधिक कम हो गईं तथा खजाना बिलों की नीलामियों में आक्रामक बोली लगाई गई और इसलिए नीलामी का कट-ऑफ न्यूनतर रहा। अगस्त-सितंबर 2007 के मध्य के दौरान खजाना बिलों का प्रतिफल मुद्रा बाजार की उच्चतर ब्याज दरों तथा रिजर्व रिपोर्ट के जरिए अवशोषण पर लगाई गई अधिकतम सीमा को हटाए जाने के अनुरूप बढ़ गया। 18 सितंबर 2007 को यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा दर में 50 आधार अंकों की तथा 31 अक्टूबर 2007 को और 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आवकों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप सितंबर के मध्य-अक्टूबर 2007 के दौरान खजाना बिलों के प्रतिफल में कमी आई। 10 नवंबर 2007 से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाए जाने के साथ नवंबर 2007 में प्रतिफल पुनः बढ़ गया। यूएस फेड द्वारा दर में आक्रामक कटौती (11 दिसंबर 2007, 22 जनवरी 2008 तथा 30 जनवरी 2008 को क्रमशः 25 आधार अंक, 75 आधार अंक तथा 50 आधार अंक) के फलस्वरूप जनवरी 2008 में प्रतिफल में कमी आई तथा मार्च 2008 तक वह सीमित दायरे में बना रहा (चार्ट II.13)। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिफल का औसत 2007-08 में क्रमशः 7.11 प्रतिशत, 7.42 प्रतिशत तथा 7.50 प्रतिशत था।



2.118 2008-09 के लिए खजाना बिलों की नियमित नीलामी के कैलेण्डर की घोषणा 24 मार्च 2008 को की गयी। अधिसूचित राशि को 91 दिवसीय तथा 182 दिवसीय खजाना बिलों में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए पर तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रखा गया। तथापि, 2008-09 में (जुलाई 2008 के अंत तक) 91 दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि (एमएसएस को छोड़कर) सात बार हर बार 2500 करोड़ रुपए तथा एक बार 1500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी और 182 दिवसीय खजाना बिलों की राशि दो बार हर बार 500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी। इस प्रकार जुलाई 2008 में किसानों की ऋण माफी योजना पर हुए व्यय से उत्पन्न प्रत्याशित अस्थायी नकदी बेमेल के वित्तपोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई गयी।

राज्य सरकारों का बाजार उधार

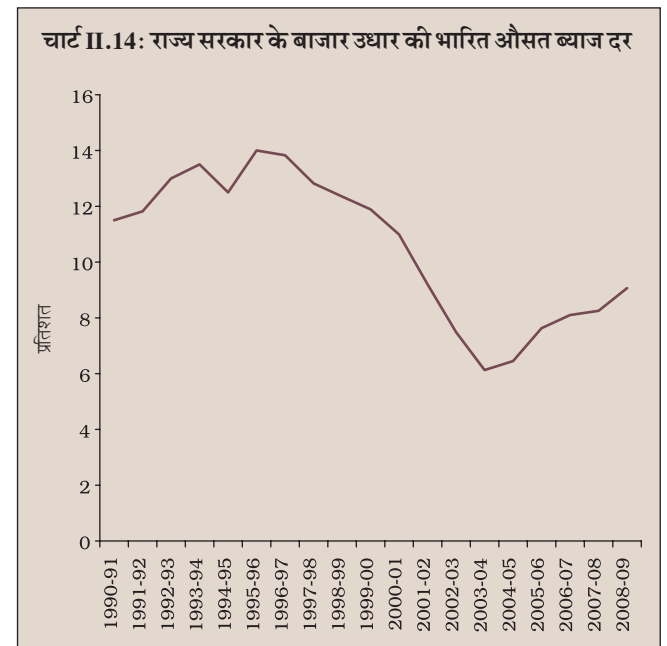
2.119 2007-08 के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 28,781 करोड़ रुपए का निवल आबंटन किया गया। वर्ष के दौरान 40,234 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन (एनएसएसएफ में कमी के कारण किए गए 35,780 करोड़ रुपए के आबंटन सहित) तथा 11,555 करोड़ रुपए की चुकौती (उड़ीसा सरकार द्वारा की गयी 156.44 करोड़ रुपए की पुनर्खरीद को छोड़कर) को हिसाब में लेते हुए, कुल आबंटन पिछले साल के 20,825 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल उधार की तुलना में 80,570 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों का कुल उधार 67,779 करोड़ रुपए हो गया जिसे अनन्य रूप से नीलामी के जरिए जुटाया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकार के बाजार ऋणों की नीलामी में, तदनुरूपी दस वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर स्प्रेड 19 तथा 90 आधार अंकों के बीच था। सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर

को छोड़कर) के लिए स्प्रेड अक्टूबर 2007 तक 50 आधार अंकों से कम था, तथापि, बाद की नीलामियों के लिए अधिकांश राज्यों के लिए स्प्रेड खुली बिक्री के मामले में द्वितीयक बाजार में समतुल्य अवधि की केंद्र सरकार की प्रतिभूति के मौजूदा प्रतिफल पर निर्धारित 50 आधार अंकों के सामान्य स्प्रेड से अधिक था तथा वह 35 से 89 आधार अंकों के दायरे में था।

2.120 2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले साल के 8.10 प्रतिशत की तुलना में 8.25 प्रतिशत था (चार्ट II.14)। वर्ष के दौरान कट-ऑफ प्रतिफल 7.84 तथा 8.90 प्रतिशत के बीच था (सारणी 2.31)। राजकोषीय वर्ष के दौरान सभी निर्गम 10 साल की परिपक्वता के थे। वर्ष के दौरान चार राज्य बाजार में नहीं आए।

2.121 सामान्य डब्ल्यूएमए की राज्यवार सीमाओं की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि 2007-08 के लिए इन सीमाओं को अपरिवर्तित रखा जाए। रिजर्व बैंक ने सामान्य बैंकिंग कारोबार करने तथा रुपया लोक ऋण का प्रबंधन करने के लिए पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की सरकार के साथ एक समझौता किया है जो 17 दिसंबर 2007 से लागू है। पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 50 करोड़ रुपए है। तदनुसार 2007-08 के लिए पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र सहित कुल सामान्य डब्ल्यूएमए सीमा 9,925 करोड़ रुपए थी।

2.122 अधिकांश राज्य सरकारों की चलनिधि की स्थिति 2007-08 में सुखद बनी रही। राज्यों द्वारा 2007-08 के दौरान 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में किया गया मासिक औसत निवेश 74,047 करोड़ रुपए था जो पिछले साल के



**सारणी 2.31 राज्य सरकारों की बाजार उधारियां
(31 जुलाई 2008 तक)**

मद	दिनांक	कट-ऑफ दर (प्रतिशत)	अवधि (वर्ष)	जुलाई गई राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
नीलामियां				
2007-08				
पहली	अप्रैल 19, 2007	8.30	10	1,837
दूसरी	मई 10, 2007	8.34	10	350
तीसरी	मई 17, 2007	8.40	10	1,400
चौथी	जून 19, 2007	8.45-8.57	10	3,566
पांचवीं	जुलाई 26, 2007	8.00-8.25	10	1,389
छठी	अगस्त 16, 2007	8.30-8.90	10	3,484
सातवीं	सितंबर 20, 2007	8.14-8.50	10	3,074
आठवीं	अक्टूबर 4, 2007	8.20	10	590
नौवीं	अक्टूबर 8, 2007	8.31-8.40	10	4,672
दसवीं	नवंबर 13, 2007	8.39-8.69	10	5,300
ग्यारहवीं	नवंबर 30, 2007	8.45-8.50	10	5,212
बारहवीं	दिसंबर 18, 2007	8.39-8.58	10	2,963
तेरहवीं	जनवरी 7, 2008	8.03-8.12	10	5,833
चौदहवीं	जनवरी 24, 2008	7.84-7.98	10	7,778
पंद्रहवीं	फरवरी 15, 2008	7.93-8.02	10	7,776
सोलहवीं	फरवरी 22, 2008	8.12-8.48	10	4,975
सत्रहवीं	मार्च 7, 2008	8.28-8.45	10	4,349
अठारहवीं	मार्च 26, 2008	8.35-8.70	10	3,229
कुल				67,779
2008-09				
पहली	अप्रैल 22, 2008	8.50-8.60	10	2,648
दूसरी	मई 27, 2008	8.39-8.68	10	3,264
तीसरी	जून 27, 2008	9.38-9.59	10	2,300
चौथी	जुलाई 10, 2008	9.81	10	500
पांचवीं	जुलाई 31, 2008	9.86-9.90	10	2,100
कुल				10,812

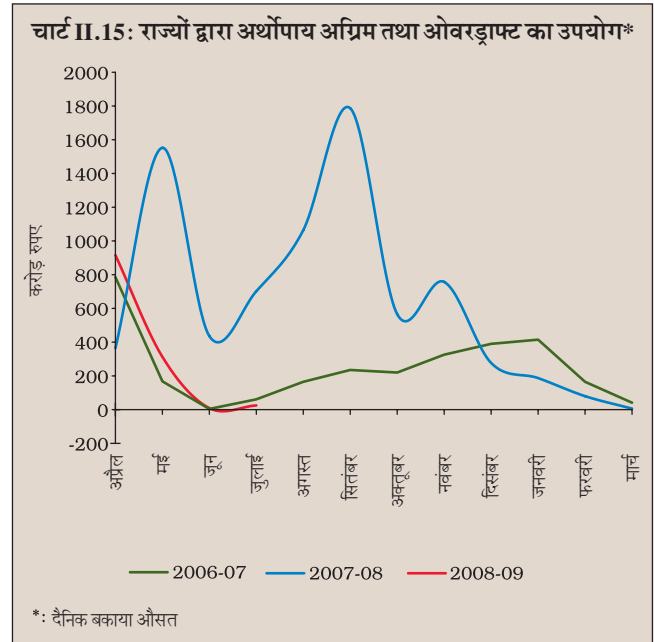
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

63,908 करोड़ रुपए की तुलना में उच्चतर था। 2007-08 के दौरान राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग पिछले साल के 248 करोड़ रुपए की तुलना में 648 करोड़ रुपए पर कुछ अधिक था (चार्ट II.15), हालांकि यह 2007-08 तथा 2008-09 के लिए निर्धारित 9,925 करोड़ रुपए की डब्ल्यूएमए सीमा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2007-08 के दौरान, पिछले साल क्रमशः सात राज्यों तथा तीन राज्यों की तुलना में, आठ राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया तथा तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। 2008-09 में (जुलाई 2008 के अंत तक) राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग 313 करोड़ रुपए था। उसी अवधि के दौरान चार राज्यों ने डब्ल्यूएमए और तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय आइटीबी तथा एटीबी में मार्च 2007 के अंत के 73,403 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 97,615 करोड़ रुपए का समेकित निवेश किया गया, जबकि राज्यों के डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट की समस्त बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के 285 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 172 करोड़ रुपए थी।

2008-09 के दौरान अब तक (11 अगस्त 2008 तक) राज्य सरकारों का बाजार उधार

2.123 2008-09 के लिए राज्य सरकारों के निवल बाजार उधार की अनुमानित राशि 44,692 करोड़ रुपए है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियों को हिसाब में लेने पर, राज्य सरकारों का सकल बाजार उधार 59,108 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष में (11 अगस्त 2008 तक), आठ राज्य सरकारों ने बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 10,812 करोड़ रुपए जुटाए जबकि इसकी तुलना में पिछले साल की तदनु रूप अवधि में 8,542 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। नीलामी में कट-ऑफ प्रतिफल 8.39 प्रतिशत और 9.90 प्रतिशत के बीच था। बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर 2008-09 में (11 अगस्त 2008 तक), 2007-08 की तदनु रूप अवधि के 8.35 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 9.07 प्रतिशत हो गयी। तदनु रूप परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल की तुलना में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के स्प्रेड पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 19 एवं 44 आधार अंकों की तुलना में 30 एवं 98 आधार अंकों के दायरे में थे।

2.124 राज्य सरकारों द्वारा 11 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों में 86,464 करोड़ रुपए का समेकित निवेश किया गया। अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान राज्यों द्वारा खजाना बिलों (14 दिवसीय और नीलामी) में, पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 70,513 करोड़ रुपए की तुलना में, 82,298 करोड़ रुपए का औसत निवेश किया गया (चार्ट II.16)।



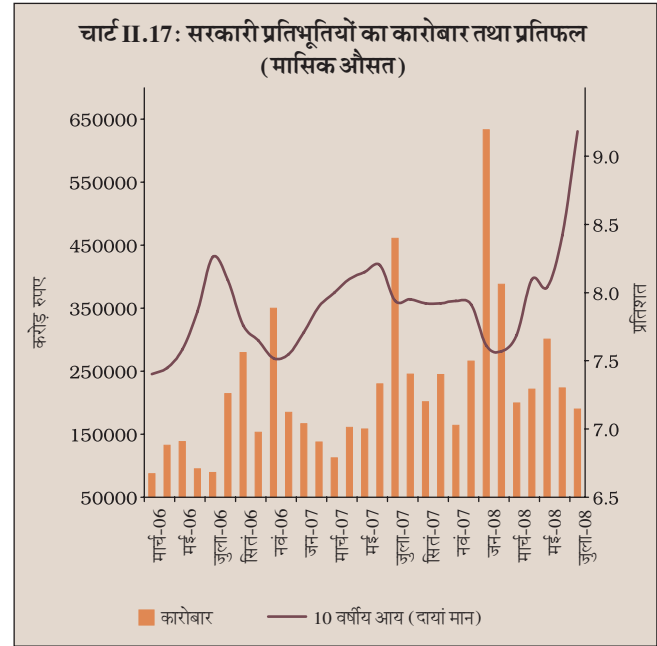
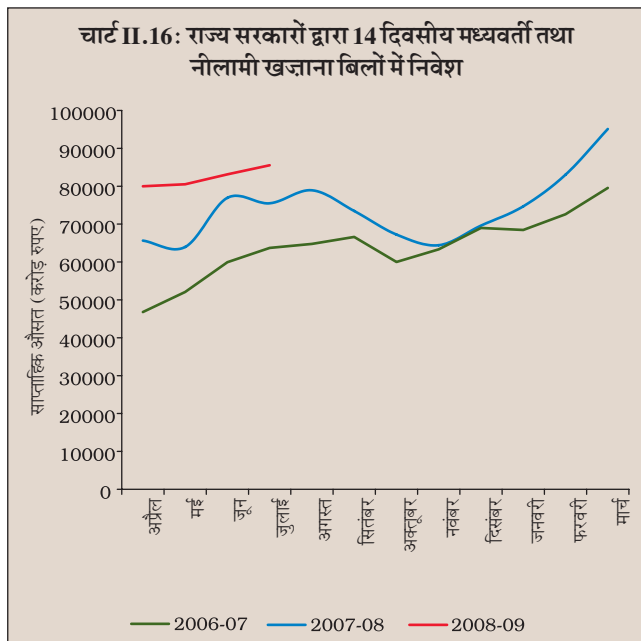
सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन

2.125 2007-08 के दौरान, द्वितीयक बाजार के लेनदेन की कुल मात्रा 2006-07 के 35,83,336 करोड़ रुपए (जिसका 29 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन के लिए तथा शेष रिपो के लिए था) से 57 प्रतिशत बढ़कर 56,27,347 करोड़ रुपए (जिसका 30 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन के लिए तथा शेष रिपो के लिए था) हो गयी। द्वितीयक बाजार के लेनदेनों की कुल मात्रा अप्रैल 2007 के दौरान 2,31,094 करोड़ रुपए (माह के दौरान औसत बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल 8.17 प्रतिशत था) पर न्यूनतम थी तथा प्रतिफल में नरमी आने पर जनवरी 2008 के दौरान 7,42,365 करोड़ रुपए पर अधिकतम थी (माह के दौरान औसत बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल 7.57 प्रतिशत था) (चार्ट II.17)।

2.126 2008-09 में अब तक (अप्रैल से जुलाई 2008 तक), द्वितीयक बाजार के लेनदेनों की कुल मात्रा पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 14,09,136 करोड़ रुपए से 20 प्रतिशत बढ़कर 16,85,238 करोड़ रुपए हो गयी।

प्रतिफल में घटबढ़ और प्रतिफल वक्र

2.127 2007-08 के दौरान तथा पुनः अगस्त-दिसम्बर 2007 में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में थोड़ी गिरावट आयी, 2007-08 की पहली तिमाही अपवाद थी, जब प्रतिफल में वृद्धि हुई। 2007-08 की पहली तिमाही में प्रतिफल में कुछ वृद्धि हुई, जो अंशतः वैश्विक प्रवृत्तियों तथा गैर अनुसूचित नीलामी की घोषणा को दर्शाता है। अगस्त-दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान प्रतिफल आम तौर पर एक सीमित दायरे में रहा तथा जनवरी एवं फरवरी 2008 के दौरान उसमें नरमी आयी, जो अंशतः प्रतिफलों की वैश्विक



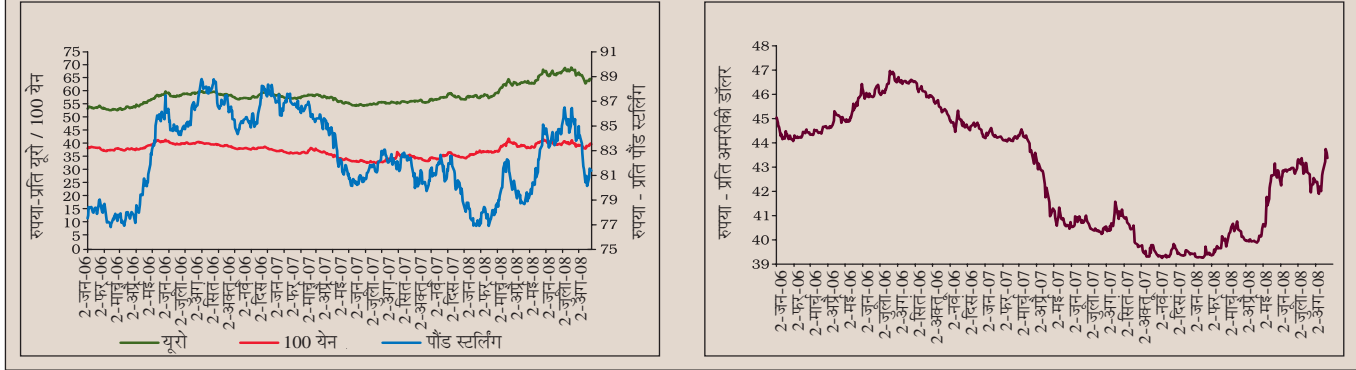
प्रवृत्तियों, फेडरल रिजर्व द्वारा क्रमिक रूप से दर में कटौती, न्यूनतम मुद्रास्फीति तथा चलनिधि की नरम स्थितियों को दर्शाता है। तथापि, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाते हुए मार्च 2008 के दूसरे पखवाड़े में प्रतिफल पुनः बढ़ गया। 2007-08 के दौरान दस वर्षीय प्रतिफल 7.42 - 8.32 प्रतिशत के दायरे में था। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, प्रतिफल 7.93 प्रतिशत था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 4 आधार अंक कम था। 1 वर्षीय तथा 10 वर्षीय प्रतिफल के बीच स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 42 आधार अंकों की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 45 आधार अंक था। 10 वर्षीय तथा 30 वर्षीय प्रतिफल के बीच स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 37 आधार अंकों की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 47 आधार अंक था। 2007-08 के संपूर्ण वर्ष के लिए औसत प्रतिफल 7.91 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 7.78 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर था।

2.128 2008-09 के दौरान अब तक (अप्रैल से जुलाई 2008 तक), पहले दो महीनों में प्रतिफल एक सीमित दायरे में बने रहे परंतु मुद्रास्फीति बढ़ने और तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के कारण जून-जुलाई 2008 के दौरान उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 10 वर्षीय प्रतिफल, जो पहले दो महीनों के दौरान 7.90 - 8.20 प्रतिशत के बीच घटता बढ़ता रहा, 15 जुलाई 2008 को 9.51 प्रतिशत पर शिखर पर पहुंच गया।

विदेशी मुद्रा बाजार

2.129 2007-08 के दौरान, ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के साथ रुपया प्रति अमरीकी डालर 43.15 - 39.26 रुपए के दायरे में रहा। अगस्त 2007 के पहले पखवाड़े में रुपए का मूल्यहास हुआ, जिसका कारण था - भारत

चार्ट II.18 : प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया घट-बढ़



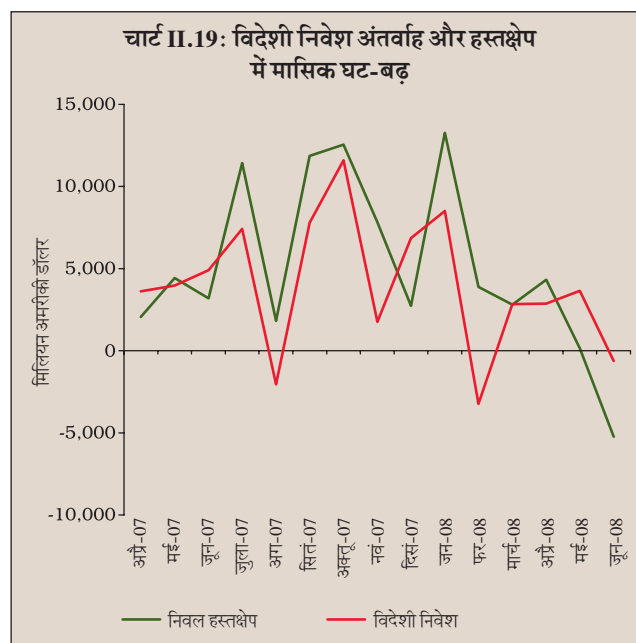
में इक्विटी बाजार में मंदड़िया स्थिति, अमरीका में सबप्राइम उधार संकट संबंधी चिंता तथा बीएनपी परिबास नामक अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा इसके तीन म्युच्युअल फंडों के निवल आस्ति मूल्य की गणना निलंबित किए जाने के समाचार के कारण एफआइआइ के बहिर्वाह में तेजी आना। उसके बाद बड़ी मात्रा में पूंजी के अंतर्वाह, अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में कमजोरी आने तथा देशी स्टॉक बाजार में तेजड़िया स्थिति के फलस्वरूप रुपए की मूल्यवृद्धि हुई। तथापि, स्टॉक बाजार की मंदड़िया स्थिति, पूंजी के बहिर्वाह, तेल की कीमतों में वृद्धि और आयातकों एवं एफआइआइ द्वारा डालर की मांग में वृद्धि के कारण फरवरी 2008 के आरंभ से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में मूल्यहास शुरू हो गया। 31 मार्च 2008 को रुपया प्रति अमरीकी डालर 39.99 रुपए पर था। इस स्तर पर भारतीय रुपए का मूल्य 30 मार्च 2007 के स्तर से अमरीकी डालर की तुलना में 9.0 प्रतिशत तथा पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 7.6 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, इसमें यूरो की तुलना में 7.8 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में 7.6 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ (चार्ट II.18)। 2008-09 के दौरान अब तक, पिछली प्रवृत्ति जारी रखते हुए 21 अगस्त 2008 को रुपया प्रति अमरीकी डालर 43.58 रुपए पर पहुंच गया। मार्च 2008 के अंत तथा 21 अगस्त 2008 के बीच, भारतीय रुपए की विनिमय दर में अमरीकी डालर की तुलना में 8.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 2.4 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 2.2 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में 0.1 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ। मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के बीच, भारतीय रुपए की 36 मुद्रा वाली व्यापार भारित सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में, पिछले साल की तदनुरूप अवधि में हुए क्रमशः 2.7 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत के मूल्यहास की तुलना में क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। रुपए के 6 मुद्रा वाले व्यापार भारित एनईईआर तथा आरईईआर में मार्च 2007 और मार्च 2008 के बीच क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई (सारणी 2.32)।

सारणी 2.32 : भारतीय रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार - आधारित भारांक)

वर्ष / माह	आधार : 1993-94 (अप्रैल-मार्च) = 100			
	6-मुद्रा		36-मुद्रा	
	नीर	रीर	नीर	रीर
1	2	3	4	5
1993-94	100.00	100.00	100.00	100.00
2000-01	77.43	102.82	92.12	100.09
2002-02	76.04	102.71	91.58	100.86
2002-03	71.27	97.68	89.12	98.18
2003-04	69.97	99.17	87.14	99.56
2004-05	69.58	101.78	87.31	100.09
2005-06	72.28	107.30	89.85	102.35
2006-07 (अ)	68.49	105.57	85.89	98.43
2007-08 (अ)	74.17	114.09	92.46	105.08
अप्रैल 2006	71.63	105.86	87.73	98.17
मई 2006	69.39	103.70	85.43	96.39
जून 2006	68.79	103.19	85.11	96.53
जुलाई 2006	68.14	102.31	84.22	95.72
अगस्त 2006	67.65	102.26	83.61	95.59
सितंबर 2006	68.40	104.88	84.65	97.96
अक्टूबर 2006	69.66	107.34	86.18	99.91
नवंबर 2006	69.90	107.92	86.50	100.27
दिसंबर 2006	69.38	106.52	85.89	99.05
जनवरी 2007 (अ)	70.32	107.69	87.05	100.59
फरवरी 2007 (अ)	70.42	107.67	87.21	100.49
मार्च 2007 (अ)	70.23	107.46	87.11	100.50
अप्रैल 2007 (अ)	72.74	111.63	91.79	102.84
मई 2007 (अ)	75.19	115.73	94.68	106.24
जून 2007 (अ)	75.37	115.22	93.24	106.14
जुलाई 2007 (अ)	75.15	115.10	93.08	106.19
अगस्त 2007 (अ)	74.44	114.10	92.63	105.54
सितंबर 2007 (अ)	74.64	115.03	92.89	106.15
अक्टूबर 2007 (अ)	75.45	115.79	93.49	106.34
नवंबर 2007 (अ)	74.34	113.90	92.47	104.85
दिसंबर 2007 (अ)	74.65	114.52	92.92	105.16
जनवरी 2008 (अ)	74.31	114.23	92.55	105.12
फरवरी 2008 (अ)	73.41	113.06	91.41	103.84
मार्च 2008 (अ)	70.38	110.87	88.34	102.55
नीर	: सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर।			
रीर	: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर।			
अ	: अनंतिम			
टिप्पणी	: सूचकांक में वृद्धि रुपए की मूल्यवृद्धि और कमी उसके विपरीत का सूचक है।			

विनिमय दर का प्रबंधन

2.130 हाल में मौद्रिक नीति के संचालन को बड़े पूंजी प्रवाह तथा ऐसा प्रवाहों में बढ़ी हुई अस्थिरता से संतुष्ट रहना पड़ा। 2007-08 के दौरान एफआइआइ ने बड़े पैमाने पर भारतीय स्टॉक बाजारों में निवेश किया, जो स्टॉक बाजारों में उछाल, सुदृढ़ देशी कार्यकलाप तथा भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तथापि, इन अंतर्वाहों के साथ इन महीनों में अस्थिर पैटर्न देखा गया। वर्ष के अधिकांश भाग में, विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप माहवार आधार पर बड़े पूंजी प्रवाहों के अनुरूप रहा तथा अगस्त 2007, नवम्बर 2007, फरवरी 2008 और मार्च 2008 के महीने इसके एक मात्र अपवाद थे जब एफआइआइ के कारण हुए निवल बहिर्वाहों के बावजूद रिजर्व बैंक द्वारा निवल खरीद की गयी (सारणी 2.33 तथा चार्ट II.19)। अगस्त 2007 में, पार्टिसिपेटरी नोटों संबंधी एफआइआइ मानदण्डों को सख्त बनाए जाने, भारत सहित एशिया के स्टॉक बाजारों में मंदड़िया स्थिति, तथा आवास बाजार में और कमजोरी संबंधी चिंताओं के कारण अमरीकी स्टॉक बाजारों में बड़े पैमाने पर बिक्री संबंधी चिंताओं के कारण बहिर्वाह हुए। फरवरी 2008 में एफआइआइ द्वारा बड़े पैमाने पर बहिर्वाह किया गया जिसका मुख्य कारण आइपीओ निर्गमों में अभिदान करने के लिए जनवरी 2008 के दौरान लायी गयी राशि की वापसी था।



2.131 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008 महीनों के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा इन महीनों में हुए बड़े पूंजी अंतर्वाहों के अनुरूप बड़े पैमाने पर खरीद की गयी।

सारणी 2.33 : रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की बिक्री / खरीद

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	खरीद	बिक्री	निवल खरीद / बिक्री (-)	विदेशी निवेश अंतर्वाह **	एफआइआइ अंतर्वाह (निवल)	भारतीय रुपए की मूल्यवृद्धि / मूल्यहास (माह-दर-माह आधार पर)
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	26,824	0	26,824	29,082	3,225	-2.2'
2007-08	79,696	1,493	78,203	61,830	20,328	12.5'
<i>2007-08</i>						
अप्रैल 2007	2,055	0	2,055	3,617	1,963	4.5
मई 2007	4,426	0	4,426	3,972	1,847	3.4
जून 2007	3,192	0	3,192	4,902	3,279	0.0
जुलाई 2007	11,428	0	11,428	7,418	4,685	0.9
अगस्त 2007	1,815	0	1,815	-2,044	-3,323	-1.0
सितंबर 2007	11,867	0	11,867	7,794	7,057	1.2
अक्टूबर 2007	12,544	0	12,544	11,591	6833	2.1
नवंबर 2007	7,827	0	7,827	1,757	-265	0.2
दिसंबर 2007	2,731	0	2,731	6,852	2,396	0.0
जनवरी 2008	13,625	0	13,625	8,506	6,490	0.2
फरवरी 2008	3,884	0	3,884	-3,234	-8,991	-0.9
मार्च 2008	4,302	1,493	2,809	2,838	-1,643	-1.5
<i>2008-09</i>						
अप्रैल 2008	4,325	0	4,325	2,869	-1,432	0.8
मई 2008	1,625	1,477	148	3,644	-734	-5.0
जून 2008	1,770	6,999	-5,229	-618	-3,011	-1.6

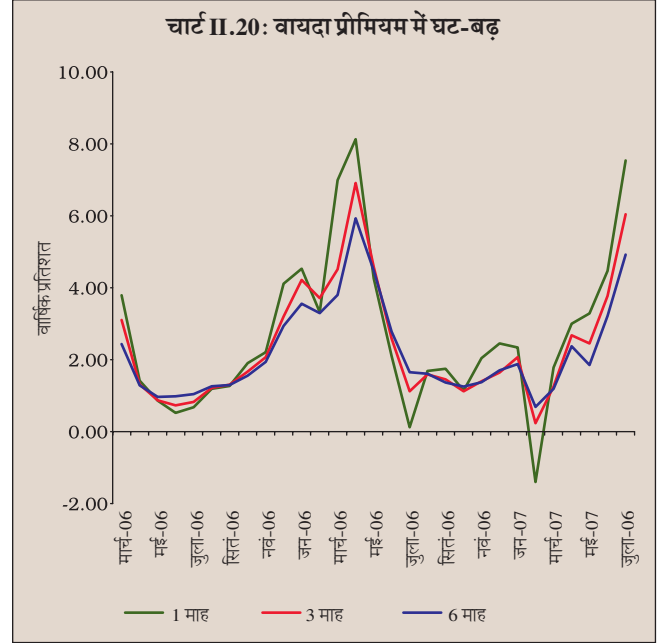
* : मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यहास (-) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर।
 ** : एफडीआइ और एडीआर/जीडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा जुटाए गए संसाधन के रूप में पोर्टफोलियो अंतर्वाह एवं विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा अंतर्वाह सहित (स्तंभ 6 में अलग से भी दर्शाए गए हैं)।

2.132 रिजर्व बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने के बावजूद, 2007-08 के दौरान भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि होना जारी रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा 78.2 बिलियन अमरीकी डालर की निवल खरीद किए जाने के बावजूद वार्षिक औसत आधार पर रुपए में 12.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। बड़े पैमाने पर ऐसे हस्तक्षेप के अभाव में, विनिमय दर में अस्थिरता काफी अधिक होती। ऐसे हस्तक्षेपों के देशी चलनिधि पर प्रभाव को ठीक करने के लिए, पहले दिए गए ब्यौरों के अनुसार एमएसएस परिचालनों - बड़े अंतर्वाहों की स्थिति में अवशोषण तथा विपर्यय / न्यूनतम अंतर्वाहों के दौरान शेष राशि को उघाड़ना - का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया।

2.133 2007-08 के दौरान वायदा प्रीमियम कम रहा, जो देशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की नरम स्थिति तथा निर्यातकों द्वारा भारी वायदा बिक्री को दर्शाता है। सभी परिपक्वताओं में वायदा प्रीमियम में वर्ष के दौरान निरंतर गिरावट आयी। 3 माह का वायदा प्रीमियम मार्च 2007 के अंत के 5.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2008 के अंत में 2.8 प्रतिशत रह गया। फरवरी 2008 के दौरान एक माह की वायदा दर बढ़े में बदल गयी। तथापि, बाद में वह प्रीमियम पर आ गयी। 14 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार एक माह, तीन माह और छः माह का वायदा प्रीमियम क्रमशः 6.6 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत था (चार्ट II.20)।

पूँजी बाजार

2.134 2007-08 के दौरान भारत में प्राथमिक पूँजी बाजार में सामान्यतः उछाल की स्थिति रही। मुख्यतः अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्तियों के कारण 2007-08 के दौरान भारतीय स्टॉक बाजारों में अस्थिरता के तेज दौर देखे गए।



प्राथमिक बाजार

2.135 2007-08 में सार्वजनिक निर्गमों के जरिए 83,707 करोड़ रुपए का संसाधन (119 निर्गमों के माध्यम से) जुटाया गया, जो पिछले साल के 32,382 करोड़ रुपए (119 निर्गमों के माध्यम से) की तुलना में उच्चतर था (सारणी 2.34)। चार को छोड़कर से सभी सार्वजनिक निर्गम निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लाए गए थे। साथ ही, 119 सार्वजनिक निर्गमों में से, 116 इक्विटी के रूप में थे तथा सिर्फ तीन ऋण के रूप में थे। तथापि, अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी संबंधी चिंताओं तथा अगले खण्ड में ब्यौरेवार बताए गए अनुसार वैश्विक ऋण बाजारों में उथल-पुथल के कारण द्वितीयक बाजार में तीव्र गिरावट आने से जनवरी 2008 की संक्षिप्त अवधि में सार्वजनिक

सारणी 2.34 : प्राथमिक बाजार से संसाधन संग्रहण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06		2006-07		2007-08 अ	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
क. सार्वजनिक निर्गम @						
(प्रॉस्पेक्टस और राइट्स)	138	26,940	119	32,382	119	83,707
I. सार्वजनिक क्षेत्र	7	5,786	2	1,779	4	20,069
II. निजी क्षेत्र	131	21,154	117	30,603	115	63,638
ख. निजी प्लेसमेंट	1,115	96,473	1,681	1,45,866	1,812	2,12,568
I. सार्वजनिक क्षेत्र	169	55,283	157	64,025	198	83,046
II. निजी क्षेत्र	946	41,190	1,524	81,841	1,614	1,29,522
ग. यूरो निर्गम @ @	48	11,352	40	17,005	26	26,556
कुल (क+ख+ग)	1,301	1,34,765	1,840	1,95,253	1,957	3,22,831

* : ऋण और इक्विटी दोनों सहित।

@ : बिक्री के लिए प्रस्ताव को छोड़कर।

@ @ : एडीआर और जीडीआर।

अ : अनंतिम।

नोट : अनुमान अरेंजर्स, वित्तीय संस्थाओं और सेबी से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।

निर्गमों के जरिए संसाधन संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से बाजार से तीन निर्गम वापस लेने पड़े तथा कुछ प्रस्तावित निर्गमों को स्थगित भी करना पड़ा। तथापि, बाद में फरवरी-मार्च 2008 के दौरान बाजार में आने वाले सभी 16 निर्गमों को पूर्ण अभिदान मिला।

2.136 2007-08 के दौरान निजी स्थानन के माध्यम से 2,12,568 करोड़ रुपए का कुल संसाधन संग्रहण किया गया, जो 2006-07 की तुलना में 45.7 प्रतिशत उच्चतर था। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं ने 2006-07 के 43.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में निजी स्थानन के जरिए कुल संसाधन संग्रहण का 39.1 प्रतिशत राशि जुटायी (सारणी 2.34)। वित्तीय मध्यस्थों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) द्वारा संसाधन संग्रहण पिछले साल के 1,00,531 करोड़ रुपए से 43.6 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 1,44,336 करोड़ रुपए हो गया।

2.137 अमरीकी निक्षेपागार रसीद (एडीआर) तथा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर) द्वारा यूरो निर्गमों के माध्यम से संसाधन संग्रहण में 2007-08 के दौरान 56.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-08 में 26 यूरो निर्गमों के माध्यम से 26,556 करोड़ रुपए जुटाए गए जबकि इसकी तुलना में 2006-07 में 40 निर्गमों के माध्यम से कुल 17,005 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

2.138 2007-08 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण (मोचन को घटाकर) 63.6 प्रतिशत बढ़कर 1,53,802 करोड़ रुपए हो गया (सारणी 2.35)। स्कीम-वार, 2007-08 के दौरान निधियों के निवल संग्रहण का 9.7 प्रतिशत लिक्विड/मुद्रा बाजार उन्मुख स्कीमों के तहत था (पिछले साल के 5.3 प्रतिशत की तुलना में) तथा 57.5 प्रतिशत ऋण-उन्मुख स्कीमों के तहत था (पिछले साल 63.9 प्रतिशत)। आलोच्य अवधि के दौरान इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों के तहत जुटायी गयी निधियां कुल संग्रहण का 4.0 प्रतिशत थीं।

द्वितीयक बाजार

2.139 वित्तीय वर्ष 2007-08 की शुरुआत देशी स्टॉक बाजारों की कमजोर स्थिति से हुई। तथापि, शीघ्र ही बाजार में उछाल आया तथा प्रमुख कंपनियों द्वारा घोषित 2006-07 की चौथी तिमाही के उत्साहजनक कारपोरेट परिणामों, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नरमी, भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) द्वारा सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के

सारणी 2.35 : म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4
I. यूटीआइ म्यूच्युअल फंड	3,424	7,326	10,677
II. निजी क्षेत्र	42,977	79,038	1,33,304
III. सार्वजनिक क्षेत्र	6,379	7,621	9,821
कुल (I+II+III)	52,780	93,985	1,53,802

स्त्रोत : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)।

पूर्वानुमान की रिपोर्टों तथा 06 अप्रैल 2007 को जारी सुदृढ़ अमरीकी रोजगार आंकड़ों के समर्थन से अगस्त 2007 के मध्य तक बाजार में उछाल जारी रहा। 9 जुलाई 2007 को बीएसई सेन्सेक्स 15,000 के स्तर के ऊपर चला गया। तथापि, बाजार में यह गति बरकरार नहीं रह सकी तथा अमरीका में मकानों की बिक्री में आयी गिरावट और अमरीकी बंधक एवं कंपनी उधार बाजारों में बढ़ती हुई चिंताओं से प्रेरित होकर वैश्विक इक्विटी बाजारों में आयी तेज गिरावट के फलस्वरूप अगस्त 2007 के मध्य के बाद बाजारों में गिरावट आयी। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, सरकार द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के माध्यम से जुटायी गयी निधियां प्रत्यावर्तित करने पर लगाये गये प्रतिबंधों और वैश्विक तांबा मूल्यों में गिरावट ने भी बाजार के रुख को प्रभावित किया।

2.140 स्टॉक बाजारों में फिर सुधार आया तथा सुदृढ़ समष्टि आर्थिक फंडामेंटल, अच्छी कारपोरेट आय, एफआइआइ द्वारा सुदृढ़ अंतर्वाह, धातु की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, अमरीकी फेड दर में कटौती तथा देशी वार्षिक मुद्रास्फीति दर में नरमी के समर्थन से 8 जनवरी 2008 तक उछाल बरकरार रहा। यद्यपि, देशी स्टॉक बाजारों में सेबी द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अक्टूबर के मध्य में और अमरीका एवं यूरोप में सब-प्राइम हानियों तथा ऋण की तंगी, अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में मूल्यहास तथा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़कर रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंचने संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में आयी अधोमुखी प्रवृत्ति की वजह से दिसंबर 2007 के मध्य में थोड़ा करेक्शन देखा गया, उनमें पुनः सुधार आया और वे नयी ऊंचाई पर पहुंच गए। 8 जनवरी 2008 को बीएसई सेन्सेक्स 20873.33 के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर बंद हुआ और उसने मार्च 2007 के अंत की तुलना में 59.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2.141 तथापि, 11 जनवरी 2008 से देशी स्टॉक बाजारों में अस्थिरता देखी गयी, जिसका कारण था - अमरीकी सेवा उद्योग में संकुचन के कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में अत्यधिक चिंता, कुछ अग्रणी अमरीकी कंपनी द्वारा आय में कम वृद्धि सूचित किया जाना, गृह मोचन-निषेध रिकार्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंचना और अमरीका में खुदरा बिक्री की खराब स्थिति। बड़े आइपीओ के कारण द्वितीयक बाजार से नकदी के निष्कासन, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआइआइ द्वारा भारी मात्रा में बिक्री, सीएसओ द्वारा जीडीपी की वृद्धि में अधोमुखी संशोधन, 2008-09 के केंद्रीय बजट में अल्पावधि पूंजी लाभ कर 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत किए जाने, देशी वार्षिक मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें रिकार्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंचने तथा अमरीकी बाजारों में एडीआर मूल्यों में गिरावट ने भी बाजार के रुख को निरुत्साहित कर दिया। इन गतिविधियों के फलस्वरूप 31 मार्च 2008 को बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी क्रमशः 15644.44 तथा 4734.50 पर बंद हुआ और उनमें 8 जनवरी 2008 की तुलना में क्रमशः 25.1 प्रतिशत तथा 24.7 प्रतिशत की गिरावट आयी।

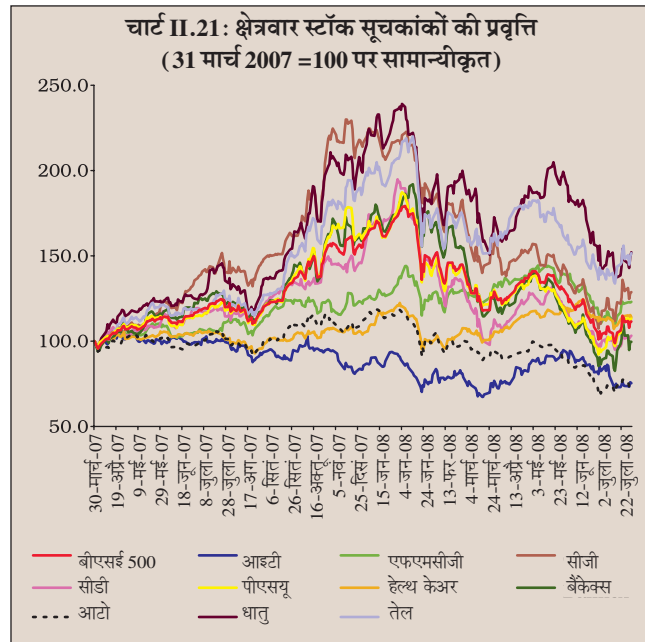
तथापि, पूरे साल में बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी ने क्रमशः 19.7 प्रतिशत तथा 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2.142 2007-08 के दौरान अधिकांश सेक्टर के सूचकांकों अर्थात् धातु, तेल और गैस, पूंजीगत माल, तीव्र खपत वाले उपभोक्ता माल, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बैंकिंग और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गयी। तथापि, आइटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी (चार्ट II.21)।

2.143 सेबी के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 के दौरान एफआइआइ ने भारतीय इक्विटी में 52,574 करोड़ रुपए का निवल निवेश किया जो पिछले साल के निवल निवेश की तुलना में दुगुने से अधिक थे। ऋण में निवल निवेश पिछले साल के 6,081 करोड़ रुपए की तुलना में 12,499 करोड़ रुपए थे। म्यूच्युअल फंडों द्वारा भी इक्विटी तथा ऋण लिखतों में निवल निवेश में तीव्र वृद्धि की गई (सारणी 2.36)।

2.144 2007-08 के दौरान बीएसई और एनएसई के नकद खण्ड के संयुक्त पण्यवर्त में पिछले साल की तुलना में 76.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाजार पूंजीकरण मार्च 2007 के अंत के 85.5 प्रतिशत से सुधरकर, मार्च 2008 के अंत तक गिरकर 109.0 प्रतिशत होने के पहले, 8 जनवरी 2008 को 156.7 प्रतिशत हो गया। बीएसई सेन्सेक्स का मूल्य अर्जन (पी/ई) अनुपात भी मार्च 2007 के अंत के 20.3 से बढ़कर, मार्च 2008 के अंत तक गिरकर 20.1 होने के पहले, 8 जनवरी 2008 तक 28.5 हो गया। घटबढ़ के गुणांक द्वारा मापे जाने पर 2007-08 के दौरान अस्थिरता में भी वृद्धि हुई (सारणी 2.37)।

2.145 2008-09 के दौरान, देशी स्टॉक बाजारों में 21 मई 2008 तक बढ़त की प्रवृत्ति देखी गयी, मार्च 2008 के अंत की तुलना में उसमें 10.2



सारणी 2.36 : संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी संस्थागत निवेशक		म्यूच्युअल फंड	
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	2	3	4	5
2003-04	43,631	5,534	1,308	22,701
2004-05	40,991	1,927	448	16,987
2005-06	48,487	-7,334	14,303	36,801
2006-07	26,031	6,081	9,062	52,543
2007-08	52,574	12,499	16,306	73,790

टिप्पणी : विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश इक्विटी में तथा ऋण बाजार में वास्तविक निवेश दर्शाते हैं। इस सारणी के आंकड़े हो सकता है कि भुगतान संतुलन खंड के विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह के शेष, जो देश में / से वास्तविक अंतर्वाह / बहिर्वाह को दर्शाते हैं, से नहीं मेल खाएं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड।

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। तथापि, उसके बाद अन्य बातों में मुख्य रूप से खुदरा ईंधन के देशी मूल्यों में वृद्धि, देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआइआइ द्वारा निवल बिक्री, बढ़ते व्यापार घाटे तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अधोमुखी प्रवृत्ति पर चिंता, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण बाजारों में सतर्कता आ गयी। फलस्वरूप 27 अगस्त 2008 को बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी दोनों क्रमशः 14297 तथा 4292 पर न्यूनतर स्तर पर बंद हुए और मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में उन्होंने क्रमशः 8.6 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत की हानि दर्ज की। मार्च 2008 के अंत और 27 अगस्त 2008 के बीच बीएसई सेन्सेक्स 12576-17600 के दायरे में रहा।

2.146 2007-08 के दौरान एनएसई के डेरिवेटिव खण्ड में कुल पण्यवर्त नकद खण्ड के पण्यवर्त की तुलना में उल्लेखनीय रूप से ऊंचा बना रहा (सारणी 2.38)।

सारणी 2.37: शेयर बाजारों की प्रवृत्तियां

मद	बीएसई		एनएसई	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. औसत बीएसई सेन्सेक्स / एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी	12277	16569	3572	4897
2. उतार-चढ़ाव (घटबढ़ का गुणांक)	11.1	13.7	10.4	14.4
3. नकद खंड कारोबार (करोड़ रुपए)	9,56,185	15,78,856	19,45,285	35,51,038
4. बाजार पूंजीकरण (अवधि के अंत का) (करोड़ रुपए)	35,45,041	51,38,014	33,67,350	48,58,122
5. पी/ई अनुपात (अवधि के अंत का)	20.3	20.1	18.4	20.6

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)।

सारणी 2.38 : राष्ट्रीय शेयर बाजार में नकदी के मुकाबले डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार

वर्ष	(करोड़ रुपए)	
	डेरिवेटिव्स	नकदी
1	2	3
2002-03	4,39,862	6,17,989
2003-04	21,30,610	10,99,535
2004-05	25,46,982	11,40,071
2005-06	48,24,174	15,69,556
2006-07	73,56,242	19,45,285
2007-08	130,90,478	35,51,038

स्रोत : भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

VI. बैंक और वित्तीय संस्थाएं

2.147 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन से व्यावसायिक परिचालनों और वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी के वित्तीय कार्यनिष्पादन को समर्थन मिलना जारी रहा। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की कुल आस्तियों में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीडीपी की तुलना में एससीबी की आस्तियों का अनुपात (चालू मूल्यों पर कारक लागत पर) मार्च 2006 के अंत के 85.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 91.4 प्रतिशत हो गया, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के संबंध में बैंकिंग प्रणाली की तीव्रतर वृद्धि को सुझाता है। तथापि, लगातार दो साल सुदृढ़ वृद्धि होने के बाद, 2006-07 में बैंक ऋण में थोड़ी गिरावट आयी।

2.148 लगातार तीसरे साल, 2006-07 में ऋण और अग्रिम में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई (2005-06 के 31.8 प्रतिशत तथा 2004-05 के 33.2 प्रतिशत की तुलना में 30.6 प्रतिशत)। सभी प्रमुख चार सेक्टरों अर्थात् कृषि, उद्योग, सेवा और वैयक्तिक ऋण में समग्र ऋण⁶ में थोड़ी मंदी दिखायी दी। ऋण संबंधी मंदी भूसंपदा ऋण और वैयक्तिक ऋण में विशेष रूप से दिखायी दी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वृद्धि भी 2005-06 की 36.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2006-07 में कम होकर 24.0 प्रतिशत रह गयी। 'अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' को ऋण, जिसमें हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखी गयी थी, में भी 2006-07 के दौरान तेज गिरावट आयी। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण वृद्धि में काफी तेजी आयी। ऋण वृद्धि में थोड़ी मंदी तथा जमाराशियों में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) 2006-07 की दूसरी छमाही में कम हो गया। मार्च 2007 के अंत में, वृद्धिशील सीडीआर एक साल पहले के 110 प्रतिशत की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत (साल-दर-साल) था।

2.149 एक समूह के रूप में एससीबी का निवल लाभ 2005-06 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 27.0 प्रतिशत बढ़ गया। एससीबी के प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में तीव्र वृद्धि होने के बावजूद निवल लाभ में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ मोटे तौर पर पिछले वर्ष के अनुरूप है। मार्च 2007 के अंत में सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां मार्च 2006 के अंत के 3.3 प्रतिशत से और गिरकर 2.5 प्रतिशत हो गईं। मार्च 2006 के अंत में निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां भी मार्च 2007 के अंत के 1.2 प्रतिशत से गिरकर 1.0 प्रतिशत हो गईं। एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 12.3 प्रतिशत के पिछले साल के स्तर पर बना रहा, जो यह सुझाता है कि पूंजी में वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के अनुरूप रही (सारणी 2.39)।

2.150 शहरी सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालनों में 2006-07 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में एससीबी की वृद्धि 24.3 प्रतिशत थी। जहां ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य आस्तियों में तीव्र वृद्धि देखी गई, निवेशों में वृद्धि में कमी आई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का निवल लाभ पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान मुख्यतः प्रावधानों, आकस्मिक व्ययों और करों में वृद्धि के कारण घट गया। 2006-07 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ जैसा कि कुल तथा प्रतिशत के रूप में एनपीए (सकल और निवल) में आई गिरावट में दिखाई देता है (सारणी 2.40)।

2.151 मार्च 2007 के अंत में सात वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा टीएफसीआइ रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित थीं। इनमें से, 5 वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) रिजर्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन थीं। जनता की जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली परंतु 500 करोड़ रुपए और अधिक की आस्तियां रखनेवाली वित्तीय संस्थाएं रिजर्व बैंक के सीमित परोक्ष पर्यवेक्षण के अधीन हैं। टीएफसीआइ इस श्रेणी में आता है, जबकि आइआइबीआइ ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। एनबीएफसी विनियमावली से आइएफसीआइ को दी गई छूट अगस्त 2007 में हटा ली गई तथा अब इसका विनियमन प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के रूप में किया जा रहा है।

2.152 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता (कुल रूप में) 2000-01 और 2004-05 के बीच गिरावट दर्शाने के बाद अगले दो वर्षों में बढ़ गई। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय संस्थाओं, विशेषज्ञताप्राप्त वित्तीय संस्थाओं और निवेश

⁶ 51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित सेक्टर-वार ऋण आंकड़ों के अनुसार।

सारणी 2.39 : बैंक समूहों के महत्वपूर्ण पैरामीटर

(प्रतिशत)

बैंक समूह	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
परिचालन व्यय / कुल आस्तियाँ					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.3	2.2	2.1	2.1	1.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.1	2.0	2.0	2.1	1.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
विदेशी बैंक	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8
स्प्रेड / कुल आस्तियाँ					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.9	3.0	2.9	2.9	2.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3
विदेशी बैंक	3.4	3.6	3.3	3.6	3.7
निवल लाभ / कुल आस्तियाँ					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.2	1.2	0.3	0.6	0.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9
विदेशी बैंक	1.6	1.7	1.3	1.5	1.7
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8.8	7.2	5.2	3.3	2.5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	9.4	7.8	5.5	3.6	2.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	8.9	7.6	6.0	4.4	3.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	7.6	5.0	3.6	1.7	1.9
विदेशी बैंक	5.3	4.6	2.9	2.0	1.8
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4.4	2.9	2.0	1.2	1.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4.5	3.0	2.1	1.3	1.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5.5	3.9	2.7	1.7	1.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	4.6	2.4	1.9	0.8	1.0
विदेशी बैंक	1.8	1.5	0.9	0.8	0.7
सीआरएआर					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12.6	13.2	12.9	12.2	12.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.8	13.7	12.5	11.7	12.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.3	10.2	12.1	12.6	12.0
विदेशी बैंक	15.2	15.0	14.0	13.0	12.4

संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के दौरान हुई क्रमशः 41.0 प्रतिशत तथा 38.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना

में 2006-07 के दौरान क्रमशः 12.9 प्रतिशत तथा 82.8 प्रतिशत बढ़ गई (सारणी 2.41)।

सारणी 2.40 : शहरी सहकारी बैंक -
चुनिंदा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2005-06	2006-07
1	2	3
प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)		
जमाराशि	8.6	6.1
ऋण	5.2	9.8
वित्तीय संकेतक[@] (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
परिचालन लाभ	36.0	2.2
निवल लाभ	104.8	-14.0
स्प्रेड	2.2	2.3
सकल अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)	18.9	17.0
[@] : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित।		

2.153 वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन 2005-06 में जुटाए गए संसाधनों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थे। संसाधन जुटाने के लिए चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की सकल छत्र सीमाएं 31 मार्च 2006 के 15,157 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 मार्च 2007 को 19,001 करोड़ रुपए कर दी गईं। छत्रसीमा के तहत इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए सकल बकाया संसाधन 31 मार्च 2006 के 1,977 करोड़ रुपए (सकल सीमा का 13.1 प्रतिशत) से बढ़कर 30 मार्च 2007 को 3,293 करोड़ रुपए (समस्त सीमा का 17.3 प्रतिशत) हो गए। 30 मार्च 2007 को बकाया स्थिति के आधार पर वित्तीय संस्थाओं ने संसाधनों का बड़ा भाग (2,540 करोड़ रुपए) वाणिज्यिक पत्र के जरिए जुटाया, उसके बाद जमा प्रमाणपत्र (663 करोड़ रुपए)

**सारणी 2.41 : वित्तीय संस्थाएं -
चुनिंदा निष्पादन संकेतक**

संकेतक	2005-06	2006-07
1	2	3
तुलनपत्र संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
परिचालन लाभ	1.4	2.1
निवल लाभ	1.0	1.5
स्प्रेड	1.8	1.6
संसाधन प्रवाह (करोड़ रुपए)		
स्वीकृतियां	27,666	31,238
संवितरण	21,146	38,656
टिप्पणी : 1. तुलनपत्र संकेतक के आंकड़े आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, और एगिजम बैंक से संबंधित हैं।		
2. संसाधन प्रवाह के आंकड़े एआइएफआइ (आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ), विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं (आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर तथा टीएफसीआइ) और निवेश संस्थाओं (एलआइसी तथा जीआइसी, उनकी पूर्व सहयोगी संस्थाओं के साथ) से संबंधित हैं।		

तथा मीयादी जमाराशियों (89 करोड़ रुपए) का स्थान था। इस अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था ने मीयादी मुद्रा अथवा अंतर-कंपनी जमाराशि के रूप में संसाधन नहीं जुटाए।

2.154 वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्दिष्ट मानदंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर बना रहा। चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय 2005-06 के 2,555 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 2,598 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की प्रवृत्ति के अनुरूप, वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय 2005-06 के 1,353 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2006-07 में 1,913 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, पिछले साल देखी गई तीव्र वृद्धि के विपरीत, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। फलस्वरूप, परिचालन लाभ में 73.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई (2005-06 के 1,993 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 3,460 करोड़ रुपए)। यह कर के लिए चिह्नित उच्चतर प्रावधानों के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में भी दिखाई दिया।

2.155 जमा लेनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की आस्तियां/देयताएं 2005-06 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की अधिक उच्चतर दर से बढ़ीं (सारणी 2.42)। उधार, जो एनबीएफसी की निधियों का एक प्रमुख स्रोत है, वर्ष के दौरान 30.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जनता की जमाराशियों में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई जो जुटाए गए संसाधनों के स्वरूप में बदलाव को दर्शाता है। आस्ति पक्ष में, ऋण तथा अग्रिम और किराया खरीद आस्तियां कुल मिलाकर कुल आस्तियों के तीन-चौथाई से अधिक थीं। 2006-07 के दौरान जहां ऋण और अग्रिम में 0.8 प्रतिशत की सीमांत गिरावट आई, किराया खरीद आस्तियों में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनबीएफसी का एक नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति

**सारणी 2.42 : एनबीएफसी - डी (आरएनबीसी को छोड़कर)
के समेकित तुलनपत्र**

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में	
	2006	2007अ
1	2	3
देयताएं		
1. प्रदत्त पूंजी	1,827 (4.8)	2,289 (4.8)
2. रिजर्व और अधिशेष	5,625 (14.9)	5,969 (12.4)
3. जनता की जमाराशि	2,447 (6.5)	2,042 (4.3)
4. उधार	24,942 (65.9)	32,563 (67.8)
5. अन्य देयताएं	2,987 (7.9)	5,136 (10.7)
कुल देयताएं / आस्तिचाँ	37,828	47,999
आस्तिचाँ		
1. निवेश		
i) अनुमोदित प्रतिभूतियां@	292	241
ii) अन्य निवेश	4,034	7,267
2. ऋण और अग्रिम	10,686 (28.2)	10,602 (22.1)
3. किराया खरीद आस्तियां	20,008 (52.9)	26,048 (54.3)
4. उपस्कर पट्टा आस्तियां	1,502 (4.0)	1,334 (2.8)
5. बिल संबंधी कारोबार	44 (0.1)	6 (0.0)
6. अन्य आस्तियां	1,261 (3.3)	2,500 (5.2)
अ : अनंतिम		
@ : एसएलआर आस्तियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' एवं 'भाररहित मीयादी जमाराशियां' शामिल हैं।		
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।		
स्रोत : वार्षिक विवरणियां		

वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 से प्रभावी हुआ। उत्पादक/आर्थिक कार्यकलापों के लिए वास्तविक/भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करनेवाली कंपनियों को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस नए वर्गीकरण के अनुसार, कुल आस्तियों/देयताओं में एएफसी का हिस्सा सर्वाधिक (51.5 प्रतिशत) था, जिसके बाद किराया खरीद वित्त कंपनियों (35.7 प्रतिशत) तथा ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) का स्थान था। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान जहां उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों में गिरावट आई जो मुख्यतः एनबीएफसी के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है, वहीं ऋण तथा निवेश समूह की आस्तियों में वृद्धि हुई।

2.156 तीन आरएनबीसी की आस्तियों में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर भारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा बांडों/डिबेंचरों के रूप में उनकी आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि एससीबी की सावधि जमा राशियों / जमा प्रमाणपत्रों तथा अन्य निवेशों में गिरावट दर्ज की गई (सारणी 2.43)। 2006-07 में आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधियों में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.157 कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के समर्थन से 2006-07 के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की गई। लगातार तीसरे साल 30 प्रतिशत से अधिक पर ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में तेज वृद्धि के बावजूद बैंक अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में समर्थ रहे। जोखिम भारित आस्तियों में तेज वृद्धि के बावजूद, उनका पूंजी पर्याप्तता का स्तर पिछले साल के स्तर पर बना रहा। वर्ष के दौरान आस्ति की गुणवत्ता, जैसाकि सकल और निवल अनर्जक आस्तियों के स्तर में दिखाई देता है, में और सुधार आया।

सारणी 2.43 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की प्रोफाइल

(करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में	
	2006	2007 अ
1	2	3
I. आस्तियां (I से V तक)	21,891	23,172
(i) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2,346	3,317
(ii) अनु.वा.बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र में निवेश	6,090	5,604
(iii) बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र*	9,577	11,700
(iv) अन्य निवेश	1,658	1,156
(v) अन्य आस्तियां	2,220	1,395
II. निवल स्वाधिकृत निधियां	1,183	1,366
III. कुल आय (I+II)	1,620	1,893
(i) निधि आय	1,616	1,886
(ii) शुल्क आय	3	8
IV. कुल व्यय (I+II+III)	1,439	1,648
(i) वित्तीय लागत	1,165	1,230
(ii) परिचालन लागत	159	284
(iii) अन्य लागत	114	134
V. कराधान के लिए प्रावधान	22	44
VI. परिचालन लाभ (पीबीटी)	180	246
VII. निवल लाभ (पीएटी)	158	201

अ. : अर्नतिम

* : सरकारी कंपनियों / सरकारी क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं / निगमों के

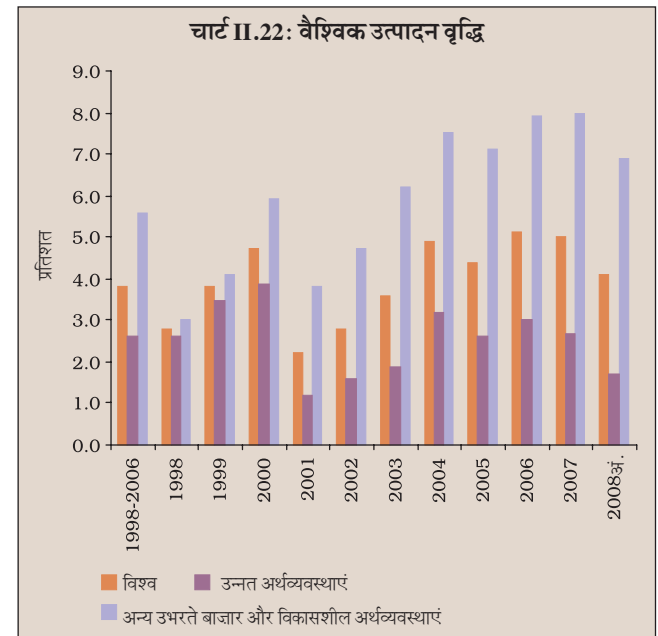
नोट : 1. पीबीटी - कर पूर्व लाभ. 2. पीएटी - करोत्तर लाभ.

VII. बाह्य क्षेत्र

वैश्विक आर्थिक संभावना

2.158 2007 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप में सुदृढ़ता बनी रही, यद्यपि 2006 की सुदृढ़ स्थिति की तुलना में इसमें कमी आई। कुल मिलाकर क्रय शक्ति समता भारांक के आधार पर मापा गया वैश्विक जीडीपी 2006 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 5.0 प्रतिशत बढ़ने - लगातार चौथे वर्ष प्रवृत्ति के काफी ऊपर - का अनुमान है (चार्ट II.22)। आशा से अधिक तीसरी तिमाही की वृद्धि को देखते हुए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से युनाइटेड स्टेट्स में, वर्ष 2007 के अंत तक कार्यकलाप में तीव्र मंदी आई क्योंकि अमरीकी सब प्राइम बंधक बाजार की समस्या का अप्रत्यक्ष प्रभाव व्यापक तौर पर वित्तीय बाजारों तथा संस्थाओं पर पड़ा। इसके विपरीत उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ गति से बढ़ती रहीं, बावजूद इसके कि वर्ष 2007 के अंत तक कार्यकलाप में थोड़ी कमी आई। चीन और भारत, जिनमें 2007 में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के अगुवा बने रहे। उत्पादकता में अच्छी वृद्धि द्वारा वृद्धि को गति मिली क्योंकि ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्रमिक रूप से समन्वित हो गए। इसके अलावा, मूल्य में वृद्धि के कारण पण्य उत्पादकों (तेल और अन्य कच्चा माल) के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों का लाभ इन देशों को मिला।

2.159 2007 की चौथी तिमाही के दौरान, अधिकांश उन्नत देशों में वृद्धि में गत वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में कमी आई। इसके विपरीत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में तेजी आई (सारणी 2.44)।



सारणी 2.44: वृद्धि दरें - वैश्विक परिदृश्य

(प्रतिशत)

देश / क्षेत्र	2004	2005	2006	2007	2008 प्र	2009 प्र	2006				2007			
							ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. विश्व उत्पादन	4.9	4.4	5.1	5.0	4.1	3.9								
I.1 विकसित अर्थव्यवस्थाएं														
यूरो क्षेत्र	2.1	1.6	2.8	2.6	1.7	1.2	2.2	2.7	2.8	3.3	3.0	2.5	2.7	2.2
जापान	2.7	1.9	2.4	2.1	1.5	1.5	3.0	2.1	1.6	2.2	2.6	1.6	1.9	2.0
कोरिया	4.7	4.2	5.1	5.0	4.2	4.4	6.3	5.1	4.6	4.0	4.0	5.0	5.2	5.7
यूके	3.3	1.8	2.9	3.1	1.8	1.7	2.4	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	2.8
अमरीका	3.6	3.1	2.9	2.2	1.3	0.8	3.3	3.2	2.4	2.6	1.9	1.9	2.8	2.5
ओईसीडी देश	3.1	2.5	3.1	2.7	1.8	1.7	3.2	3.3	2.8	3.1	2.8	2.5	3.0	2.7
I.2 उभरती अर्थव्यवस्थाएं														
अर्जेंटीना	9.0	9.2	8.5	8.7	7.0	4.5	8.6	7.9	8.7	8.6	8.0	8.7	8.7	9.1
ब्राजील	5.7	3.2	3.8	5.4	4.9	4.0	3.9	1.1	3.2	4.4	4.3	5.4	5.7	6.2
चीन	10.1	10.4	11.6	11.9	9.7	9.8	10.3	10.9	10.7	10.7	11.1	11.9	11.5	11.2
भारत	7.5	9.4	9.6	9.0	8.0	8.0	10.0	9.6	10.2	8.7	9.7	9.2	9.3	8.8
इंडोनेशिया	5.0	5.7	5.5	6.3	6.1	6.3	5.0	5.0	5.5	6.1	6.0	6.3	6.5	6.3
मलेशिया	6.8	5.0	5.9	6.3	5.0	5.3	6.0	6.1	6.0	5.7	5.3	5.7	6.7	7.3
थाईलैंड	6.3	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	6.1	5.0	4.5	4.3	4.3	4.4	4.9	5.7
II. विश्व व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएं)	10.7	7.6	9.2	6.8	5.6	5.8								

प्र : आइएमएफ प्रक्षेपण ।

टिप्पणी : स्तंभ 2 से 5 के भारत के आँकड़े क्रमशः राजकोषीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 से संबंधित हैं।

स्रोत : आइएमएफ, दि इकोनॉमिस्ट, एवं दि ओईसीडी

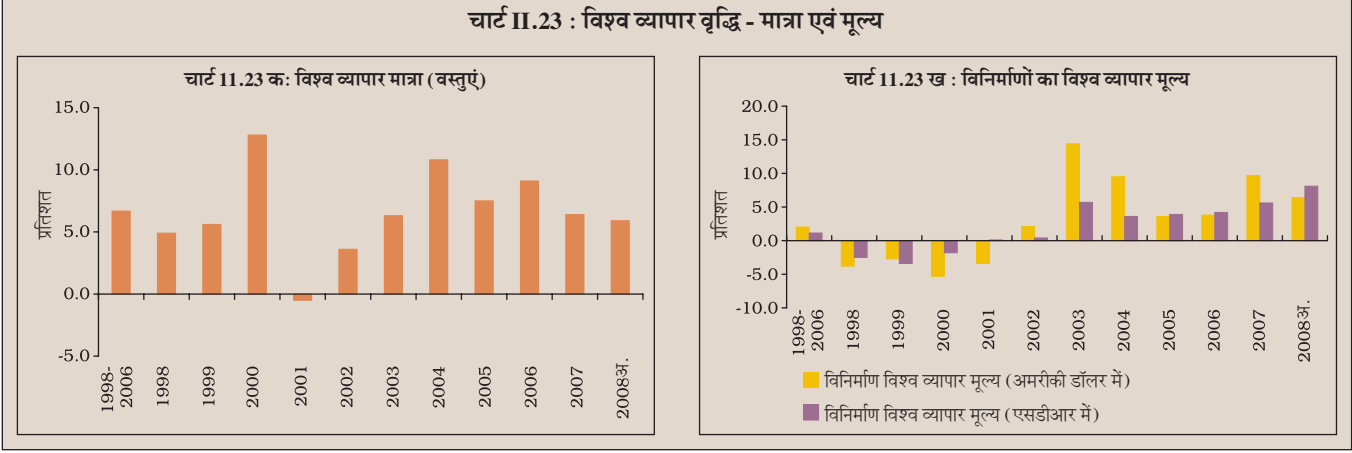
2.160 आइएमएफ के अनुसार, अमरीका में आवास में बनी हुई मंदी से मांग में कमी रहेगी तथा यह वित्तीय बाजारों के लिए अनिश्चितता का एक स्रोत होगा। फलस्वरूप, आइएमएफ द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अमरीकी अर्थव्यवस्था में पहले से उपलब्ध कराई गई पर्याप्त मौद्रिक और राजकोषीय उत्प्रेरणा के बावजूद 2008 में 1.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी (सारणी 2.44)। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी व्यापारिक और वित्तीय असर के फैलाव के कारण मंदी आएगी तथा विशेष रूप से आवास बाजार कुछ यूरोपीय देशों में मंदी के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। कुछ देशों में ओवरहीटिंग को रोकने के प्रयासों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के असर के फैलाव तथा पण्य मूल्यों में कुछ कमी को दर्शाते हुए यह उम्मीद है कि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी आएगी। तथापि, सभी क्षेत्रों में वृद्धि प्रवृत्ति के ऊपर बनी रहेगी।

2.161 आइएमएफ के अनुसार, विश्व व्यापार (माल और सेवाओं) में वृद्धि पिछले साल के 6.8 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2008 में मात्रा के रूप में 5.6 प्रतिशत रह जाने की आशा है (चार्ट II.23क)। अन्य उभरते बाजार और विकासशील देशों के निर्यात (माल और सेवाएं) में 2008 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है (एक साल पहले 8.9 प्रतिशत), जबकि उन्नत देशों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 5.8 प्रतिशत) होने की आशा है। विश्व स्तर पर लेनदेन वाले विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें

2006 में अमरीकी डालर के रूप में 3.8 प्रतिशत (एसडीआर के रूप में 4.2 प्रतिशत) से बढ़कर 2007 में अमरीकी डालर के रूप में 9.7 प्रतिशत (एसडीआर के रूप में 5.6 प्रतिशत) हो गई (चार्ट II.23ख)। आइएमएफ के अनुसार, उभरते तथा विकासशील देशों में निजी निवल पूंजी प्रवाह 2006 के 231.9 बिलियन अमरीकी डालर से काफी बढ़कर 2007 में 605.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मुख्यतः अन्य निजी पूंजी प्रवाहों में अनुमानित गिरावट के कारण 2008 में पूंजी प्रवाह काफी कम होकर 330.7 बिलियन अमरीकी डालर रह जाने का अनुमान है।

2.162 अल्पावधि वैश्विक वृद्धि के प्रति समग्र जोखिम संतुलन की संभावना का झुकाव अधोमुखी बना हुआ है। सबसे बड़ी जोखिम वित्तीय बाजारों में अभी तक उद्घाटित न हुई घटनाओं से, विशेष रूप से यूएस सब-प्राइम बंधक बाजार तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित संरचित ऋणों पर अधिक हानियों की संभावना से, आती है जो वित्तीय प्रणाली के तुलनपत्रों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। ऋणात्मक वित्तीय आघातों और देशी मांग, विशेष रूप से आवास बाजार के जरिए, के बीच की अंतःक्रिया अमरीका के लिए तथा थोड़ी कम मात्रा में पश्चिमी यूरोप और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग के अनुमानों से कुछ ऊर्ध्वमुखी संभावना है परंतु ये अर्थव्यवस्थाएं व्यापार और वित्तीय प्रभाव-प्रसार के प्रति सुभेद्य बनी हुई हैं।

चार्ट II.23 : विश्व व्यापार वृद्धि - मात्रा एवं मूल्य



2.163 2007-08 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अनिश्चितता तथा उथल-पुथल की स्थितियां देखी गईं, जो अमरीकी सब-प्राइम बाजार की समस्याओं द्वारा प्रेरित थीं। यह अशांति बाद में ऋण बाजार और अल्पावधि मुद्रा बाजार तक फैल गई, जिसके फलस्वरूप अगस्त 2007 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की रात भर की ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि हुई जब बैंकों ने अपनी चलनिधि को संरक्षित करना चाहा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजारों के चलनिधि आघात को कम करने तथा बड़ी वित्तीय संस्थाओं के बीच शोधनीयता के मुद्दों का समाधान करने के लिए परंपरागत तथा गैर परंपरागत दोनों तरह के उपायों से प्रतिसाद व्यक्त किया। कुछ केंद्रीय बैंकों, उल्लेखनीय रूप से ईसीबी, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया तथा स्विस् नेशनल बैंक ने अव्यक्त रूप से वित्तीय उथल-पुथल को अनिवार्यतः चलनिधि की सख्ती की समस्या के रूप में देखते हुए अंतर बैंक बाजारों को चलनिधि प्रदान कर प्रतिसाद व्यक्त किया। इन केंद्रीय बैंकों ने अपने संबंधित मुद्रा बाजारों में व्यवस्थित स्थितियों के आश्वासन के उद्देश्य से परिचालनों को परिष्कृत कर चलनिधि प्रदान की। दूसरी ओर, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा बैंक ऑफ कनाडा जैसे कुछ केंद्रीय बैंकों ने बाजार की आघातों, जैसाकि आर्थिक कार्यकलाप में मंदी लंबे समय तक चलने के खतरों सहित चलनिधि की जब्ती तथा वित्तीय स्थिरता के प्रति व्यापक खतरों दोनों रूपों में प्रदर्शित हुआ, से निपटने के लिए अधिक विशाखीकृत रूप में प्रतिसाद व्यक्त किया। तदनुसार, उन्होंने सामान्य और विशेष सुविधाओं के माध्यम से मुद्रा बाजारों में चलनिधि का अंतर्वेश करने के लिए कार्रवाई की। उन्होंने केंद्रीय बैंक से चलनिधि प्राप्त करने के लिए पात्र प्रतिभूतियों की श्रेणी में भी शिथिलता लाई। साथ ही इस आशंका के बीच कि सब प्राइम संकट एक बड़े ऋण संकट में बदल सकता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव वास्तविक क्षेत्र पर पड़ेगा, उन्होंने नीति दरों में भी भारी कटौती की। यूएस फेड निवेश बैंकों तथा बीमा कंपनियों जैसी बैंकेतर संस्थाओं में पैदा हुई समस्याओं का समाधान करने में भी लगा हुआ था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अदला-बदली संबंधी प्रतिभूतियों के लिए सामान्यीकृत तथा संस्था विशिष्ट आपातकालीन चलनिधि तथा सुविधाएं प्रदान कीं।

2.164 दिसंबर 2007 में शुरू हुए केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेप के दूसरे चरण में (पहला चरण अगस्त-सितंबर 2007 में था), यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और स्विस् नेशनल बैंक (एसएनबी) ने समन्वित तरीके से चलनिधि डाली। फेडरल रिजर्व द्वारा की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित भी शामिल थे - बट्टे पर ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों के प्रति अस्थायी मीयादी नीलामी सुविधा (टीएएफ) की स्थापना; ईसीबी और एसएनबी के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप व्यवस्था की स्थापना जिससे ईसीबी और एसएनबी को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उपयोग के लिए क्रमशः 20 बिलियन अमरीकी डालर और 6 बिलियन अमरीकी डालर तक के डालर प्राप्त होंगे। इसके अलावा, 11 मार्च 2008 को मीयादी प्रतिभूति उधार सुविधा तथा 22 अप्रैल 2008 को प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधा (पीडीसीएफ) की घोषणा की गई। अलग-अलग टीएएफ नीलामी का आकार कार्यक्रम के आरंभ में 20 बिलियन अमरीकी डालर था जिसे बढ़ाकर मई 2008 में 75 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।

2.165 कुछ केंद्रीय बैंकों ने 2007 की तीसरी तिमाही से, जब वित्तीय बाजार में उथल-पुथल सामने आया, नीति दरों में कटौती की। 18 सितंबर 2007 से 30 अप्रैल 2008 के दौरान, यूएस फेडरल रिजर्व ने, जून 2004 तथा जून 2006 के बीच नीति दर में सतरह बार वृद्धि कर उसे 5.25 प्रतिशत करने के बाद, 275 आधार अंक घटाकर उसे 2.00 प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फरवरी तथा अप्रैल 2008 में प्रत्येक बार अपनी बैंक दर में 25 आधार अंकों की कमी कर उसे 5.0 प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ कनाडा ने दिसंबर 2007 एवं जनवरी 2008 में प्रत्येक बार अपनी दर में 25 आधार अंकों की तथा मार्च एवं अप्रैल 2008 में प्रत्येक बार 50 आधार अंकों की कटौती कर उसे 3.0 प्रतिशत कर दिया। यूरो क्षेत्र, जापान और कोरिया सहित कुछ देशों के केंद्रीय बैंकों ने 2007 की अंतिम तिमाही से अपनी दरों में बदलाव नहीं किया है। कुछ केंद्रीय बैंकों ने हाल के महीनों में अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि की, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (फरवरी-मार्च 2008 में नकद दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत कर दिया),

पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (उधार दर सितंबर 2007 के 7.29 प्रतिशत से बढ़ाकर दिसंबर 2007 में 7.47 प्रतिशत कर दिया गया); बैंकों सेंट्रल डि चिली (बेंचमार्क उधार दर अक्टूबर 2007 के 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 2008 में 6.25 प्रतिशत तथा जून 2008 में 6.75 प्रतिशत और जुलाई 2008 में 7.25 प्रतिशत कर दी गई); तथा बैंकों सेंट्रल डो ब्रासिल (रात भर की सेलिक दर 50 आधार अंक बढ़ाकर अप्रैल 2008 में 11.75 प्रतिशत, जून 2008 में 12.25 प्रतिशत तथा 75 आधार अंक बढ़ाकर जुलाई 2008 में 13 प्रतिशत कर दी गई) शामिल हैं।

2.166 यूएस सब प्राइम संकट का कोई उल्लेखनीय असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि इक्विटी बाजार पिछले खंड में दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की गतिविधियों के अनुरूप अस्थिर हो गया। तथापि भारत में चलनिधि की अधिशेष स्थितियों और मुद्रास्फीति दर में वृद्धि ने नीतिगत प्रतिसादों को आवश्यक बना दिया। रिपो दर को 30 मार्च 2007 के 7.75 प्रतिशत से संशोधित कर 11 जून 2008 को 8.00 प्रतिशत, 24 जून 2008 को 8.50 प्रतिशत तथा 30 अगस्त 2008 से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर को भी क्रमिक रूप से संशोधित कर 3 मार्च 2007 के 6.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 जून 2008 को 8.75 प्रतिशत तथा और बढ़ाकर 30 अगस्त 2008 से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया।

भारत का पण्य व्यापार

2.167 2007-08 के दौरान भारत के पण्य व्यापार (निर्यात और आयात दोनों) में उच्च वृद्धि बनी रही। डीजीसीआइएण्डएस के अनुसार, 2007-08 में 159.0 बिलियन अमरीकी डालर पर निर्यात में, पिछले साल के 22.6 प्रतिशत की तुलना में, 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2007-08 के दौरान 239.7 बिलियन अमरीकी डालर पर आयात में एक साल पहले के 24.5 प्रतिशत की तुलना में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी (सारणी 2.45)।

2.168 2007-08 के दौरान 80.6 बिलियन अमरीकी डालर पर व्यापार घाटे में 2006-07 की तुलना में 21.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दिखाई दी। 2007-08 के दौरान तेल खाते पर व्यापार घाटा 54.8 बिलियन अमरीकी डालर (तीन साल पहले 38.5 बिलियन अमरीकी डालर) तथा तेल से इतर व्यापार घाटा 25.9 बिलियन अमरीकी डालर (एक साल पहले 20.9 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया। पांच वर्ष की अवधि (2003-08) के दौरान निर्यातों में वार्षिक वृद्धि का औसत 24.7 प्रतिशत था। फलस्वरूप, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे निर्यातक देशों में एक बना रहा (सारणी 2.46)।

2.169 2007-08 (अप्रैल-मार्च) के लिए पण्यवार निर्यात आंकड़ों से प्राथमिक उत्पादों तथा विनिर्मित माल के निर्यात की वृद्धि में बढ़त दिखाई देती है (सारणी 2.47)।

सारणी 2.45 : भारत का पण्य व्यापार

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2005-06	2006-07	2007-08 सं	2007-08 सं 2008-09 अ	
				अप्रैल-जून	
1	2	3	4	5	6
निर्यात	103.1 (12.7)	126.4 (13.8)	159.0 (13.6)	35.0	42.8
आयात	149.2 (18.4)	185.7 (20.3)	239.7 (20.6)	56.5	73.3
तेल	44.0 (5.4)	57.1 (6.2)	79.6 (6.8)	17.0	25.6
तेल से इतर	105.2 (13.0)	128.6 (14.0)	160.0 (13.7)	39.5	47.7
व्यापार संतुलन	-46.1 (5.7)	-59.4 (6.5)	-80.6 (6.9)	-21.5	-30.4
तेल से इतर	-13.8	-20.9	-25.9	-10.9	..
व्यापार संतुलन	(1.7)	(2.3)	(2.2)		
<i>घट-बढ़ (प्रतिशत)</i>					
निर्यात	23.4	22.6	25.8	20.4	22.4
आयात	33.8	24.5	29.0	38.0	29.8
तेल	47.3	30.0	39.4	23.9	50.4
तेल से इतर	28.8	22.2	24.4	45.1	20.9

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े रुपय में जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस
सं : संशोधित अ : अनंतिम

2.170 कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग माल, रत्न एवं आभूषण तथा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात वृद्धि के प्रमुख वाहक थे क्योंकि इन उत्पादों ने मिलाकर 2007-08 के दौरान निर्यात वृद्धि में लगभग 69 प्रतिशत अंशदान किया। 2007-08 के दौरान प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में 37.5

सारणी 2.46: वैश्विक पण्य निर्यात में वृद्धि

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	2005	2006	2007	2007 2008	
				जनवरी-मार्च	
1	2	3	4	5	6
विश्व	14.0	15.3	15.0	13.2	22.9
औद्योगिक देश	8.5	12.4	13.6	13.5	20.4
यूएसए	10.8	14.7	12.2	10.8	17.1
फ्रान्स	3.8	9.9	12.0	10.3	22.9
जर्मनी	7.3	14.7	18.5	21.2	20.9
जापान	5.2	9.2	9.2	5.4	28.7
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	22.0	19.1	16.8	13.0	26.0
तेल से इतर विकासशील देश	19.3	19.4	17.9	27.8	21.3
चीन	28.4	27.2	25.6	27.8	21.3
भारत	29.9	21.4	20.3	15.2	33.8
कोरिया	12.0	14.4	14.2	14.6	17.4
सिंगापुर	15.6	18.4	10.1	9.9	21.3
इंडोनेशिया	22.9	18.3	16.8	9.7	34.2
मलेशिया	12.0	14.0	9.6	7.6	19.1
थाईलैंड	14.5	18.5	16.8	17.2	21.3

स्रोत: (1) आइएमएफ (www.imfstatistics.org)।
(2) डीजीसीआइएण्डएस, भारत के लिए

सारणी 2.47: प्रमुख पण्य निर्यात

पण्य समूह	बिलियन अमरीकी डॉलर			घट-बढ़ (प्रतिशत)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-मार्च		
1	2	3	4	5	6	7
1. प्राथमिक उत्पाद	16.4	19.7	27.1	20.8	20.2	37.5
जिसमें से:						
क) कृषि और संबद्ध उत्पाद	10.2	12.7	18.1	20.5	24.2	42.4
ख) अयस्क और खनिज	6.2	7.0	9.0	21.4	13.6	28.6
2. विनिर्मित वस्तुएं	72.6	84.9	101.1	19.5	17.0	19.1
जिसमें से:						
क) रसायन और संबंधित उत्पाद	14.8	17.3	20.5	18.7	17.4	18.0
ख) इंजीनियरिंग वस्तुएं	21.7	29.6	36.7	25.2	36.1	24.2
ग) वस्त्र एवं वस्त्रोत्पाद	16.4	17.4	19.0	21.0	5.9	9.5
घ) रत्न और आभूषण	15.5	16.0	19.7	12.8	2.9	23.0
3. पेट्रोलियम उत्पाद	11.6	18.7	24.9	66.5	60.5	33.1
4. कुल निर्यात	103.1	126.4	159.0	23.4	22.6	25.8

स्रोत: डीजीसीआइएण्डएस.

प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दिखाई दी, जिसका कारण था कृषि और संबद्ध उत्पादों (42.4 प्रतिशत) तथा लौह अयस्क (47.2 प्रतिशत) के निर्यातों में वृद्धि। 2007-08 के दौरान विनिर्मित माल के निर्यात में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 17.0 प्रतिशत) दर्ज की गई। विनिर्मित माल के भीतर रसायन और संबद्ध उत्पाद तथा रत्न और आभूषण ने निर्यात में उच्चतर वृद्धि दिखाई, जबकि इंजीनियरिंग माल के निर्यात में कमी दिखाई दी। 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 60.5 प्रतिशत) दर्ज की गई। गंतव्यवार, समग्र निर्यात में 13.0 प्रतिशत हिस्से (एक साल पहले 14.9 प्रतिशत)

के साथ अमरीका भारत के लिए अकेला सबसे बड़ा बाजार बना रहा। अन्य प्रमुख गंतव्य थे - यूएई (9.7 प्रतिशत), चीन (6.8 प्रतिशत), सिंगापुर (4.3 प्रतिशत), यूके (4.1 प्रतिशत), हांगकांग (4.0 प्रतिशत), जर्मनी (3.2 प्रतिशत) तथा नीदरलैंड (3.0 प्रतिशत)। क्षेत्रवार, ईयू, पूर्वी यूरोप तथा एशिया के विकासशील देशों को निर्यात बढ़ गया, जबकि ओपेक तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों को निर्यात में कमी आई (सारणी 2.48)।

2.171 तेल तथा तेल से इतर दोनों तरह के आयातों में उच्च वृद्धि के कारण 2007-08 के दौरान आयातों में वृद्धि की गति बनी रही (देखें

सारणी 2.48: भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश

समूह/देश	बिलियन अमरीकी डॉलर			घट-बढ़ (प्रतिशत)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-मार्च		
1	2	3	4	5	6	7
1. ओईसीडी देश	45.8	52.0	61.7	25.6	13.5	18.6
जिसमें से:						
क) ईयू	22.4	25.8	32.2	27.6	15.1	24.9
ख) उत्तरी अमरीका	18.4	20.0	22.0	25.6	8.7	10.0
यूएस	17.4	18.9	20.7	26.1	8.7	9.7
2. ओपीईसी	15.2	20.7	26.2	15.4	35.8	26.4
जिसमें से:						
यूएई	8.6	12.0	15.4	16.9	40.0	27.7
3. विकासशील देश	39.7	50.8	67.2	23.8	27.8	32.4
जिसमें से:						
क) एशिया	31.0	37.6	50.1	21.6	21.4	33.2
चीन	6.8	8.3	10.8	20.4	22.7	30.0
सिंगापुर	5.4	6.1	6.9	35.6	11.9	12.9
4. कुल निर्यात	103.1	126.4	159.0	23.4	22.6	25.8

स्रोत: डीजीसीआइएण्डएस.

सारणी 2.45)। 2007-08 के दौरान, पूंजीगत माल के आयात में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 25.0 प्रतिशत), जबकि सोने और चांदी में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 29.4 प्रतिशत)(सारणी 2.49)। स्रोतवार, चीन आयात का प्रमुख स्रोत था, 2007-08 में कुल आयात में उसका हिस्सा 11.3 प्रतिशत था। अन्य प्रमुख स्रोत थे - सऊदी अरब (8.1 प्रतिशत), यूएई (5.6 प्रतिशत), यूएस (5.5 प्रतिशत), ईरान (4.6 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (4.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.0 प्रतिशत) तथा आस्ट्रेलिया (3.3 प्रतिशत)।

2.172 2008-09 (अप्रैल-जून) के दौरान, पण्य निर्यात में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई [2007-08 (अप्रैल-जून) में 20.4 प्रतिशत] तथा आयातों में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 38.0 प्रतिशत)। अप्रैल-जून 2008 में व्यापार घाटा 30.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जो अप्रैल-जून 2007 के 21.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 9.0 बिलियन अमरीकी डालर अधिक था।

भुगतान संतुलन

2.173 2007-08 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। व्यापार घाटे में काफी वृद्धि होने के बावजूद, चालू खाता घाटा नियंत्रण में था, हालांकि उच्चतर निजी विप्रेषणों और सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात की अगुवाई में अदृश्य खातों में अधिशेष के कारण यह 2006-07 की तुलना में कुछ अधिक था। तथापि उच्चतर चालू खाता घाटे का वित्तपोषण आसानी से पूंजीगत प्रवाहों के द्वारा किया गया, जो 2007-08 के दौरान काफी अधिक रहा। पूंजीगत प्रवाहों के घटकों में से एफआईआइ

सहित संविभाग निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा अल्पावधि व्यापार घाटा 2007-08 में काफी बढ़ गया। जावक एफडीआइ बढ़ता रहा जो बाजार और संसाधनों के रूप में वैश्विक विस्तार के लिए भारतीय कंपनियों की इच्छा को दर्शाता है।

चालू खाता

2.174 2006-07 के 63.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर व्यापार घाटा (भुगतान संतुलन आधार पर) 2007-08 में 90.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अदृश्य मदों में निवल अधिशेष 2006-07 के 53.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 72.7 बिलियन अमरीकी डालर था, जो 36.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। निवल अदृश्य अधिशेष के द्वारा पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 84.5 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 80.7 प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतितुलित हो गया। चालू खाता घाटा 2006-07 के 9.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 17.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2.50)।

2.175 2007-08 में अदृश्य प्राप्तियों में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (2006-07 में 28.3 प्रतिशत) (चार्ट II.24)। अदृश्य प्राप्तियों में मुख्य अंशदान विदेशी भारतीयों से प्रेषण, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, निवेश आय, यात्रा अर्जन और परिवहन का था। विदेश में कार्यरत भारतीयों से मुख्यतः विप्रेषण युक्त निजी अंतरण तथा देशी उपयोग के लिए अनिवासी रुपया खाते से स्थानीय आहरण 42.6 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 29.0 बिलियन अमरीकी डालर) था, जो 2007-08 में 47.1 प्रतिशत (2006-07 में 16.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। 2007-08

सारणी 2.49: भारत के प्रमुख आयात

समूह/पण्य	बिलियन अमरीकी डॉलर			घट-बढ़ (प्रतिशत)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-मार्च		
1	2	3	4	5	6	7
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद तथा संबन्धित सामग्री	44.0	57.1	79.6	47.3	30.0	39.4
खाद्य तेल	2.0	2.1	2.6	-17.9	4.2	21.3
लोहा और इस्पात	4.6	6.4	8.7	71.3	40.5	35.2
पूंजीगत वस्तुएं	37.7	47.1	58.4	49.9	25.0	24.1
मोती, मूल्यवान व कम मूल्यवान पत्थर	9.1	7.5	8.0	-3.1	-18.0	6.5
रसायन	7.0	7.8	9.9	22.5	12.1	26.2
सोना और चांदी	11.3	14.6	17.8	1.5	29.4	21.8
कुल आयात	149.2	185.7	239.7	33.8	24.5	29.0
<i>जापन:</i>						
तेल से इतर आयात	105.2	128.6	160.0	28.8	22.2	24.4
तेल से इतर आयात, सोना और चांदी को छोड़कर	93.9	114.0	142.2	33.1	21.4	24.7
मुख्यतः औद्योगिक निविष्टियां	87.5	104.7	130.0	34.7	19.6	24.2

* : सोना और चांदी छोड़कर तेल से इतर आयात, थोक उपभोक्ता वस्तुएं, विनिर्मित उर्वरक तथा व्यावसायिक उपकरण।

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस.

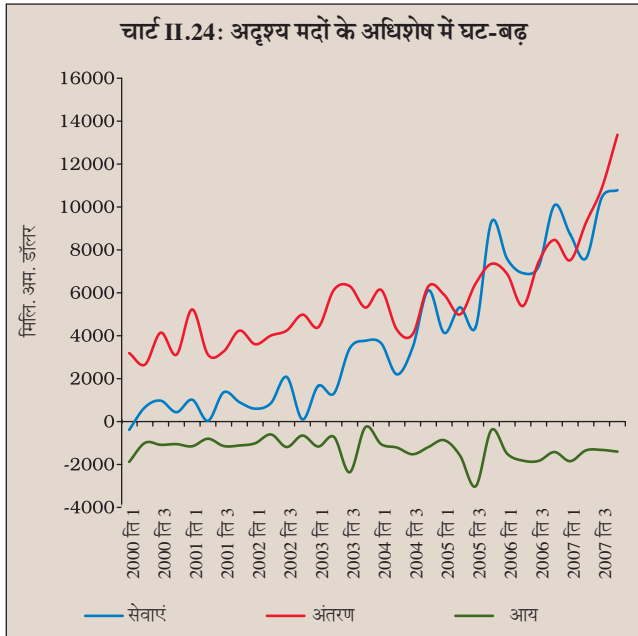
सारणी 2.50: भारत का चालू खाता

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06सं.	2006-07आं.सं.	2007-08प्रा.
1	2	3	4	5	6	7
I. व्यापारिक माल शेष	-10690	-13718	-33702	-51904	-63171	-90060
II. अदृश्य मदों का शेष (क+ख+ग)	17035	27801	31232	42002	53405	72657
क) सेवाएं	3643	10144	15426	23170	31810	37550
i) यात्रा	-29	1435	1417	1215	2438	2118
ii) परिवहन	-736	879	144	-2012	-18	-2107
iii) बीमा	19	56	148	-54	560	543
iv) जी.एन.आइ.ई.	65	28	-10	-215	-153	-51
v) विविध	4324	7746	13727	24236	28983	37047
जिसमें से : सॉफ्टवेयर सेवाएं	8863	12324	16900	22262	29033	37051
ख) अंतरण	16838	22162	20785	24687	28168	41017
i) अधिकारिक	451	554	260	194	227	239
ii) निजी	16387	21608	20525	24493	27941	40778
ग) आय	-3446	-4505	-4979	-5855	-6573	-5910
i) निवेश आय	-3544	-3757	-4095	-5262	-6018	-5239
ii) कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	98	-748	-884	-593	-555	-671
कुल चालू खाता	6345	14083	-2470	-9902	-9766	-17403

जीएनआईई : सरकारी, जो अन्यत्र शामिल नहीं है। सं. : संशोधित। आं.सं. : आंशिक रूप से संशोधित। प्रा : प्रारंभिक

में 40.3 बिलियन अमरीकी डालर की सॉफ्टवेयर सेवा का निर्यात किया गया जो 2006-07 के 32.6 प्रतिशत की तुलना में 28.8 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्शाता है। 2007-08 में अदृश्य मदों के भुगतान में 17.7 प्रतिशत (2006-07 में 29.3 प्रतिशत)की वृद्धि दर्ज की गई। अदृश्य भुगतान के प्रमुख घटक थे - यात्रा भुगतान, परिवहन, व्यवसाय सेवा भुगतान यथा व्यवसाय तथा प्रबंधन परामर्श; इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाएं; तथा लाभांश, लाभ और ब्याज भुगतान।



2.176 भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 2007-08 में 17.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कच्चे तेल, पूंजीगत माल तथा सोना और चांदी के आयात में उच्च वृद्धि की अगुवाई में व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। डीजीसीआइएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 के दौरान तेल से इतर आयातों में 24.4 प्रतिशत (2006-07 में 22.2 प्रतिशत) की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान आयात में तीव्र वृद्धि दर्शाने वाले अन्य प्रमुख तेल से इतर उत्पाद थे - खाद्य तेल, उर्वरक, लोहा और इस्पात, मोती, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान पत्थर, रसायन, वस्त्र, कोयला और कोक। डीजीसीआइएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 में तेल के आयात में 39.4 प्रतिशत (2006-07 में 30.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भारतीय बास्केट (ओमान, दुबई और ब्रेंट की किस्मों का मिश्रण) का औसत मूल्य पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 62.4 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर 2007-08 में 79.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल (65.5 अमरीकी डालर से 99.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल के बीच) हो गया।

पूंजी खाता

2.177 2007-08 के दौरान भारत में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर पूंजी का अंतर्वाह (निवल) हुआ, जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में यह 45.8 बिलियन अमरीकी डालर था (सारणी 2.51)। 2007-08 के दौरान अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर पूंजी प्रवाह के सभी घटकों में उच्चतर अंतर्वाह दर्ज किया गया।

2.178 विदेशी निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा तथा 2007-08 में 61.8 बिलियन अमरीकी डालर का अंतर्वाह हुआ। प्रत्यक्ष निवेश (अनिगमित

सारणी 2.51 : पूंजी प्रवाह (निवल)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2005-06सं.	2006-07आ.सं.	2007-08अ
1	2	3	4
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	3,034	8,479	15,545
संविभाग निवेश#	12,494	7,062	29,261
बाह्य सहायता	1,702	1,767	2,114
बाह्य वाणिज्यिक उधार	2,508*	16,155	22,165
एनआरआई जमाराशि	2,789	4,321	179
अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर बैंकिंग पूंजी	-1,416	-2,408	11,578
अल्पावधि ऋण	3,699	6,612	17,683
रुपया ऋण	-572	-162	-121
अन्य पूंजी	1,232	3,953	9,627
कुल	25,470	45,779	108,031

अ : अनंतिम. आं.सं.: आंशिक रूप में संशोधित. सं.: संशोधित.
 * : 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट का प्रभाव शामिल है।
 # : संविभाग निवेश में विदेशी वित्तीय संस्थाओं के निवल अंतर्वाह, भारतीय कंपनियों द्वारा एडीआर / जीडीआर तथा अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन शामिल हैं।

संस्थाओं की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा संबद्ध संस्थाओं के बीच अंतर - कंपनी ऋण लेनदेन सहित) के तहत भारत में 2007-08 के दौरान 32.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ जो पिछले साल की तुलना में उच्चतर था (सारणी 2.52)। एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि ने एफडीआई नीति के युक्तियुक्तकरण/ उदारीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाया। भारत की उदारीकरण नीति के अनुक्रम में, दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई। एफडीआई को मुख्य रूप से विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और निर्माण में लगाया गया। मारीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड तथा यूके भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोत बने रहे।

2.179 2007-08 के दौरान एफआईआई द्वारा सकल अंतर्वाह और सकल बहिर्वाह क्रमशः 226.6 बिलियन अमरीकी डॉलर और 206.3 बिलियन अमरीकी डॉलर पर उच्चतर थे जिसके फलस्वरूप 20.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (2006-07 में 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर) का निवल अंतर्वाह हुआ। वर्ष 2007-08 के आरंभ में एफआईआई ने बड़े पैमाने पर भारतीय स्टॉक बाजार में निवल निवेश किया, जो सुदृढ़ देशी आर्थिक कार्यकलाप तथा भारतीय रुपए की वृद्धिकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है (सारणी 2.53 तथा चार्ट II.25)। जून-जुलाई 2007 के दौरान, एफआईआई के निवल अंतर्वाहों में मुख्यतः दो बड़े आईपीओ तथा वैश्विक बाजारों में उपलब्ध अतिरिक्त चलनिधि के कारण वृद्धि हुई। तथापि अगस्त 2007 में पार्टिसिपेटरी नोट संबंधी एफआईआई मानदंडों को सख्त बनाने, भारत सहित एशियाई स्टॉक बाजारों में मंदडिया स्थिति, तथा आवास बाजार में और कमजोरी की चिंताओं

सारणी 2.52 : श्रेणी के अनुसार विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4
अ. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	8,961	22,079	32,435
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ)	5,975	16,482	25,241
क. सरकार (एसआईए/एफआईपीबी)	1,126	2,156	2,298
ख. भा.रि.बैं.	2,233	7,151	17,129
ग. शेयर अभिग्रहण *	2,181	6,278	5,148
घ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी #	435	897	666
II. पुनर्निवेशित आय **	2,760	5,091	6,884
III. अन्य पूंजी ***	226	506	310
आ. संविभाग निवेश (क+ख+ग)	12,492	7,003	29,395
क. जीडीआर/एडीआर	2,552	3,776	8,769
ख. एफआईआई @	9,926	3,225	20,328
ग. अपतटीय निधि और अन्य	14	2	298
ग. कुल (अ+आ)	21,453	29,082	61,830

अ : अनंतिम.
 * : अनिवासियों द्वारा फेमा, 1999 की धारा 6 के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों के अभिग्रहण से संबंधित है।
 # : अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी के 2006-07 तथा 2007-08 के आंकड़े अनुमानित हैं।
 ** : पिछले दो वर्षों के औसत के आधार पर 2006-07 और 2007-08 के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है।
 *** : आंकड़ों में एफडीआई संस्थाओं के अंतर कंपनी ऋण लेनदेन शामिल हैं।
 @ : आंकड़े वित्तीय एफआईआई द्वारा निधियों का निवल अंतर्वाह दर्शाते हैं।
टिप्पणी : इस सारणी में प्रस्तुत विदेशी निवेश के आंकड़े देश में अंतर्वाह को दर्शाते हैं और हो सकता है अन्य सारणियों में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल न खाएं। निवल एफआईआई अंतर्वाह भी एफआईआई द्वार शेयर बाजार में निवल निवेश से संबंधित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

के कारण अमरीकी स्टॉक बाजारों में बड़े पैमाने पर बिकवाली से संबंधी चिंताओं के कारण भारी मात्रा में निवल बहिर्वाह हुआ। इसके बाद, सितंबर 2007 में अंतर्वाहों में रिकार्ड वृद्धि हुई, जो मोटे तौर पर जनवरी 2008 तक बना रहा। जनवरी 2008 के दौरान, मुख्यतः दो बड़े निर्गमों में अभिदान के कारण एफआईआई द्वारा 6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ। तथापि मुख्यतः आईपीओ में अभिदान के लिए जनवरी 2008 में धन की वापसी किए जाने के कारण फरवरी 2008 में 9.0 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल बहिर्वाह देखा गया।

2.180 बहिर्वाह मार्च 2008 से जुलाई 2008 तक जारी रहा, जिसका कारण यूएस सब-प्राइम संकट से उत्पन्न अस्थिर वैश्विक ऋण बाजार स्थितियों का बने रहना था। सेबी के पास पंजीकृत एफआईआई की संख्या मार्च 2007 के अंत के 997 से बढ़कर 31 मार्च 2008 तक 1,319 तथा 31 जुलाई 2008 तक और बढ़कर 1,457 हो गई। विदेश

सारणी 2.53: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह/बहिर्वाह

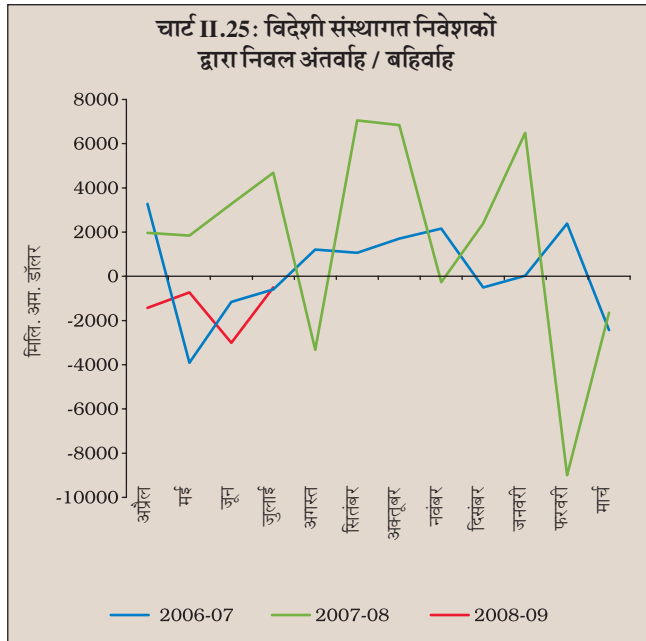
(मिलियन अमरीकी डॉलर)

माह	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
अप्रैल	3,276	1,963	-1,432
मई	-3,906	1,847	-734
जून	-1,157	3,279	-3,011
जुलाई	-595	4,685	-499
अगस्त	1,212	-3,323	
सितंबर	1,064	7,057	
अक्टूबर	1,703	6,833	
नवंबर	2,159	-265	
दिसंबर	-507	2,396	
जनवरी	24	6,490	
फरवरी	2,385	-8,991	
मार्च	-2,433	-1,643	

में अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) द्वारा पूंजी का अंतर्वाह 2007-08 के दौरान 8.8 बिलियन अमरीकी डालर था (देखें सारणी 2.52)।

2.181 वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के तहत अंतर्वाह (निवल) पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 16.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 22.2 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्चतर था।

2.182 2007-08 के दौरान अनिवासी भारतीय जमाराशियों के तहत 179 मिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 के दौरान अधिकतम ब्याज दरों में



सारणी 2.54: एनआरआइ जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत अंतर्वाह

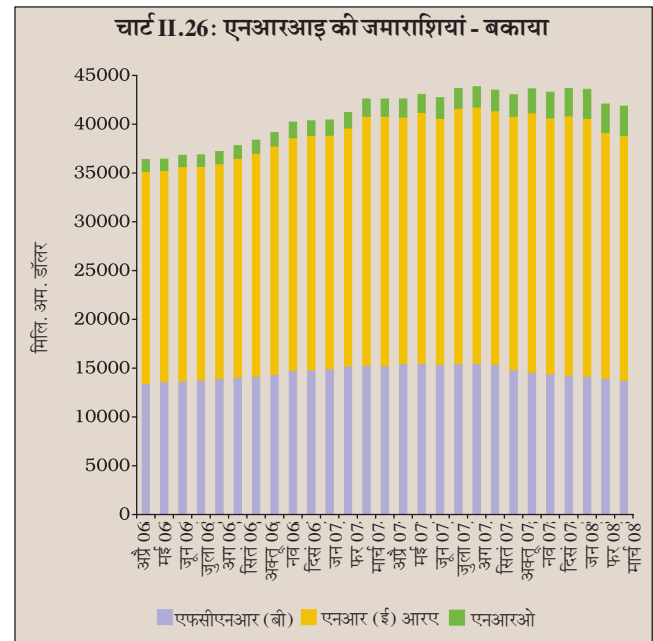
(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1. एफसीएनआर (बी)	1,612	2,065	-960
2. एनआर(ई)आरए	1,177	1,830	109
3. एनआरओ	930	426	1,030
कुल	3,719	4,321	179

अधोमुखी संशोधन तथा अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) जमाराशियों से बड़े स्थानीय आहरण के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि एनआर(ई) आरए जमाराशियों तथा अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाता खंडों के तहत अंतर्वाह हुए (सारणी 2.54 तथा चार्ट II.26)।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

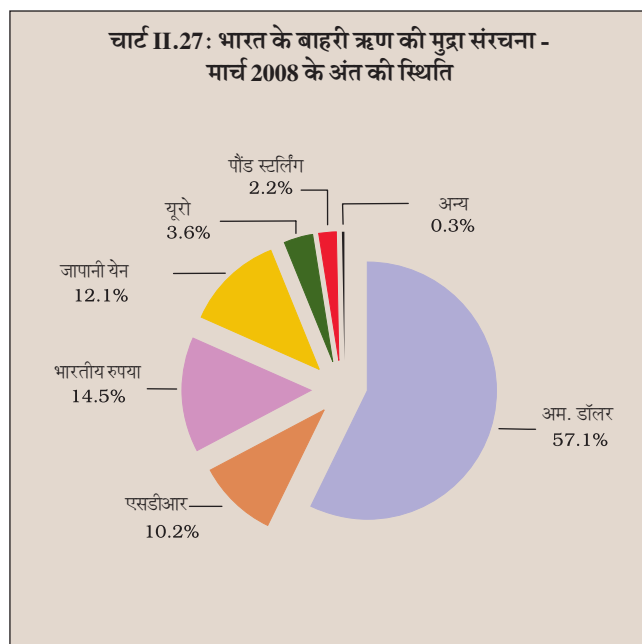
2.183 2007-08 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, पूंजीगत अंतर्वाह चालू खाता घाटा की तुलना में काफी अधिक थे, जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में मार्च 2007 के अंत की तुलना में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर (मूल्यन सहित) की वृद्धि को दर्शाता है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां, जिनमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) तथा आइएमएफ में आरक्षित श्रृंखला स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं, 15 अगस्त 2008 को 296.2 बिलियन अमरीकी डालर (पिछले साल की तदनु रूप अवधि में 226.4 बिलियन अमरीकी डालर) तक पहुंच गईं। मार्च 2008 के अंत में भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच आरक्षित निधियों के स्टॉक का तीसरा सबसे बड़ा धारक तथा विश्व में चौथा सबसे बड़ा धारक था।



भारत का बाह्य ऋण

2.184 मार्च 2008 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण 221.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 51.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (30.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। अवधि के दौरान बाह्य ऋण में हुई वृद्धि का मुख्य कारण उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा उच्चतर अल्पावधि व्यापार ऋण था। भारतीय कंपनियों द्वारा उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधार ने देशी और अंतरराष्ट्रीय दरों तथा हितकर विनिमय दर संबंधी प्रत्याशाओं के बीच मौजूद ब्याज संबंधी अंतर को दर्शाया। इसके अलावा, वर्ष 2007-08 के दौरान बाह्य ऋण में 51.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि में से, अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं तथा भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्यहास को दर्शानेवाला मूल्यन प्रभाव 9.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 180 दिनों की परिपक्वता तक के आपूर्तिकर्ता ऋणों तथा अल्पावधि ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को मार्च 2005 से भारत के अल्पावधि ऋण में शामिल किया गया है। बकाया अल्पावधि ऋण मार्च 2007 के अंत के 26.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 44.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो बाह्य ऋण में कुल वृद्धि का 34.8 प्रतिशत था (सारणी 2.55)। अमरीकी डॉलर अग्रणी मुद्रा बना रहा, जिसमें भारत के बाह्य ऋण को मूल्यवर्गित किया गया, जो कुल ऋण का लगभग 57.1 प्रतिशत था (चार्ट II.27)।

2.185 2007-08 के दौरान ऋण की धारणीयता के संकेतक सुखद स्तरों पर रहे। जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2007 के अंत के 17.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 18.8 प्रतिशत हो गया। मार्च 1995 के अंत में यह अनुपात 30.8 प्रतिशत था। ऋण चुकौती



अनुपात 2006-07 के 4.8 प्रतिशत तथा 2005-06 के 9.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 5.4 प्रतिशत रखा गया। 2007-08 के दौरान अल्पावधि ऋण में हुई वृद्धि को दर्शाते हुए, कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण तथा आरक्षित निधियों के प्रति अल्पावधि ऋण का अनुपात बढ़कर क्रमशः 20.0 प्रतिशत तथा 14.3 प्रतिशत हो गया। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां बाह्य ऋण की तुलना में 88.5 बिलियन अमरीकी डॉलर अधिक थीं तथा उन्होंने मार्च 2008 के अंत में बाह्य ऋण स्टॉक को 140.0 प्रतिशत का कवर प्रदान किया (सारणी 2.55)।

सारणी 2.55: भारत का बाह्य ऋण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	मार्च 1995 के अंत में	मार्च 2005 के अंत में	मार्च 2006 के अंत में	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में
1	2	3	4	5	6
1. बहुपक्षीय	28,542	31,744	32,620	35,337	39,312
2. द्विपक्षीय	20,270	17,034	15,761	16,061	19,613
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	4,300	0	0	0	0
4. व्यापार ऋण (1 वर्ष से अधिक)	6,629	5,022	5,420	7,051	10,267
5. बाह्य वाणिज्यिक उधार	12,991	26,405	26,452	41,657	62,019
6. एनआरआई जमाराशि	12,383	32,743	36,282	41,240	43,672
7. रुपया ऋण	9,624	2,302	2,059	1,947	2,016
8. दीर्घावधि (1 से 7)	94,739	115,250	118,594	143,293	176,899
9. अल्पावधि	4,269	17,723	19,539	26,376	44,313
कुल (8+9)	99,008	1,32,973	1,38,133	1,69,669	2,21,212
कुल ऋण/जीडीपी	30.8	18.6	17.2	17.8	18.8
अल्पावधि/कुल ऋण	4.3	13.3	14.1	15.5	20.0
अल्पावधि ऋण/आरक्षित निधियां	16.9	12.5	12.9	13.2	14.3
रियायती ऋण/कुल ऋण	45.3	30.9	28.6	23.3	19.9
आरक्षित निधियां/कुल ऋण	25.4	106.4	109.8	117.4	140.0
ऋण चुकौती अनुपात	25.9	6.1	9.9	4.8	5.4

VIII. समग्र मूल्यांकन

2.186 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही, यद्यपि पिछले साल की तुलना में कुछ कमी आई। आइएमडी द्वारा वर्षा के पूर्वानुमान की तुलना में दक्षिण-पश्चिम मानसून का कार्य-निष्पादन बेहतर था। इस मंत्रालय द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के दौरान कुल खाद्य उत्पादन रिकार्ड ऊंचाई पर होने का अनुमान था। मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में कमी के कारण 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि कम हो गई। तथापि, पूंजीगत माल क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि दिखनी जारी रही। 2007-08 के दौरान सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि बनी रही। सीएसओ द्वारा लगाए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि दर बनी रहेगी, हालांकि समग्र वृद्धि 2006-07 की तुलना में थोड़ी कम होगी। सीएसओ के संशोधित अनुमानों में 2007-08 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 9.0 प्रतिशत पर रखा गया।

2.187 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के संशोधित अनुमानों के तहत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा बजट अनुमानों की तुलना में निम्नतर रखा गया। ऐसा राजस्व प्राप्तियों, विशेष तौर पर प्रत्यक्ष करों, में उछाल द्वारा संभव होगा जिसकी मात्रा ब्याज भुगतान तथा सब्सिडी के लिए उच्चतर प्रावधानों के कारण व्यय में हुई वृद्धि को प्रतिलुलित करने से अधिक थी। 2008-09 के बजट अनुमानों में एक ओर कर प्राप्तियों में उछाल तथा दूसरी ओर बेहतर व्यय प्रबंधन के आधार पर सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में और कटौती की गई। यद्यपि 2008-09 तक जीडीपी के 3.0 प्रतिशत पर जीएफडी प्राप्त करने का एफआरबीएम लक्ष्य प्राप्त किया जाना था, 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करने के लक्ष्य को काफी राजस्व व्यय वाले योजना कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के कारण पुनर्निर्धारित करना पड़ा। तेल बांडों से बजट बाह्य दबाव, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में छठे वेतन संशोधन, उर्वरक सब्सिडी तथा अल्पावधि में योजनेतर व्ययों को नियंत्रित करने में प्रणालीगत जटिलता 2008-09 में केंद्र सरकार के वित्त पर कुछ दबाव डाल सकती है।

2.188 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2007-08 के पहले आठ महीनों में मोटे तौर पर कम रही तथा दिसंबर 2007 के बाद प्राथमिक खाद्येतर वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण उसमें तेजी आई। साल-दर-साल आधार पर मार्च 2008 के अंत में मुद्रास्फीति 7.7 प्रतिशत थी। तथापि, औसत वार्षिक आधार पर, 2007-08 के दौरान 4.7 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति पिछले साल की तुलना में कम थी। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण जनवरी 2008 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति कम हुई। तथापि, बाद में सीपीआई मुद्रास्फीति अनाज, ईंधन तथा सेवाओं

(विविध समूहों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई मदों) के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ गई। आंशिक रूप से वैश्विक गतिविधियों के कारण हाल के महीनों में मुद्रास्फीति पर अप्रत्याशित आपूर्ति पक्ष के दबावों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने कई उपाय किए, यथा गेहूं और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती, गैर बासमती चावल, खाद्य तेल और दालों के निर्यात पर पाबंदी, बासमती चावल से संबंधित न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि, चावल, स्किम्ड मिल्क पावडर, खाद्य तेल, बटर ऑइल तथा मक्के पर सीमा शुल्क में कटौती। अन्य प्रशासनिक उपाय भी शुरू किए गए, यथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए चुनिंदा कृषि उत्पादों पर स्टॉक सीमा लगाना। मार्च 2008 के अंत तथा 29 जुलाई 2008 के बीच, रिजर्व बैंक ने सीआरआर में 150 आधार अंकों (30 अगस्त 2008 से लागू 25 आधार अंकों सहित) तथा रिपो दर में 125 आधार अंकों की वृद्धि जैसे मौद्रिक उपायों की घोषणा भी की। सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन तथा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों संबंधी हाल की पहलों से आशा है कि निकट भविष्य में मुद्रास्फीति पर मंदकारी प्रभाव पड़ेगा।

2.189 2007-08 के दौरान वित्तीय बाजार की स्थितियां व्यवस्थित बनी रहीं, इक्विटी बाजार को छोड़कर जिसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप अस्थिरता के दौर देखे गए। रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के पूंजी प्रवाहों तथा नकदी शेष में परिवर्तन के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता के संक्षिप्त दौर देखे गए। मुद्रा बाजार की ब्याज दरें वर्ष की दूसरी छमाही के अधिकांश भाग में रिवर्स रिपो तथा रिपो दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर बनी रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रूप में आम तौर पर वर्ष के दौरान दुतरफा गतिविधियां दिखाई दीं। वर्ष के अधिकांश भाग में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिफलों में नरमी रही।

2.190 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के समर्थन से 2006-07 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों में अच्छी गति से विस्तार बना रहा। वर्ष के दौरान अच्छी ऋण वृद्धि के साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार भी आया। बैंकिंग की लाभप्रदता में सुधार हुआ तथा वे पिछले वर्ष के स्तर पर सीआरएआर बनाए रखने में समर्थ रहे।

2.191 2007-08 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मुख्यतः उच्चतर निजी विप्रेषणों तथा सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात की अगुवाई में अदृश्य खातों में अधिशेष बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा नियंत्रित रखा गया। 2007-08 के दौरान निवल पूंजी अंतर्वाह 2006-07 के 45.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर पर अधिक बना रहा। वर्ष के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई

और वह मार्च 2008 के अंत तक 309.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई।

2.192 अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण 2008 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप मंद होने का अनुमान है। इसके अलावा, ऐसी आशंका है कि वित्तीय उथल-पुथल का असर वास्तविक क्षेत्र तक फैल जाएगा जिसका रोजगार और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2007-08 में सुदृढ़ मांग और घटते हुए स्टॉक से प्रेरित होकर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वैश्विक स्थिरता के लिए प्रमुख जोखिम बन गई। कच्चे तेल की कम उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के साथ कई तेल निर्यातक देशों में आपूर्ति की चिंताओं के कारण विश्व में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं। 2007-08 के दौरान परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं तथा ईएमई दोनों में मुद्रास्फीतिकारी दबाव दिखाई दे रहे थे, यद्यपि ईएमई में यह अधिक मुखर था। कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारी दबाव में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई।

2.193 2008-09 के लिए रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) में यह नोट किया गया कि 2007-08 के दौरान वैश्विक तथा देशी दोनों गतिविधियों में आरंभिक आकलनों की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव देखे गए। वक्तव्य के अनुसार वैश्विक मंदी के खतरे बढ़ रहे थे यद्यपि इस बात पर सहमति थी कि सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तविक नीति वक्तव्य में यह भी नोट किया गया कि अभूतपूर्व जटिलताओं तथा अत्यधिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिन्होंने 2008-09 के लिए मौद्रिक नीति के रुख के निर्धारण को नियंत्रित किया। पहला, अनाज और ऊर्जा के बढ़े हुए और अस्थिर मूल्य, जिनमें संभवतः कुछ संरचनागत घटक हैं, तात्कालिक चुनौती है। तथापि यह मानना आवश्यक है कि उनके विकास में कुछ चक्रीय घटक भी हैं। दूसरा, जहां मांग के दबाव बने हुए हैं, वहीं समर्थक नीतिगत माहौल से अतिरिक्त क्षमताओं के निर्माण के साथ देशी आपूर्ति संबंधी प्रतिसाद में कुछ सुधार हुआ है। तदनुसार, निवेश मांग सुदृढ़ बने रहने पर भी, आपूर्ति संबंधी लचीलेपन में और सुधार हो सकता है तथा आनेवाले महीनों में नयी क्षमताएं आ सकती हैं। तीसरा, सितंबर 2004 से की जा रही सोची समझी मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों का अर्थव्यवस्था पर कुछ स्थिरकारी प्रभाव बना रहेगा। साथ ही, भारत सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन के संबंध में किए गए हाल के पहल तथा रिजर्व बैंक द्वारा नकदी आरक्षित अनुपात के संबंध में किए गए उपाय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में हैं, यद्यपि मुद्रास्फीति की संभावना उस

समय फसल की संभावनाओं के अधिक विश्वसनीय आकलन पर निर्भर होगी। चौथा, मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों गतिविधियों संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, प्रत्याशाओं के प्रबंधन के लिए नीतिगत प्रतिसादों में वैश्विक उत्पादन वृद्धि की मंदी के चारों ओर घिरी वैश्विक एवं देशी अनिश्चितताओं तथा साथ ही भारत के संदर्भ में अतिरंजित मंदी की संभाव्यता पर विचार किया जाना चाहिए। पांचवां, जहां मौद्रिक नीति को तात्कालिक चिंताओं के प्रति सक्रिय रूप से रेस्पांड करना चाहिए, इसमें समग्र समष्टि आर्थिक संभावनाओं के संबंध में अपेक्षाकृत दीर्घतर परिप्रेक्ष्य, यथा एक से दो साल तक, में किए जानेवाले सोच-विचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही मौजूदा स्थिति में मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं के संबंध में प्रतिकूल गतिविधियों के किसी संकेत को नियंत्रित करने के लिए निर्णायक रूप से, कारगर रूप से और तुरंत निरंतर आधार पर कार्रवाई करने के निश्चय को दर्शाना महत्वपूर्ण है। उक्त अभूतपूर्व अनिश्चितताओं और द्विविधाओं को देखते हुए, नीतिगत कार्रवाइयों के समय और परिमाण के संबंध में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है; तथा यह जरूरी है कि ऐसे निर्णय में निरंतर आधार पर आनेवाली जानकारी के मूल्यांकन का लाभ निहित हो।

2.194 अप्रैल 2008 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने 2008-09 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.0 से 8.5 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान लगाया, जिसे जुलाई 2008 के मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा संबंधी वक्तव्य में 8.0 प्रतिशत के आसपास रखा गया। इस पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किन्हीं प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के उदय को छोड़कर तथा वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए संभावना सहित अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकलन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में मौद्रिक नीति के समग्र रुख का मोटे तौर पर निम्नानुसार उल्लेख किया गया: (i) ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जिसमें मूल्य स्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजार में व्यवस्थित स्थितियों को, वृद्धि की गति जारी रखने में सहायक होने के साथ, उच्च प्राथमिकता दी जाए; (ii) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों तथा देशी स्थितियों के विकसित हो रहे समूह के प्रति उपयुक्त परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों तरह के उपायों से निरंतर आधार पर तुरंत रेस्पांड करना; तथा (iii) वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए रोजगार प्रधान क्षेत्रों के लिए ऋण की गुणवत्ता तथा ऋण की सुपुर्दगी पर विशेष रूप से बल देना।